हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

13 नवम्बर, 1973

खण्ड–2 अंक 2

अधिकृत विवरण

विषय–सूची

मंगलवार, 13 नवम्बर, 1973

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उतर	(2) 1
तारांकित प्रश्न संख्या 513 के सम्बन्ध में अध्यक्ष द्वारा	(2) 23

निरुपण	
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	(2) 23
कार्य–मंत्रणा समिति का प्रथम प्रतिवेदन	(2) 25
अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) 1973–74 (1) राज्य के राजस्वो पर प्रभभृत व्यय के अनुमानो पर चर्चा (2) अनुपूरक अनुदानो की मांगो पर चर्चा तथा मतदान	 (2) 25 (2) 25
बैठक के समय में वृद्धि	(2) 67
बहिर्गमन	(2) 67
अनुपूरक अनुदानो की मांगो पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(2) 67
बहिर्गमन	(2) 74
अनुपूरक अनुदानो की मांगो पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(2) 76

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 13 नवम्बर, 1973

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9:30 बजे हुई। अध्यक्ष

(श्री बनारसी दास गुप्त) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उतर

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण प्रश्नोत्तर काल।

Gunny Bags

***442. Chaudhri Mehar Chand:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state-

(a) the total number of gunny bags purchased by the Marketing Federation, Haryana, in Connection with the procurement of wheat in Rabi, 1973. and

(b) the total number of bags actually used for procurement of wheat in 1973, by the Marketing Federation?

Agriculture Minister (Ch. Bhajan Lal):

(a) 31,92,300 gunny bags

(b) 15,80000 gunny bags

चौधरी मेहर चन्दः क्या वजीर साहब बताएगें कि 32 लाख के करीब बैग क्यों खरीदे गए जबकि एक्च्युअली 16 लाख की कंजम्पशन होनी थी ?

चौधरी भजन लालः इसके बारे में ऐसी पोजीशन है कि शुरु में जो हम ने गेंहू खरीदने का टारगैट फिक्स किया था वह 13 लाख टन गेंहू का था तो उसके हिसाब से हमने बारदाने का इंतजाम किया था लेकिन बाद में प्रोक्योरमैंट कम हुई। वैसे तो बारदाने की जिम्मेवारी स्टेट्स की होती है मगर वह सारा डायरैक्टर जनरल सप्लाईज़ एंड डिस्पोजल्स भारत सरकार ही खरीद करता है तो हमने उनको 40 लाख गिनी बैग्ज का आर्डर किया था लेकिन उन्होने हमें 31,92,300 बोरियां सप्लाई की जिनका रेट 303 रुपए से लेकर 332.15 रुपए के हिसाब से हमें देना पडा जबकि इस वक्त बैग्ज का रेट 380 रुपए का हो गया है। इस में हमें इस वक्त 8/9 लाख रुपए का प्रोफिट रहेगा।

चौधरी दल सिंहः क्या वजीर साहब बताएंगे कि उन बोरियों का साईज़ क्या था और उनका वजर कितना था ?

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहिब जो बारदाना बैस्ट होता है वही परचेज किया जाता है। यह बारदाना काली डोरी का होता है और हर बोरी का वनज सवा दो पाउंड होता है और इस से बढिया बारदाना काई नही होता।

चौधरी शिव राम वर्माः क्या वजीर साहब बताएंगे कि सरकार के अन्दाजे में और असली पैदावार में इतना अन्तर क्यों रहा?

श्री अध्यक्षः वैसे आप जवाब देना चाहें तो दे दें लेकिन यह प्रश्न उत्पन्न नही होता।

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल): स्पीकर साहब चौधरी शिव राम वर्मा ने खुद ही उस वक्त अपनी स्पीच में कहा था कि यह टारगैट जो सरकार ने माना है इतनी पैदावार नही है।

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब खडी फसल का अन्दाजा हमारा बहुत अच्छा था। पिछले साल से पिछले साल हमारी 24 लाख टन के करीब पैदावार थी। लेकिन चूंकि इस दफा सोइंग ज्यादा थी इसलिए हमने अन्दाजा लगाया कि 26 लाख टन के करीब गेहू पैदा होगा। लेकिन फसल पकने से पहले कुछ गर्म हवा चली जिस से गेंहू की पैदावार में फर्क पड गया और कम हुई।

मलिक सतराम दास बतराः क्या वजीर साहब बताएंगें कि बारदाना खरीदते वक्त कौन–कौन सी कोटेशन ली गई थी ?

चौधरी भजन लालः यह तो गर्वमेंन्ट आफॅ इन्डिया परचेज़ करके देती है। गवर्नमैंट आफ इन्डिया का डायरैक्अर जनरल सप्लाईज होता है और उनका इस के अलावा बाकायदा एक बोर्ड बना हुआ होता है, तो सारी परचेज उनके थ्रूरु की गई थी। इस के अलावा जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं जिस वक्त हम ने परचेज़ की थी उस वक्त रेट मंदा था लेकिन बाद में रेट ज्यादा हो गया है जिस से गवर्नमैंट को 8/9 लाख रुपए का फायदा हो गया है।

चौधरी मेहर चन्दः क्या वजीर साहब बताएगें कि फतेहाबाद मार्किटिंग सोसाईटी में कितनी बोरियां भेजी गई थी और एक्चुअली वहां कितनी बोरियां इस्तेमाल हुई और उन बोरियों की इस वक्त मौजूदा कण्डीशन क्या है ?

चौधरी भजन लालः सोसाईटी–वाईज़ तो डिटेल मेरे पास नही है, अगर आप ज़िलावार पूछें तो मैं बता सकता हूं।

चौधरी राम लाल वघवाः क्या वजीर साहब बताएंगे कि जो बारदाना बाकी बच गया है और जब उस की कीमत बढ गई है तो उस को क्या गवर्नमैंट ने फरोख्त कर दिया है या वह अभी रखा हुआ है ?

चौधरी भजल लालः उस को फरोख्त करने जा रहे हैं।

चौधरी फूल चन्द (रोहट): क्या वजीर साहब बताएंगे कि जो प्रोक्योरमैंट हुई है उस में से कितना स्टोक आप ने सैंटर को दिया है और कितना स्टेट के पास है और जो पास है वह क्या हमारी जरुरत के लिए काफी है ?

श्री अध्यक्षः यह प्रश्न एराईज़ नही होता।

Debt Against the Haryana Government

***453. Chaudhri Dal Singh:** Will the Minister for Finance be pleased to state-

a) the total amount of debt outstanding against the Haryana Government as on 13.03.1973; and

b) the total amount paid as interest on debt by the Government during the financial years 1970-71, 1971-72 and 1972-73, separately?

Finance Minister (Shri Ram Saran Chand Mital):

a) The requisite information will be available in the Finance Accounts 1972-73, which are presently under compilation with the Accountant General, Haryana. Finance Accounts, 1972-73 will be laid on the Table of the House in due course. However, from the information available from our records which may undergo marginal changes in the Finance Accounts, the outstanding liability on 31.03.1973 amounted to Rs. 267.79 crores.

b) The figures of interest paid as per our records are as follows:-

1970-71	Rs. 8.80 crores
1971-72	Rs. 9.74 crores
1972-73	Rs. 11.41 crores

These figures are subject to marginal changes on compilation of the Finance Accounts as already stated.

चौधरी दल सिंहः क्या वित्त मंत्री महोदय बताएंगे कि सन् 1972.73 में सरकार ने कितना कर्जा वापिस किया ?

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल): वह तो हर साल के बजट में लिखा हुआ होता है। जो स्अेटमैंट आफ अकाउंटस होता है वह सारा

बजट में आता है और वह डाक्युमैंट हर मैंबर को अवेलेबल है। That document is available to every Hon. Member.

चौधरी राम लाल वधवा: क्या वजीर खजाना बताने की कृपा करेंगे कि यह कर्जे कहां–कहां से लिए गए और कब वापिस करने है ?

श्री अध्यक्ष: वह तो जैसे मुख्य मंत्री साहब ने बताया है पबलिशड डाक्युमैंट है, वह आप को मिल सकता है और वहां से सारी इन्फरमेशन आप को मिल सकती है।

श्री राम सरन चन्द मित्तल: जो फाईनैंस अकाउंटस होते है बस में हर चीज होती है, कितना कर्ज लिया गया, कितना प्रिंसिपल अमाऊंट है, कितना इंनटैस्ट दिया गया यह सब डिटेलृज़ आप को मिल सकती है।

चौधरी दल सिंह: वजीर साहब ने सवाल के जवाब में बताया है कि 1970.71 में 8.80 करोड इन्ट्रैस्ट, 1971–72 में 9.47 और 1972–73 में 11.41 करोड इन्ट्रैस्ट दिया। पिछली बार इन्होने बताया था कि 276 करोड कर्जा है और आज सवाल के जवाब में बताया है कि 267.79 करोड की लायबिलिटी है। लेकिन जो रकम सद की दी गई है उससे पता चलता है कि कर्जा बढाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: वह तो आप पबलिश्ड डाक्युमैंट से देख सकते है।

Amounts Given to Students belonging to Scheduled Castes and Backward Community.

***482. Shri Girish Chander Joshi:** Will the Minister for Development be pleased to state the total amount of stipends given to the students belonging to Scheduled Castes and Backward Community from 1st April 1972 to 31st March 1973?

Development Minister (Shri Shyam Chand): Rs. 45,55,607.00

श्री गिरीश चन्द्र जोशीः यह जो 45,55,607.00 रुपए की रकम बताई गई है इस में से शैड्यूलड कास्टस और बैकवर्ड कलासिज़ को कितनी दी गई है ?

Shri Shyam Chand: Rs 4.91 Lakhs to Backward Classes and the rest to Scheduled Castes.

श्री गिरीश चन्द्र जोशीः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि शैड्यूलड कास्टस के कितने लडके थे और बैकवर्ड क्लासिज के कितने लडके थे ?

Shri Shyam Chand: About which category the hon. Member wants information, pre-matric or post-matric?

चौधरी दल सिंहः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जो उन्होने शड्यूलड कास्टस के लडको को कर्जे दिए है, हमारे जींद के जिला में कितने शैडयूलड कास्टस के लडको को ऐसा कर्जा दिया गया है ?

श्री श्याम चन्दः कर्जे तो नही दिए, स्कौलरशिप दिए है। डिस्ट्रिक्ट–वाईज इन्फर्मेशन बेसिक क्वेश्चन में मांगी नही गई थी।

इसलिए इस का जवाब देने के लिए सैप्रैट नोटिस दें तो जवाब दे दिया जाएगा।

चौधरी राम लाल वधवा: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि कितने स्ऊडैंट्स को स्कालरशिप दिया गया ?

Shri Shyam Chand: College stage-3812 and School stage-29405

श्री अमर सिंह: क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि 1 अक्तुबर 1972 से 31 मार्च, 1973 तक डिस्ट्रिक्ट हिसार में बैकवर्ड क्लासिज तथा शैड्यूल्ड कास्ट्स के कितने–कितने लडको को स्कौलरशिप दिया गया ?

श्री अध्यक्ष: इन्होने पहले ही कह दिया कि डिस्ट्रिक्ट–वाईज इन्फमेंशन मेरे पास नही है।

चौधरी राम लाल वधवा: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि स्कालरशिप देने का क्या काइटिरिया सरकार ने मुकर्रर कर रखा है ?

श्री श्याम चन्द: जो लडके स्कूल और कालेज में एडमिट होते है उन को दिया जाता है।

Licences From the Central Government

***491. Shri Gauri Shankar:** Will the Minister for Industries be pleased to state-

a) whether th Government has secured any licences from the Central overnment to start any new Industries in the State; if so, the details thereof; and

b) the number of persons who are likely to get employment by the setting up of these industries?

Industries Minister (Shri Harpal Singh): (a) & (b) The Government has not secured and licence from the Government of India. The Haryana State Industrial Development Corporation has secured licences/Letters of Intent from Government of India. Details are given in the statement which is laid on the Table of the Vidhan Sabha.

STATEMENT

Sr.	Name of the Project	Capacity	Letter of Intent and Licence	Employment
1	Brewery	50,000 Heco Liters	Letter of Intent and Licence.	332
2	Tannery	Upper Leather (420000 Nos. of sheep skins) (Lining 180000 Nos. of sheep skins)	Letter of Intent only.	193
3	Steel Billets	50000 Tons	-do-	453
4	Walkie Talkie	10000 Nos.	-do-	251

5	Television	5000 Nos.	-do-	410
6	Sponge Iron	One lakh tons	-do-	366
7	Nylon	2100 tons	-do-	605
8	Synthetic detergent	10000 tons	-do-	87
9	Cigarette & other allied tissue paper	2000 tons	-do-	280
10	Cigarette Project	4500 million pieces	-do-	875
11	Glass Bottle	18000 tons	-do-	515
12	Rice Husk Particle Board and its Products	1500 tons	-do-	65

मलिक सतराम दास बतराः जो इंडस्ट्रीज़ वगैरा लगाई जाती है उन के लिए रा–मैटीरियल खरीदने के लिए पैसा रखा होता है और

रा–मैटीरियल खरीदने में काफी देर लगती है। क्या सरकार इसमें सुधार करने के लिए कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री हरपाल सिंहः रा–मैटीरियल खरीदने के मामले को सैन्ट्रल गवर्नमैंट में इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट वाले डील करते है और हम यहां से रिकमैंड करके भेज देते है।

चौधरी राम लाल वधवाः क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो लाइसेंस इशू हुए हैं, क्या वे सिर्फ सैक्टर में लगा रहे हैं या प्राईवेट में भी लगा रहे है ?

श्री हरपाल सिंहः हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रीयल डिवैल्पमैंट कारपोरेशन ने जो लाईसैंस प्राप्त किए हैं उन में से एक प्रोजैक्ट है जो पब्लिक सैक्टर में लगा रहे हैं और बाकी ज्वायंट सैक्टर में है।

श्री अमर सिंहः क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो लाईसैंस मिले है उनकी डिस्ट्रिक्ट–वाईज़ कितनी कितनी–ब्रेक–अप है ?

श्री हरपाल सिंहः इसमें डिस्ट्रिक्ट–वाईज़ ब्रेक–अप का सवाल नही है। जो साईट ठिक समझी जाती है उसको प्रपोज़ किया जाता है कि यहां पर इंडस्ट्री लगाई जाए। वैसे जहां–जहां जो–जो इंडस्ट्री लगा रहे हैं वह इस प्रकार है:–

1.	ब्रीवरी–मुरथल
2.	टैनरी–जींद

3.	स्टील बिलिट्स–हिसार
4.	टेलिविज़न–गुड़गांव
5.	नाईलोन–भिवानी
6.	सिगरेट–अम्बाला
7.	राईस हस्क पार्टिकल बोर्ड एंड इट्स प्रोडक्ट्स–करनाल

चौधरी दल सिंहः क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जींद में टेनरी का कारखाना बन कर कब तक मुकम्मल हो जाएगा ?

श्री हरपाल सिंहः काम शुरु हो गया है, बाउंड्री वॉल बनानी शुरु कर दी है, टैक्नीकली जो एग्रीमैंट है वह हो चुका है सैनट्रल गवर्नमैंट के अप्रवूल की इंतजार है। अप्रूवल अपने के बाद काम शरु हो जाएगा।

श्री गौरी शंकरः जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया कि हिसार में स्अील बिलिट्स का कारखाना लगाना है। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इस पर कब तक काम शुरु हो जाएगा।

श्री हरपाल सिंहः इसके लिए लैंड अक्वायर हो चुकी है, जल्दी ही पोजैशन ले लेंगे और काम शूरु कर देंगे।

श्री औम प्रकाश गर्ग: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि कुरुक्षेत्र में कौन सा कारखाना लगायेंगे?

श्री हरपाल सिंह: कुरुक्षेत्र ज़िला अभी बना है, इसमें कारखाने लगाने शुरु करेंगे । (हंसी)

श्री अमर सिंह: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्री लगाने का जो सरकार ने फेसला किया है उस पर काम कब तक शुरु हो जाएगा और कब तक समाप्त हो जाएगा ?

श्री हरपाल सिंह: वहां पर नाईीन का प्रोजैक्ट लगना है। इसका एग्रीमैंट कोलैबोरेटर्ज से अभी हुआ है और यह ज्वायंट सैक्टर में लगायेंगे। इस पर काम जल्दी से जल्दी शुरु किया जाएगा लेकिन यह मालूम नही कि समय कितना लगेगा।

चौधरी फूल सिंह कटारिया: जैसा कि कुरुक्षेत्र के बारे में बताया है, कुरुक्षेत्र नया जिला है लेकिन रोहतक बहुत पुराना जिला है। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि उस में कितने कारखाने लगाने की तज़वीज है ?

श्री हरपाल सिंह: मैंने इस चीज को पहले सैशन में भी एक्सप्लेन किया था। ज्वायंट सैक्टर में कोलैबोरेटर अपनी मर्जी से फैक्टरी के लिए साईट सिलेक्ट करते हैं। अगर रोहतक में इंडस्ट्री लगाने के लिए कोई कोलैबोरेटर तैयार हो जाएगा तो हम तैयार है।

श्री दलीप सिंहः क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि महेन्द्रगढ जैसे बैकवर्ड डिस्ट्रिकट में कोई इंडस्ट्री लगाने की स्कीम है।

श्री हरपाल सिंहः वहां पर मारबल प्रोजैक्ट आलरेडी चल रहा है और स्पंज आईरन की फैक्टरी एस्अेबलिश करने जा रहें है।

चौधरी राम लाल वधवाः जो ज्वायंट सैक्टर में इंडस्ट्रीज़ लग रही है उनको लगाने के लिए हरियाणा प्रदेश कीकितनी पार्टीज है और हरियाणा से बाहर की कितनी है ?

श्री हरपाल सिंहः एक आध पार्टी ही बाहर की है जैसे स्अील बिलिट्स की फैक्टरी और बाकी सब हरियाणा प्रान्त की पार्टीज हैं।

Milk Centres

***501 Chaudhri Phool Chand (Mullana):** Will the Minister for Transport be pleased to state whether the Government have opened any new Milk Centres in the State since April, 1972; if so, the details thereof?

Transport Minister (Col. Maha Singh): Yes 324 Milk Centres have been opened in the State since April 1972 uptil 20-10-1973, the details of which are as under:-

Ambala	101
Kurukshetra	13
Karnal	35
Sonepat	14

Rohtak	11
Jind	15
Bhiwani	48
Hissar	25
Mohindergarh	62
Gurgaon	62

चौधरी मेहर चन्दः जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया कि 25 सैन्टर हिसार डिस्ट्रिक्ट में खोले है। क्या मंत्री महोदय कृप्या बताने की कृपा करेंगे कि फतेहाबाद सब–डिवीज़न में कितने सैंटर खोले गए है ?

कर्नल महा सिंहः फतेहाबाद में कोई सैन्टर नही खोला गया क्योंकि सिरसा में हमारा मिल्क प्लांट चल चुका है। जब हिसार में डेरी शुरु करेंगे तब फतेहाबाद में खोलेंगे।

चौधरी दल सिंहः जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया कि जींद में 15 मिल्क सैंटर खोले है। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि उन सैन्टरेा से कितना दूध प्राप्त होता है?

कर्नल महा सिंहः जींद में 15सैन्टर अब खुले है और पहले के भी खुले हुए है। आज कल जींद के सैंटरो से 8 हजार लिटर दुध आ रहा है।

श्री हरि सिंहः सम्भालखा बडा इर्प्पोटैंट टाउन है और जी. टी. रोड़ पर पडता है। इसके आस पास तकरीबन सब लोग दुध पैदा करते है। क्या सरकार वहां भी दुध का सैंटर खोलने की तज़वीज़ करेगी ?

कर्नल महा सिंहः उसके आस–पास मिल्क कुलैक्शन सैंटर खोले जा रहे हैं और बडी तेजी के साथ खोल रहे हैं।

मलिक सतराम दास बतराः क्या मंत्री महोदय बातयेंगे कि बहुत से प्लांट घाटे में जा रहे हैं ? अगर जा रहे हैं तो क्या सरकार ने उस घाटे को पूरा करने के लिए कोई उपाय किये हैं ?

कर्नल महा सिंहः सबसे पुराना मिल्क प्लांट जींद का है जो अब घाटे में नही चल रहा, जब नया–नया बना था तब जरुर घाटे में जाता था। अभी–अभी हमने भिवानी और अम्बाला में मिल्क प्लांट खोले है। इनकी बाबत अभी कुछ नही कहा जा सकता क्योंकिं भिवानी मिल्क प्लांट के स्वीट मिल्क की अभी तक हम पूरी खपत नही कर पाए हैं। अम्बाला का बिल्कुल नया है, इसकी बाबत कुछ दिनों के बाद बताया जा सकता है, अभी नही।

राव बंसी सिंहः क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि डिस्ट्रिक्ट गुडगांव और महेन्द्रगढ में सैपरेट–सैपरेट कितने सैंटर्ज़ खोले गए हैं ?

कर्नल महा सिंहः गुडगांव में मिल्क सैंटर्ज पहले से खुले हुए थे और अब भी खोले जा रहे है। अभी एक चिलिंग सैंटर हम रिवाडी में खोल रहे है और मिल्क सैंटर्ज़ भी खोलने शुरु कर दिए है। दूध जो

है उसे हमने बिलासपुर में जो गुडगांव का एक चिलिंग सैंटर है और रिवाडी के नजदीक है, लाना शुरु किया है। आगे चलकर हम सारा महेन्द्रगढ जिला ही नही बल्कि सब जिलों को इसी तरह कवर करेंगे।

श्री औम प्रकाश गर्गः क्या मिनिस्टर साहब बताने की कृपा करेंगे कि थानेसर सब–डिविजन में कितने मिल्क सैंटर्ज़ खोले गए है और कहां–कहां खोले गए हैं ?

कर्नल महा सिंहः मैंने जिले के फिगर्ज़ बता दिए हैं। सब–डिविज़न वाइज डाटा मैं अभी नही दे सकता। इसके लिए नोटिस चाहिए। वैसे कुरुक्षेत्र ज़िला में पेहवा में एक मिल्क प्लांट है और उसके आंकडे इसमें शामिल भी नही है।

चौधरी मेहर सिंहः क्या मिनिस्टर साहब फरमायेंगे कि उन्होने कभी सब–डिविज़न वाइज या तहसील वाइज़ सर्वे करवा करके देखा है कि मिल्क किस सब–डिविज़न में ज्यादा मिल सकता है और वहां सैंटर्ज़ खोलने जरुरी हैं या नही ?

कर्नल महा सिंहः सर्वे कुछ पहले कराया गया था लेकिन मुकम्मल नही हुआ है। उसे मुकम्मल कराया जाएगा और जहां ज्यादा दूध इकट्ठा हो सकेगा वहां ज्यादा से ज्यादा सैंटर्ज़ खोले जाएंगे।

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि जींद मिल्क प्लांट में घाटा नही है। क्या वे फरमा सकते है कि किस–किस साल में कितना फायदा है या कोई एक पीरियड ही बता दें जिसमें फायदा रहा हो ?

कर्नल महा सिंहः इसके लिए सैपरेट नोटिस चाहिए लेकिन इस वक्त की हालत मैं बता दूं कि जींद मिल्क प्लांट में घाटा अब नही है।

Pandit Jawahar Lal Nehru Project

***510. Chaudhri Phul Singh kataria:** Will the Chief Minister be pleased to state the time by which the Jawahar Lal Nehru Project is likely to be completed together with the total number of villages, which are likely to be benefited under this project?

State Minister for Irrigation & Power (Sardar Harmohinder Singh Chatha): Subject to the availability of material and funds, the project is likely to be completed in about three years after it is started. 800 villages are likely to be benefited from this Project.

राव दलीप सिंहः क्या मिनिस्टर साहब बतायेंगे कि इस प्रोजैक्ट पर काम कब तक शुरु होगा ?

सरदार हरमोंहिन्द्र सिंह चट्ठाः स्पीकर साहब इस प्रोजैक्ट पर काम शुरु हो चुका है। एक हिस्से पर यानी झज्जर लिफ्ट इरीगेशन स्कीम पर तो काम चल चुका है। पीछे उसका उद्घाटन भी हो गया था। जहां तक दुसरे हिस्से का सम्बन्ध है, उसकी कंसैट प्लानिंग कमीशन से मिल चुकी है लेकिन लीगल बात अभी आनी है। जिस दिन आएगी, उस दिन काम शुरु कर देंगे।

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल): स्पीकर साहब, मैं जरा इसे सप्लीमैंट कर दूं। लेटैस्ट अप्रैल के महीने में पूरे प्रोजैक्ट पर काम शुरु हो जाएगा।

चौधरी राम लाल वधवा: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि यह कब तक कम्पलीट हो जाएगा ?

सरदार हरमोंहिन्द्र सिंह चट्ठा: हमारा टारगैट तो तीन साल का है मगर दो साल में कम्पलीट करने की कोशिश करेंगे।

चौधरी बंसी लाल: जुलाई 1977 से पहले–पहले कम्पलीट हो जाएगा।

चौधरी दल सिंह: स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने अपने जवाब में 800 गांव फरमाये है। क्या वे बता सकेंगे कि वे किस–किस जिले के हैं?

सरदार हरमोंहिन्द्र सिंह चट्ठा: स्पीकर साहब, तहसील ब्रेक–अप इस प्रकार है:–

नारनौल	222
महेनद्रगढ	128
रिवाडी	376
झज्जर	59

दादरी	5

मलिक संतराम दास बतराः क्या मिनिस्टर साहब बताने कि कृपा करेंगे कि नेहरु नहर में कितने क्यूसिक पानी चलेगा और ब्यास रावी प्रोजैक्ट वाला पानी कब तक आ जाएगा ?

सरदार हरमोंहिन्द्र सिंह चटूठाः ब्यास रावी प्रोजैक्ट वाले पानी के मुतल्लिक तो अभी कुछ नही कह सकता क्योंकि बात चल रही है। अभी तक इसमें फुलडिड वाटर इस्तेमाल करेंगें। जब ब्यास रावी प्रोजैक्ट का पानी आएगा उस वक्त उसे भी इसमें यूटिलाइज किया जाएगा।

चौधरी चांद रामः क्या मिनिस्टर साहब दोनो रिप्लाइज को रीकंसाइल करके कोई जवाब देने की कृपा करेंगे क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब ने तो दो साल कह दिया लेकिन मिनिस्टर साहब ने स्वयं कहा कि सबजैक्ट टु दी अवेलेबिलिटी आफ मैटीरियल एंड फंडज लगभग तीन साल में पूरा करने की कोशिश करेंगे? क्या वे यह भी बताएंगे कि गवर्नमैंट के सामने अब फंड्ज और मैटीरियल की क्या दिक्कत है? क्या यह स्कीम सारी चीजें देख करके शुरु नही की गई थीं?

(कोई उत्तर नही दिया गया)

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न श्री के0 एन0 गुलाटी।

श्री क0 एन0 गुलाटी: स्पीकर साहब, क्प्या पहले मेरे प्रश्न संख्या 435 को ले लिया जाए, बाद में इसे ले लेना।

श्री अध्यक्ष: आप पहले यह बोलिए।

श्री के0 एन0 गुलाटी: प्रश्न संख्या 436।

Medical Colleges

***436 Shri K.N. Gulati:** Will the Minister of Industries be please to state-

(a) the total number of Medical Colleges running in the State; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to open more such colleges at different places in the State?

State Minister for Home & Health (Smt. Sharda Rani):

(a) Yes

(b) No.

श्री के0 एन0 गुलाटी: स्पीकर साहब, मुझे उत्तर सुनाई नही दिया।

श्री अध्यक्ष: एक में हां, एक में ना।

Gunny Bags

***443. Chaudhri Mehar Chand:** Will the Minister for Agriculture be please to state-

(a) the total number of gunny bags purchased by the Food and Supplies Department] Haryana in connection with the procurement of wheat in Rai 1973; and

(b) the total number of bags actually used for procurement of wheat in 1973 by the Food & Supplies Department, Haryana?

State Minister for Irrigation & Power (Sardar Harmohinder Singh Chatha):

(a) 44 lac Bags

(b) 28 Lac 70 thousand Bags.

चौधरी मेहर चन्दः स्पीकर साहब, यह जवाब तो करीब–करीब वैसा ही है। इसमें फर्क कुछ नही है। मार्किटिंग फैडरेशन में भी ज्यादा और यहां भी ज्यादा। कोई बात नही लंकिन क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि गवर्नमैंट का इरादा इस तरह की तिज़ारत करने का ही है ?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः ऐसी बात तो नही है। गवर्नमैंट ऐसा व्यापार नही किया करती। जो ठीक दुरुस्त बात है वह करती है। हमारा जितना टारगैट था उतना गेहूं पैदा नही हुआ। बोरियों का इन्तजाम पहले करना जरुरी था। अगर इन्तजाम नही करते तो गलत बात थी। फिर भी अगर इन बची हुई बोरियों को फूड एंड सप्लाइज़ डिपार्टमैंट बेचना चाहे तो हम बेचना नही चाहते, तो 46 लाख 43 हजार का प्रौफिट हो सकता है।

श्री अमर सिंहः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इन्हे हरियाणा गवर्नमैंट ने खरीदा है या ये भी सैंट्रल गवर्नमैंट ने खरीदी हैं?

कृषि मंत्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, कायदा सरकार का यह है कि डायरैक्टर जनरल, सप्लाईज एंड डिस्पोजल, भारत सरकार जो है वह सारी की सारी परचेजिज करके प्रांतीय सरकार को देता है। जिस तरह से पहले सवाल के जवाब में मैने बताया था उसी तरह से फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमैंट का है। उनके द्वारा हमने सारी 44 लाख बोरियों के आर्डर दिये थे मगर उनमें से 30 लाख बोरियां अब ता आई हैं और 14 लाख बाकी हैं। हमने उस वक्त डायरैक्टर जनरल, से कह दिया था कि बाकी का बारदाना हमें नही चाहिए क्योंकि फसल की पैदावार कम हुई लेकिन उन्होने हमारा आर्डर कैंसल नही किया। उन्होने कहा कि बारदाने का भाव बढ गया है इसलिए आर्डर कैंसल करने से स्टेट को नुकसान होगा। आज 380 का भाव है। जो बारदाना बचा पडा है यदि उसे हम मार्किट रेट पर बेचना चाहें तो 65 लाख से उपर प्रोफिट हो सकता है।

श्री अमर सिंहः क्या अपनरेबल मिनिस्टर यह बताने की क्पा करेंगे कि जो बोरियों बाकी पडी हुई हैं वे डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टज़ पर हैं या एक जगह स्टोर की हुई हैं?

चौधरी भजन लालः डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टज पर हैं। जहां–जहां हमारे प्रोक्योरमैंट सैंटर्ज़ हैं वहा–वहां गोडाउन्ज के अन्दर बिल्कुल सेफ है।

Hissar Aviation Club

***459 Chaudhri Dal Singh:** Will the Minister for Home be pleased to state-

(a) the total number of hangars constructed for the Hissar Aviation Club, Hissar, during the financial years 1972-73 and 173-74, separately;

(b) the total amount spent on the construction of hangars referred in part (a) above; and

(c) the loss, if any, caused due to the fall or damage of the said hangars in the year 1973-74?

Home Minister (Shri. K.L. Poswal):

(a) One hangar was sanctioned for construction at the Hissar Aviation Club in 1972-73 and is yet to be completed.

(b) Total expected cost of the hangar is Rs. 268000/-

(c) No loss has been caused due to the fall or damage of the above referred to hangar in the year 1973-74.

चौधरी दल सिंहः क्या मिनिस्टर साहब बताने की कृपा करेंगे कि मई, 1972 में जो हैंगर गिरा था वह हिसार का ही गिरा था या किसी और जगह का गिरा था ?

श्री क0 एल0 पोसवालः वह इसी क्लब का गिरा था लेकिन वह दूसरा था। वह कई साल पहले बना था। यह जो नया बना है यह नही गिरा।

चौधरी फूल चन्द (रोहट): स्पीकर साहब, पिछले वर्ष जब डिमांडज् पास हुई थी तो उनमें एक डिमांड हवाई जहाज खरीदने के लिए थी। क्या मिनिस्टर साहब बतायेंगे कि वह खरीद लिया गया है और यदि खरीद लिया गया है तो कितने का खरीदा गया है ?

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब इससे क्या सम्बन्ध है इस प्रश्न का ?

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल): स्पीकर साहब, मैं बता ही देता हूं कि वह खरीद लिया गया है और जल्दी ही आने वाला है।

चौधरी दल सिंहः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करें कि जो हैंगर हिसार में गिरा था उससे कितना नुकसान हुआ?

श्री के. एल. पोसवालः उससे तीन एयरक्राफट्स और चार ग्लाईडर्ज़ डेमेज हुए और करीब एक लाख की रिपायर्ज का नुकसान हुआ।

चौधरी राम लाल वधवाः क्या मंत्री महोदय बताने की क्पा करेंगे कि इस हैंगर के गिरने का कारण क्या था?

श्री के. एल. पोसवालः जबरदस्त तूफान आया था, उसकी वजह से एक दीवार गिरी थी।

चौधरी दल सिंहः क्या वजीर साहब यह बताने की कृपा करेंगे कि इस सिलसिले में इन्कवायरी होल्ड की गयी है या सरकार का इन्कवायरी करने का अब भी विचार है?

श्री के. एल. पोसवालः इन्कवायरी विजिलैंस को भेजी हुई है अभी तक उसकी रिर्पोट नही आई है।

Industries in Public Sector and Private Sector

***483. Shri Girish Chander Joshi:** Will the Minister for Industries be pleased to state the total number of Industries started in urban and rural areas separately, in Public Sector and Private Sector, respectively, during the financial year 1972-73?

Industries Minister (Shri Harpal Singh):

Public Sector		Private Sector	
Urban	Rural	Urban	Rural
Nil	1	1115	362

श्री गिरीश चन्द्र जोशीः क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि रुरल एरिया में प्राइवेट सैक्टर में और पब्लिक सैक्टर में कहां–कहां पर इंडस्ट्री लगाई गई है?

श्री हरपाल सिंहः वह तो बडी लम्बी लिस्ट है आपने डिटेल पूछी थी वह मैनें बता दी है। कहां–कहां पर हैं, यह अन्दाजा नही लग सकता है।

चौधरी राम लाल वधवा: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिलेवार क्या पोजीशन है?

श्री हरपाल सिंह: इसके लिए भी सैपरेट नोटिस चाहिए।

Chaudhri Mehar Chand: May I know from the Industries Minister the reason for slow progress in rural areas?

श्री हरपाल सिंह: स्पीकर साहब रुरल एरिया में इंडस्ट्री बहुत कम लोग लगाना चाहते है। जिन लोगों को भी इंडस्ट्री लगाने का इन्ट्रैस्ट होता है वह शहरो के नजदीक लगाने का ही होता है। सरकार अपनी तरफ से काफी कोशिश कर रही है कि लोग रुरल एरिया में इंडस्ट्री लगाए और उस तरफ को ध्यान दें। हमने तो रुरल एरिया में कई जगह पर ट्रेनिंग सैंटर भी खोले हैं। हम रुरल एरिया में इंडस्ट्री लगाने के लिए रिकमैन्ड भी कर रहे हैं कि किस एरिया में कौन कौन सी इंडस्ट्री लग सकती है। दो–तीन डिस्ट्रिक्ट का सर्वे भी किया गया है उन जिलों में ही रिकमैंड कर रहे हैं। रुरल एरिया के लिए हम एक्सट्रा फेसेलिटीज़ भी दे रहे हैं लेकिन फिर भी बहुत कम लोग आ रहे हैं तो इसमें गवर्नमैंट की कोई जिम्मेवारी नही है।

चौधरी दल सिंह: क्या मिनिस्टर महोदय यह बताने की कृपा करेंग कि इंडस्ट्री लगाते समय बैकवर्ड इलाके का भी ख्याल रखेंगे? अगर ख्याल रखा गया है तो क्या रखा गया है?

श्री हरपाल सिंह: स्पीकर साहब बैकवर्ड एरिया का काफी ख्याल रखा जा रहा है।

श्री गौरी शंकरः क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेगे कि गवर्नमैंट आफ इंडिया के लैवल पर हमारे हरियाणा के कोन–कौन से इलाके बैकवर्ड सलैक्ट किये गए है ?

श्री हरपाल सिंहः स्पीकर साहब अभी इस बारे में क्लियर नही हुआ है। गवर्नमैंट आफ इंडिया से एक्सपैक्टीड है शायद दो महीने तक यह कलियरैन्स मिल जाएगी कि कौन–कौन से बैकवर्ड जिले करार दिये गये है।

चौधरी मेहर चंदः क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेगे कि डिस्ट्रिक्ट हिसार में जो प्रौजैक्ट आफिसर पोस्ट किया गया था, अब वह अफसर नदारद है। रुरल एरिया में रुरल इंडस्ट्रीज़ को अहमियत क्यों नही दी जाती है?

श्री हरपाल सिंहः स्पीकर साहब यह बात नही है। वहां पर रुरल इंडस्ट्री प्रोजैक्ट अफसर था और एक डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री अफसर हैं। वे आपस में कोआपरेशन से नही चल रहे थे। रुरल इंडस्ट्री प्रोजैक्ट आफिसर को डी. आई. ओ. के अंडर काम करना पडता था। वैसे वह उससे सीनियर था। इसलिए अब एक आदमी को वहां पर पोस्ट किया हुआ है वही रुरल एरिया के काम को कर रहा है और दूसरे काम को भी कर रहा है।

चौधरी दल सिंहः क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जब पब्लिक सैक्टर में इंडस्ट्री लगाने के लिए साइट की सलैक्शन करते है तो किन–किन बातों का ध्यान रखते है?

श्री हरपाल सिंहः साइट की सलैक्शन करते वक्त कई बातों को ध्यान में रखा जाता है। इस बारे में मैने पहले भी बताया है कि उस एरिया में जो ज्वायंट सैक्टर में इंडस्ट्री लगती है वहां कोलैबोरेटर की कनसैन्ट देखनी होती है। पब्लिक सैक्टर में यह भी देखना होता है कि वहां रा–मैटीरियल अवेलेबल है या नही जहां पर रा–मैटीरियल मिलेगा वहीं पर प्रैफरैन्स दी जाएगी। जैसे सीमेंट का प्रोजैक्ट है, जहां पर पत्थर मिलेगा उसी एरिया में लगेगा। ऐसी कई बातों का ख्याल रखा जाता है।

Milk Bar

***492 Shri Gauri Shankar:** Will the Minister for Transport be pleased to state whether the Government contemplated to open Milk Bars on High-ways and at other suitable places in the State; if so when?

Transport Minister (Col. Maha Singh): Yes. Milk is being sold to the public at Chakravarti lake by the Department of Tourism and on bus stands at Ambala and Karnal by the Transport Department. Milk Bar will be started there from 23-11-73. It is also proposed to set up a permanent Milk Bar in the compound of the Milk Plant Ambala on the G.T. Road shortly, It is already functioning in a temporary shed. One more Milk Bar will shortly be started at bus depot Panipat.

चौधरी दल सिंहः क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जब जींद में बीयर बार खोल दी है तो क्या वहां पर मिल्क बार खोलने की भी कोई तजवीज़ है?

कर्नल महा सिंहः जींद में तो पहले ही मिल्क प्लांट है वहां पर घी, बटर और पाउडर तैयार किया जाता है। अम्बाला के अंदर बौटलिंग की जाती है इसलिए वहां से जींद ले जाने के साधन नही हैं।

चौधरी फूल सिंह कटारियाः क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस प्रकार से जगह–जगह पर मिल्क बार खोल रहे है क्या रोहतक में भी मिल्क बार खोलने की कोई प्रोपोज़ल है?

कर्नल महा सिंहः रोहतक में मिल्क प्लांट की कंस्ट्रक्शन हो रही है। अगले साल तक मुकम्मल होने की आशा है। जब मुकम्मल हो जाएगा तो वहां भी ऐसी सुविधा दे दी जाएगी।

श्री औम प्रकाश गर्गः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वे एक्साइज मिनिस्टर महोदय का इसमें मुकाबला कर जायेंगे या नही ? (हंसी)

श्री अमर सिंहः जैसा कि मंत्री महोदय ने फरमाया है कि जी. टी. रोड पर मिल्क बार खोल रहे हैं। क्या नैशनल हाई–वे दिल्ली सिरसा रोड पर भी खोलने की कोई योजना बना रहें हैं?

कर्नल महा सिंहः जब हिसार और सिरसा में मिल्क प्लांट तैयार हो जाएगा तो उधर भी सोचा जाएगा।

चौधरी फूल चन्द (रोहट): जो हमारा मिल्क प्लांट जींद है उसमें वीटा घी तैयार होता है। वीटा घी का पहले भाव 15 रुपये किलो था। जब डालडा घी की कमी हुई तो वीटा घी भी गायब हो गया। अब

जो वीटी की कीमत वसूल की जा रही है वह 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से की जा रही है। जब सरकार की ओर से दूध उसी भाव पर लिया जा रहा है तो घी की कीमत क्यों बढाई गई?

कर्नल महा सिंहः दूध की कीमत भी बढा दी गयी है। जब दूध की कीमतें बढी तो उसी के साथ घी की कीमतें बढी।

Chaudhri Mehar Chand: Will the Hon. Minister kindly consider the possibility of opening atleast a Milk Bar any where in my constituency?

Col. Maha Singh: I regret inability.

Tubewells

***502 Chaudhri Phool Chand (Mullana):** Will the Chief Minister be pleased to state the total number of tubewells energised during the year 1972-73?

State Minister for Irrigation & Power (Sardar Harmohinder Singh Chatha): 15649

Chaudhri Phool Chand (Mullana): May I know from the Hon. Minister the reason of delay in energising the newly built tubewells?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः स्पीकर साहब डिले नही हो रही है। ज्यों–ज्यों हमें टैस्ट रिर्पोट मिल रही है, उसी के अनुसार साथ ही साथ हम कुनैक्शन दे रहे हैं।

मलिक सतराम दास बतराः क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि महेन्द्रगढ जिले में 3300 ट्यूबवैल को और रोहतक जिले में 800 टयूबवैल को कुनैक्शन इसलिए नही दिया जा रहा है कि वहां पर मैटीरियल उपलब्ध नही है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः स्पीकर साहब यह बात नही हो सकती और अगर यह बात होगी तो हम जांच कर लेंगे।

चौधरी फूल सिंह कटारियाः क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेगे कि कौसली गावं जिला रोहतक में अभी तक दो सौ कनेक्शन देने इसलिए बाकी है कि वहां पर मैटीरियल नही है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः स्पीकर साहब बहुत जगह पर तो टैस्ट रिपोर्ट गलत आती है, कई जगह पर टैस्ट रिपोर्ट इन–कम्पलीट होती है या मिलती ही नही है। मैटीरियल की भी कहीं–कहीं पर कमी है। वह भी पुरी करनी जरुरी है।

श्री जोगिन्द्र सिंह श्योरानः मेरे नारनौंद के इलाके में टैस्ट रिपोर्ट भी ठीक आयी हुई है लेकिन वहां के अफसर यही कहते है कि मैटीरियल नही है।

श्रीमती लेखवती जैनः क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अम्बाला जिले में कितने टयूबवैल लगाये है और खासतौर पर मेरी कोंस्टीच्युएंसी में कितने लगाये हैं? क्या गवर्नमैंट इस बात को कन्सिडर करेगी कि अम्बाला सिटी के पास जो पार्टियां हैं जहों पर

लोग काश्त भी करते है वहां पर भी कोई ट्यूबवैल लगाने का सरका विचार रखती है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः बहिन जीम को यह पता ही नही है कि यह सवाल बिजनी कनेक्शन देने के बारे में है या ट्यूबवैल लगाने के बारे में?

श्रीमती लेखवती जैनः मुझे यह सवाल मालूम है कि आज बिजली के कनेक्शन के लिए सवाल है। लेकिन हमें मौका ही कहां मिलता है कवैश्चल करने का। फिर भी यह पानी से कुछ तो सम्बंध रखता है। (व्यवधान व शोर)

चौधरी राम लाल वधवाः क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि ट्यूबवैल की जिलावार पोजीशन क्या है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः जिला वाईज पोजीशन तो हमारे पास नही है, हमारे पास सर्कल–वाईज पोजीशन जरुर है।

श्री अमर सिंहः क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि डिसिट्रक्ट–वाईज़ कितनी ऐप्लीकेशन्ज़ टैस्ट रिपोर्ट आने के बाद भी पैंडींग पडी है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः मैंने अभी बताया है कि डिस्ट्रिक्ट–वाईज नही, हमारे पास सर्कल–वाईज पोजीशन होती है।

श्री अमर सिंहः आप सर्कल वाईज पोजीशन ही बता दें?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः ट्यूबवैल जो ऐनरजाईज़ किये है, वह तो पोजीशन मेरे पास है, कितनी टैस्ट रिपोर्टस् अभी पैंडिंग है, वह मेरे पास नही है।

चौधरी दल सिंहः क्या मिनिस्टर साहब यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जींद डिवीजन में कितनी ऐप्लीकेशन्ज़ ऐसी है जिनकी टैस्ट रिपोर्ट आयी हुई है और जो कुनैक्शनज़ देने के लिए पैंडिंग पडी है और उनको कब तक कुनैक्शन दे देगें?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः स्पीकर साहब, ये एक बहुत पुराने पार्लियामैटेरियल हैं। मैं इनसे यह अर्ज करुगां कि इनका यह सवाल बिल्कुल रैलेबैंट नही है। क्या यह मेन सवाल जींद से ताल्लुक रखता है? जींद के मुताल्लिक अलग से नोटिस दें, मैं फौरन जवाब दे दूंगा।

चौधरी श्यामलालः क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि क्या यह हकीकत है कि मेरे इलाके पलवल सब–डिविज़न में टेस्ट रिपोर्ट 3 मई 193 के बाद से पैंडिंग पडी है? वह कहते हैं कि मैटीरियल की कमी की वजह से कुनैक्शनज़ नही दे पा रहे हैं। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि कब तक कुनैक्शन दे दिये जाएगें।

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः अगर कहीं डिले नही हुई तो इस बात की हम जांच कर लेंगे लेकिन महकमा बहुत जल्दी सबको कुनैक्शन देने की कोशिश कर रहा है।

मलिक सतराम दास बतराः क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि अफसर शाम को आपकी लाईनों पर बोल्टेज बिल्कुल कम हो जाती है, उसके लिए आप क्या उपाय कर रह हैं?

मुख्यमंत्री (चौधरी बंसी लाल): स्पीकर साहब, हकीकत यह है कि इस किस्म की शिकायतें मेरे पास भी आई हैं। मैनें अभी पूरी स्टेट का टूर किया है। ऐसी शिकायत भी आई है कि वोल्टेज़ भी लो हो जाती है। ऐसी बातें भी आई हैं कि ट्यूबवैल्ज़ को कनेक्शन नही मिल रहे हैं लंकिन हमने इस बात की कोशिश की है कि एक तो पावर फलक्चुऐशन न हो। तो मेरा ख्याल है कि अगले तीन दिन के बाद जो हमने प्रैजैंट अरैंजमैंट्स किए है, न पावर फलक्चुऐशन होगी, न ट्यूबवैल को बिजनी की किसी किस्म की दिक्कत रहेगी।18 से 24 घंटे तक हम बिजनी भी देंगे। जहां तक ज्यादा कुनैक्शन देने का सवाल है, ऐप्लीकेशन्ज़ पैन्डिंग बहुत हैं लेकिन किसी जगह टैस्ट रिपोर्टस नही है और जहां टैस्ट रिपोर्ट आ गई हैं वहां तेजी से कुनैक्शन भी दिए हैं। कुछ मैटीरियल की कमी है। मैटीरियल के आने में दिक्कत भी होती है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा ट्यूबवैल को सोईन्ग सीज़न के खत्म होने के पहले, हमारा कुनैक्शन दे देने का इरादा है।

Staff for Schools

***511. Chaudhri Phul Singh Kataria:** Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any school under-staffed in the Salhawas Assembly Constituency; if so, the total number thereof together with the steps, if any, taken or proposed to be taken to provide adequate staff in the said schools?

शिक्षा तथा परिवहन राज्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी): हां, सालहावास निर्वाचन–क्षेत्र में 30 स्कूलों मे स्टाफ की कमी है। कुछ पदो के भरने के आदेश पहले ही जारी किए जा चुके है। शेष पदो के उस समय भरा जाएगा जब रिक्त पदो को भरने तथा पद बनाने पर लगाया गया प्रंतिबंध हटा दिया जावेगा। यह प्रतिबंध खर्च में बचत करने के लिए लगाया गया है।

मलिक संत राम दास बतरा: क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगी कि जहां पर स्कूल में स्ट्रेंथ तो 150.200 के करीब है लेकिन वहां पर किसी में एक मास्टर है और किसी में बिल्कुल भी नही है, वहां के लिए क्या उपाय सोचा है?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: सारी स्टेट में ही टीचर्ज़ की ट्रांसफर होने की वजह से दूर–दूर के जो गांव हैं, उनमें काफी स्कूल ऐसे हैं जहां टीचर्ज़ की कमी है और उसके लिए जल्दी ही उपाय किए जा रहे हैं। वहां पर जल्दी ही स्टाफ लगाने की कोशिश की जा रही है।

चौधरी फूल सिंह कटारिया: मंत्री महोदया यह बतायेंगी जैसे कि उन्होने बताया है कि साल्हावास के हल्के में 30 स्कूलों में स्टाफ की कमी है, क्या उन्होने यह अन्दाजा नही लगाया कि इससे बच्चों की कितनी पढाई का नुकसान हो रहा है?

श्री अध्यक्ष: ठीक है, उन्होने यह बताया है कि जल्दी ही उपाय कर रहे है।

श्री अमर सिंहः मंत्री महोदया ने बताया है कि एक ही कांस्टीचूऐंसी में 30 गांव के अंदर स्टाफ की कमी है। इसी तरह से सारी स्टेट में स्टाफ की.....

श्री अध्यक्षः सारी स्टेट की फिगर्ज़ भी कल एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने बतायी थी।

श्री अमर सिंहः क्या आने वाले दिनों में इम्तहानो का ख्याल रखते हुए टीचर्ज़ जल्दी ही लगायेंगे या टीचर्ज़ उन्हें इम्तीहानों के बाद ही मिलेंगे?

श्रीमती प्रसन्नी देवीः मैंने कहा है बहुत जल्दी ही उपाय किये जा रहे है। इम्तहानो का भी ख्याल रखा जाएगा और हमें यह ख्याल भी है कि इम्तहानो में टाईम थोडा है इसलिए टीचर्ज को लगाने का जल्दी से जल्दी प्रबंध किया जा रहा है।

चौधरी पीर चन्दः यह जो टीचरों की कमी है, टीचर्ज़ न मिलने की वजह से है या गवर्नमैंट के पास पैसा न होने की वजह से नही लगाये जा रहे है?

श्रीमती प्रसन्नी देवीः सवाल के जवाब में मैंने बताया है कि खर्च में बचत करने के लिए कुछ प्रतिबंध लगाया गया है। टीचर्ज की कोंई कमी नही है।

Training in the Industrial Training Institute, Faridabad

***435 Shri K. N. Gulati:** Will the Minister for Industries be please to state:-

(a) whether there are any arrangement for imparting training in Radio, Television and Draughtsmanship in the Industrial Training Institute at Faridabad; and

(b) if the reply to part (a) above be in the negative the time by which the said arrangements are likely to be made?

Home Minister (Shri K. L. Poswal)

(a) No, Sir

(b) The Proposal for imparting training in Radio, Television and Draughtsmanship (Civil and Mechanical trades) in the Industrial Training Institute, Faridabad will be considered during the next year.

चौधरी राम लाल वधवा: क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हरियाणपा में किसी और आई. टी. आई. में भी इस प्रकार की ट्रेनिंग का अरेंजमैंट है?

श्री के. एल. पोसवाल: जी हां। यह है अम्बाला, भिवानी, गुडगांव, हिसार, महेन्द्रगढ, रोहतक, सोनीपत, सिरसा और यमुनानगर में।

चौधरी राम लाल वधवा: क्या मंत्री महोदय यह फरमाएंगे कि करनाल में भी आई. टी. आई. में इस ट्रेनिंग का अरेंजमैंट किया जाएगा?

श्री के. एल. पोसवालः फिलहाल नही।

चौधरी शिव राम वर्माः स्पीकर साहिबा, गुलाटी साहब का एक क्वैश्चन नम्बर 436 था। उसका सवाल कुछ था और जवाब कुछ और ही था। अगर, उसका जवाब क्लीयर हो जाए तो अच्छा है। The question was-

'the total number of Medical Colleges running in the State:'

and the reply was 'Yes'.

श्री अध्यक्षः वह बात तो अब खत्म हो गई है। अब उसको रेज़ करने का कोई फायदा नही है।

चौधरी शिव राम वर्माः स्पीकर साहब यह बात यहां पर आई है अगर क्लीअर हो जाए तो अच्छा है।

श्री अध्यक्षः वह तो उसी समय पर आ सकती थी।

तारांकित प्रश्न सं0 513 के संबंध में अध्यक्ष द्वारा निरुपण

श्री अध्यक्षः मैनें कल सर्वश्री जगजीत सिंह, रामकिशन आजाद, पोकर राम गोदारा तथा धज्जा राम के स्टार्ड प्रश्न नम्बर 513 पर जो अपना निर्णय देने की घोषणा की थी इस प्रश्न के संबंध में मैने सरकार से पूरा ब्यौरा मांगा है, इसलिए इस प्रश्न पर मै अपना निर्णय 15 नवम्बर, 1973 को दूंगा। यानी परसो

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष: मेरे पास चौधरी अमर सिंह विधायक की ओर से एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (काल अटैंशन नोटिस) प्राप्त हुआ है जिसमें आवश्यक वस्तुओं की कमी और उनके वितरण आदि के बारे में जनता की कटिनाईयों का वर्णन किया है। मै इसे स्वीकार करता हूं। सदस्य महोदय अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पढ दें।

Shri Amar Singh: Sir I beg to draw the attention of the House to a matter of urgent public importance, namely, shortages of essential commodities and consequent rise in prices thereof.

There is acute shortage and scarcity of the following comodities in the state:-

(i) Soft Coal

(ii) Seeds of Wheat and Gram

(iii) Fertilizer

(iv) Dalda Ghee

(v) Cement

(vi) Kerosene Oil

(vii) Rice & Wheat

The prices of these commodities are rising day-by-day resulting in lot of harassment to the people. The people have to stand from morning till evening in queues to get these essential commodities.

The Agriculturists feel handicapped in growing more food for want of fertilizer, seeds, cement and tractors etc.

There is great resentment amongst the people because the Government had not taken concrete steps to supply these bare necessities of life through fair prices shops at reasonable prices.

The poor and middle classes and specially Harijans who are unemployed in rural areas are hit hard by the increase in prices of these essential commodities and they are facing financial difficulties.

I, therefore, urge upon the State Governent to take immediate steps to control the prices of essential commodities and supply these through fair price shops etc. at reasonable prices and thus check the situation in the State as early as possible.

श्री अध्यक्षः मंत्री महोदय अब अपना वक्तव्य दें।

कृषि मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, इसके लिए 15 तारीख तक का समय दिया जाए।

श्री अध्यक्षः ठीक है।

चौधरी राम लाल वधवाः अध्यक्ष महोदय, मैने इसी क्वैश्चल पर एक मोशन दी थी जो पैंडिंग रखी है। यह काल अटैनशन मोशन तो स्वीकार कर लिया गया है लेकिन मेरा मोशन अभी तक पैंडिंग है उसे भी स्वीकार कर लिया जाए, ताकि मामला पर पुरे तौर से बहस की जा सके।

श्री अध्यक्षः आप इसकी वजह जानना चाहते हैं तो–

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब इससे तो सिर्फ सरकार का पक्ष जो है वह ही आएगा और दूसरा पक्ष नही आएगा। अगर मोशन एडमिट हो जाता है तो इस विषय पर पूर्ण रुप से बहस हो जाती।

श्री अध्यक्ष: आप तशरीफ रखिए। इस सम्बंध में आपको उत्तर मिल गया होगा और अगर आप आगे बातचीत करना चाहते है तो मेरे चैम्बर में आ जाएं वहां बात कर लेंगे।

कार्य मंत्रणा समिति का प्रथम प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष: मैं विभिन्न कार्य के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति द्वारा निश्चित की गई समय–सारणी प्रतिवेदित करता हूं जो कि इस प्रकार है–

कुछ चर्चा के पश्चात् समिति ने सिफारिश की कि 13 नवम्बर, 1973 को निम्नलिखित रुप में कार्य किया जाए:–

1. प्रश्न समय।

2. कार्य मंत्रणा समिति का प्रथम प्रतिवेदन, पेश करना तथा उसे अंगीकार करना।

3. अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) 1973.74 पर चर्चा तथा मतदान।

Home Minister (Shri K. L. Poswal): Sir, I beg to move-

That this house agree with the recommendations contained in the Fist Report of the Business Advisory Committee

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति के प्रथम प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है।

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है –

कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति के प्रथम प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशे स्वीकार करता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) 1973.74

(1) राज्य के राजस्वों पर प्रभृत व्यय के अनुमानो पर चर्चा

श्री अध्यक्षः कांई सदस्य राज्य के राजसवो पर प्रभृत व्यय के अनुमानो पर चर्चा करना चाहे तो कर सकते है।

(कांई सदस्य बोलने के लिए खडा नही हुआ)

(2) अनुपूरक अनुदानो की मॉगो पर चर्चा तथा मतदान

श्री अध्यक्षः पूर्व प्रथा के अनुसार तथा सदन का समय बचाने के लिए, कार्य सूची में दी गई अनुदानो की मांगे एक साथ पढी तथा प्रस्तुत की गई समझी जाएंगी। माननीय सदस्य मांगो पर चर्चा उठा

सकते है किन्तु बोलते समय उन्हे मांग का कमांक बताना होगा जिस पर वे चर्चा उठाना चाहते है।

कि एक अनुपूरक धन–राशि, जो 1200000 रुपये से अधिक नहो, 26 विविध विभाग के सम्बंध में 31 मार्च 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के कम में आने वाले खर्चो के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो 267260 रुपये से अधिक न हो 35. उधोग के संबंध में 31 मार्च 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष कें भुगतान के कम में आने वाले खर्चो के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो 17575020 रुपये से अधिक न हो 39.विविध सामाजिक तथा विकासात्मक संगठन के संबंध में 31 मार्च 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष के भूगतान के कम में आने वाले खर्चो के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो 952750 रुपये से अधिक न हो 50–लोक–निर्माण–कार्य के संबंध में 31 मार्च 1974 को समाप्त हाने वाले वर्ष के भुगतान के कम मे आने वाले खर्चो के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो 123200 रुपये से अधिक न हो 70–वन के संबंध में 31 मार्च 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष के

भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो 296870 रुपये से अधिक न हो 71—विविध के संबंध में 31 मार्च 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो 74800000 रुपये से अधिक न हो 99—सिंचाई नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय (वाणिज्यिक) के सम्बंध में 31 मार्च 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो 8000000 रुपये से अधिक न हो 103—लोक—निर्माण—कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय के संबंध में 31 मार्च 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष के भूगतान के क्रम में आने वाले खर्चों के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो 20 रुपये से अधिक न हो स्थनीय निधियों तथा गैर—सरकारी पाटिर्यों को कर्जे के संबंध में 31 मार्च 1974को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

श्री अमर सिंह (बवानी खेडा अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, हाउस के सामने जो सप्लीमेन्टरी एस्अीमेट्स हैं उन में सात—आठ

डिमान्ड्ज़ हैं। इन डिमान्ड्ज़ की बाबत मैं यह कहना चाहता हूं कि इनमें से बहुत सारी डिमांड्ज़ तो ऐसी है जो जेनविन हैं और जायज हैं और मैं भी पूरी तरह से समर्थन करता हूं। एक–दो डिमांड्ज़ ऐसी हैं जिनकी बाबत मैं आपत्ती करता हूं। स्पीकर साहब, मैं एक–एक डिमांड पर अपने विचार जाहिर करुंगा। सब से पहले मैं डिमांड 45 पर अपने विचार रखना चाहता हूं। इस डिमांड में साठ लाख इक्कीस हजार छह सौ रुपया मांगा है। इसमें से 30 लाख रुपया तो जो नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं वहां पर बिल्डिंग वगैरह बनाने और लैंड ऐक्वीजीशन के लिए है और पचास लाख रुपया बैड का अस्पताल भिवानी में खोलने के लिए मांगा गया है।

स्पीकर साहब, जब डिस्ट्रिक्ट बन गया तो डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्ज पर डी. सी. का रैजीडैन्स होना निहायत जरुरी है और भिवानी में जो 500 बैड्ज का अस्पताल बन रहा है वह भी बहुत जरुरी है लेकिन इसके साथ–साथ मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जब भिवानी जिला बना तो इसके साथ बवानी खेडा तहसील बन गई और स्पीकर साहब, आपको जाति तौर पर जानकारी होगी कि भिवानी और बवानी खेडा में सिर्फ बारह–चौदह मिल का फासला है और वहां पर एक छोटी सी डिस्पैंसरी है वहां पर न कोई दवाई मिलती है और न दूसरी चीजों का प्रोपर अरेन्जमैंट है । वहां पांच बैडज़ का अस्पताल भी नही है। जब डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्ज पर आप 500 बैड्ज का अस्पताल खोलने जा रहे है तो तहसील हैडक्वार्टर्ज या सब डिविजनल हैडक्वार्टर्ज पर भी कम से कम 25 बैडज का अस्पताल खोलने की योजना बनानी चाहिए और यह

योजना बवानी खेडा पर भी लागू की जाए। इसी प्रकार जब डिस्ट्रीक्ट हैडक्वार्टर्ज पर जैसे भिवानी, कुरुक्षेत्र और पानीपत में रैजिडैंज और दूसरे आफिस बनाने जा रहे है तो तहसील हैडक्वार्टर्ज पर भी रैजीडैंस और आफिस बनाने चाहिए। बवानी खेडा स्टेशन के पास एक धर्मैशाला थी उसी को वहां पर पुलिस स्टेशन बना दिया गया और इस वजह से जो यात्री वहां पर ठहर जाया करते थे उनको तकलीफ हो गई। जिस तरह से आप डिस्ट्रीक्ट हैडक्वार्टर्ज पर हर सुविधा देने जा रहे हैं तो उसी तरह की सारी सुविधाएं पुलिस स्टेशन की, बिल्डिंगज की रैजिडैंस की तहसील हैडक्वार्टर्ज पर भी प्रदान करनी चाहिए। डिमांड न. 45 के बारे में तो सिर्फ इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि भिवानी डिस्ट्रीक्ट हैडक्वार्टर्ज पर जब 80 लाख रुपया खर्च किया जा रहा है तो इस स्कीम के तहत बवानी खेडा को भी शामिल किया जाना चाहिए। बवानी खेडा के आफिसर्ज को, वहां के कर्मचारियों को वहां के लोगों को भी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। इसके साथ साथ डिमांड नम्बर 14 में 12 लाख रुपया हरिजनो के लिए मकान बनाने के लिए मांगा गया है। यह सैंटर की स्कीम है इसमें लिखा है–

" The Government of India, Ministry of Home Affairs, have conveyed sanction of Rs. 12 lakhs for expenditure on the construction of houses for Harijans in the jayanti Villages under the Centrally Sponsored programme for the welfare of backward classes during the current financial year. Each house will have the minimum accommodations consisting of a living room, a multipurpose room (or a kitchen and a Verandah) and a store. The

financial assistance from the Cente would be to the maximum of Rs. 2000 per house……."

स्पीकर साहब इसमें दिया है कि यह मकान उनको दिए जाएगें जो सफाई का काम करने वाले हैं। उनको यह सुविधा दी जाएगी। लेकिन स्पीकर साहब यह स्कीमें इसलिए अधुरी रह जाती हैं कि आजकल इस महंगाई के जमाने में सिर्फ दो हजार की मदद की जा रही है। इस महंगाई के जमाने में तो दो हजार में एक कमरा भी नही बनता। इतनी महंगाई चल रही है जिसका वर्णन नही किया जा सकता। जब सैन्ट्रल गवर्नमैंट दो हजार रुपये मकान बनाने के लिए देगी और उस रुपये में मकान बनेगा नही तो यह स्कीम एक तरह से फेल हो जाएगी।

मकान बनाना तो आफत मोल लेना है। आज नैसेसटिज आफ लाइफ को हम पूरा नही कर सकते। आज इतनी महंगाई है और वे लोग जिनको कोई धंधा नही मिला, ऐसे लोगों को मकान बनाने के लिए सरकार ने जो 2000 रुपये की राशी रखी है वो बहुत कम है और हरियाणा सरकार की तरफ से भी अगर 800/900 रुपये दे दिए जाएं तो फिर भी वे लोग मकान नही बना सकते और जो मकान बनाने के लिए ईयर मार्किंग होती है, उससे मकान पूरा नही होगा और इस बिनाह पर वह काम अधूरा रह जाता है। इसी तरह से वे गरीब लोग धरती की गोद में सोते हैं और आसमान उनके लिए रजाई का काम देता है तो स्पीकर साहब हम डिस्ट्रीक्ट हैडक्वार्टर्ज पर और सब–डिविज़न पर देखे वहां पर एसे लोगों का अब भी तांता लगा रहता

है जिनको बिल्कुल कोई पनाह नही है और वह बेचारे सर्दियों में ठिठुरते और गर्मियों मे सडते रहते हैं। इसलिए मैं इतना ही अर्ज करुंगा यह जो डिमांड नम्बर 14 में सैन्ट्रली सपोंसर्ड प्रोग्राम के तहत बैकवर्ड क्लासीज़ की भलाई के लिए, मकान बनाने के लिए 12 लाख रुपया रखा गया है इस में हरियाणा प्रदेश गवर्नमैंट भी अपना सहयोग दें। स्पीकर साहब आज से 26–27 साल पहले पूज्य बापू जी ने यह कहा था एशोरेन्स दिया कि देश में ऐसा कोई निवासी नही होग जिसको रोटी, कपडा और रहने के लिए मकान न मिले लेकिन आज गवर्नमैंट के आकडों के मुताबिक 22करोड लोग इस देश में एसे हैं जिनको सुबह की रोटी मिलती है और शाम की नही मिलती है और स्पीकर साहब, हमारे हरियाणा प्रदेश में आज बहुत बेरोजगारी है, बहुत से लोग ऐसे है जिनके पास कोई ऐसे साधन नही है जिन से वे अपने रोज मर्रा का जीवन व्यतीत कर सके। स्पीकर साहब, 30 जून, 1972 के बाद जो रोड्ज़का काम डिसवैन्ड हो गया था, रोडज़ के मिनिस्टर साहब बैठे नही हैं, कोई लगभग साढे तीन लाख आदमी रोज वहां काम करते थे, लेकिन अब वे लोग बिल्कूल बेकार पडे हुए है। बेचारों के पास खाने को नही है। एसे लोगों का धंधा मिलना चाहिए जब तक स्टेट में कोई धंधा नही होगा तो लोगों को काम नही मिलेगा। लैंड सिलिंग की वजह से किसानो को भी खतरा रहता है कि अगर गरीब हरिजनो को काम पर बुला लाए तो कहीं लैंड सिलिंग की वजह से उनकी लेबर वगैरह भी दी हुई बेकार न चली जाए। इस वजह से एग्रीकल्चर लेबर भी बेकार बैठी है। सो मैं अर्ज करुंगा की इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए इस डिमांड के तहत और ज्यादा पैसा

खर्च किया जाए ताकि लोगों को धंधा वगैरह मिल सके। अगर लोगों के पास कोई धंधा, कमाने के साधन नही होंगे तो जो मकान वगैरह बना कर उनको दिए जाएगें, जब तक कि उनके पास धंधें के साधन स्थाई रुप से नही होगें तब तक उनका वहां रहना दूभर हो जाएगा। इसलिए मेरी गुजारिश है कि जैसा कि डिमांड नम्बर 26 के तहत, जो कैष प्रोग्राम सरकार ने रखा है, उसके बारे में मैं कहुगां कि सरकार ने यह कदम बडा सराहनीय उठाया है। बेरोजगारी को रोकने के लिए यह जो सरकार का ध्यान इस तरफ हुआ है यह बहुत अच्छी बात है लेकिन यह दो सैक्टर्ज में है। एक तो एजुकेटिड तबके के अन्दर और दूसरा रुरल एरियाज़ में, वहां पर गरीबी आसमान को छूती है, बेकारी है, लोग बेकार बैठे हुए हैं। मैं तो यहां तक कहुगां कि एग्रीकलचरिस्ट को साल में केवल तीन महीने काम मिलता है और जो लैंड लैस हैं, जैसे लोहार, खेती में काम करने वाले मजदूर, वे लोग तो टोटल 12 महीने ही बेकार रहते हैं, उनके पास कोई काम नही होता है। इसी तरह यह स्कीम सैन्टर की बनाई हुई है। डिमांड नम्बर 26 पेज 6 पर यह दिया है:—

"The schemes under this programme have already been submitted to the Government of India for approval. Under these schemes, it is expected that 10,394 educated persons will be provided jobs under the Training Schemes 176 under self-employment schemes, and 498 under employment incentive schemes which total up to 11,608 persons."

स्पीकर साहब, अगर इसी तरह की स्कीमें रुरल एरियाज़ में भी बना दी जाएं तो मैं समझता हूं कि इस से देश का उत्पादन बढेगा

और साथ साथ लोगों को काम धंधा भी मिलेगा और यह काम स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ द्वारा ही हो सकता है लेकिन वे स्कीम्ज इसी तरह की होनी चाहिए जैसी कि एजुकेटिड तबके के अंदर हैं। अन–एम्पलायमैंट को खत्म करने के लिए ऐसे कदम उठाये जाने चाहिए बेशक इस से एक प्रतिशत अन–एम्पलायमैंट ही क्यों न खत्म हो। इसी तरह से देहातो के अन्दर स्माल स्केल इंडस्ट्रीज खोल करके लोगों को काम दें जैसे कपडा बुनने का काम, चादरें बनाने का काम, तौलिए बनाने का काम, जूते बनाने का काम इत्यादि। अब भी एक गांव का जूता बनाने वाला ग्रामीण बडा सस्ता जूता बनाकर बाजार में दे देता है और बालूजा और दूसरी बडी–बडी कम्पनीयों वाले इन्ही जूतो को एशिया वगैरह से कनटैक्ट करके बाहर भेज देते हैं और वे लोग बहुत फायदा उठाते हैं। तो मैं यह चाहता हू कि इन लोगों कि एक को–ओपरिटिव बेसिजऋ पर सोसाइटी बनाई जाए और ये लोग अपना काम खुद करके खुद एक्सपोर्ट का काम करें ताकि इस काम से जितना फायदा हो, वो सभी लोगों में डिवाइड हो । इसी तरह से गांव गांव में छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ भी लगाई जाएं जैसे चमडे की फैक्ट्री, कपडा बनाने की फैक्ट्री। जैसे मेरा हल्का है बवानी खेडा ऐसी जगहों पर छोटी छोटी दस्तकारी के लिए ये फैक्ट्रीयां लगाई जानी चाहिए इस से मैं समझता हूं कि लोगों को काम धंधा भी मिल जाएगा और पैदावार में भी बढावा होगा। स्पीकर साहब, अब तो देहात के अन्दर जो लोग रहते हैं उन को एक ही बात खठकती है कि जब तक जमीन में मुझे हिस्सा नही मिलेगा उस वक्त तक गांव में हमारा स्टेटस छोटा ही होगा।

श्री अध्यक्षः श्री अमर सिंह, आप जरा टाइम का ध्यान रखें। रैपीटीशन न हो, आप के प्वाइंटस सारे आ जाएं।

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, मैं रेपीटीशन नही कर रहा, डिमांड बहुत है, मैं समय का पूरा ध्यान रखूंगा। इसके साथ साथ दूसरी स्कीम, मैं समझता हूं कि स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ की तरह की, जैसा कि फ्रैश प्रोग्राम फार एजुकेटिड परसन्ज, इसी तरह की रुरल एरियाज़ में भी की जाए और वह स्माल स्केल इंडस्ट्रीज की तरह की कोई स्कम चालू की जाए, जिस से लोगों को बहुत सा धंधा मिलेगा।

इसके साथ साथ कृषि टकनोलोजी, कार्यकलाप विविधता, रोजगार, आय तथा कारीगरी में अतः सम्बंध तथा उसका अध्ययन यह जो इस पर 15 हजार रुपया खर्च किया जा रहा है इसको ठीक समझता हू कि इसे जल्द से जल्द इम्पलीमैंट करवाया जाए तथा इसकी रिपोर्ट हाउस में आए जिससे हाउस को भी पता लग सके। इसके साथ साथ व्यस्क नेत्रहीन प्रशिक्षण केन्द्र, सोनीपत में उत्पादन यूनिट की स्ाापना के लिए सात हजार रुपया खर्च किया जा रहा है जहो तीन किस्म की शिल्प प्रारंभ की जाएगी जैसे टोकरियां बनाना, कताई और बेंत बूनना। ब्लाईंउ पर्सनज़ के लिए यह जो काम है यह बहुत ही अच्छा काम है।

इस तरह से स्पीकर साहब, जो डिमांड नं0 30 है इसमें तीन डिमांड है इनमें से एक डिमांड पर मुझे आपत्ति है और दूसरी दो डिमांडो पर मुझे काई आपत्ति नही है। एक डिमांड जो मंजूरी में रैस्ट हाउस बनाने के लिए गवर्नमैंट 4 लाख 25 हजार रुपया मांग रही है

उसके बारे में मेरा आपके द्वारा निवेदन है कि समाजवाद के दौर में स्पीकर साहब आपको पता है कि ये रैस्ट हाउसिज़ तो बहुत पहले आजादी से पहले राजाओ महाराजाओ ने हर शहर में हर दूसरे प्रदेश में बनाए हुए थे और आज भी अगर हम इस समाजवाद के दौर में रैस्ट हाउसिज़ को ज्यादा तरजीह दें तो यह कोई रचनात्मक बात नही होगी। आज रैस्ट हाउस में वही लोग ठहरेंगे जो अबव मिडल क्लास हैं। गवर्नमैंट के भी या तो आई0 ए0 एस0 अफसर ठहरेंगे या मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर और कोई नही ठहरेगा।

विकास मंत्री (श्री श्याम चन्द): एम0 एल0 ए0 भी ठहर सकता है।

श्री अमर सिंहः अगर एम0 एल0 ए0 अपनी जेब से खर्च करे तो मैं समझता हूं कि उसके लिए वहां ठहरना मुश्किल है। इसलिए मेरी यह गुजारिश है कि यह डिमांड जो है इसके लिए ऐसा भी हो सकता है कि और डिमांड हो जाए। खास तौर से जब हमने इस बात का तहैया किया है कि हमने हर एक को रोटी, कपडा और मकान देना है। और सब को काम देना है तो हमारे सामने इन मसलो के होते हुए हमे इस तरह के अन–प्रोडक्टिव प्रोग्रामो पर पैसा खर्च नही करना चाहिए। मैं इसकी ताइद नही करुंगा कि 4लाख 25 हजार रुपया इतनी दूर मंसूरी में रैस्ट हाउस बनाने के लिए खर्च किया जाए। स्पीकर साहब, अगर आपको या हमारे किसी मिनीस्टर को या चीफ मिनिस्टर को यू0 पी0 में जाना हो तो क्या वहां की सरका ठहरने के लिए जगह नही देगी। इसलिए मैं समझता हूं कि इस पैसे को खर्च करके कोई ज्यादा

बैनीफीट वाली बात नही होगी। जहां तक इनकी नं0 2 डिमांड जो रोहतक भिवानी रेल लिंक के बारे में है इस पर 377750 रुपये रोहतक से भिवानी तक ब्रौड गेज लाईन के सर्वे के बारे में मांगे गए हैं। स्पीकर साहब यह मांग बहुत दिनों से चली आ रही थी और खास तौर से बिजनेसमैन की तरफ से इसकी बहुत डिमांड थी। क्योंकि छोटी लाइन पर उनको माल लाने और ले जाने की बडी दिक्कत रहती थी। यह जो रेलवे ने हरियाणा गवर्नमैंट से 3 लाख 77 हजार 750रुपये मांगे हैं यह एक बहुत ही अच्छे काम के लिए मांगे हैं। मैं आपके द्वारा गवर्नमैंट से कहुंगा कि वह इस मैटर को परस्यु करे ताकि बहुत जल्द यह काम शुरु किया जाए। रेलवे मिनिस्टर साहब से डेट फिक्स करवाई जाए कि फलां तारीख तक यह काम पुरा हो जाए ताकि लोगों को इससे जल्द फायदा पहुंचे। इसमें तीसरी बात जो है वह न्यायिक–मैजिस्ट्रेटों के रिहायशी आवास के लिए उपलब्ध की है। इसके लिए हम एक लाख 50 हजार रुपए खर्च करने जा रह हैं। स्पीकर साहब, इसमें जिक है कि:

"On the creation of new districts in Haryana, it was desired to provide residential accomodation to Judicial magistrates. Accrdingly, it was decided to acquire land in Bhiwani District. A sumof Rs. 150000 was obtained as an advance from the state Contingency Fund to defray the expenses n the purchase on land....."

स्पीकर साहब, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो एग्जैक्टिव से बिल्कुल दूर है उसको प्राईवेट हाउस में रहने से बडी आपत्ती होती है

और उसको इंसाफ करने में भी दिक्कत रहती है तथा लोगों को भी बडे डाउट किएट हो जाते है।

श्री अध्यक्षः आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें क्योंकि और मैम्बरों ने भी बोलना है।

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, इसी तरह से हांसी में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के लिए जमीन एक्वायर हो चुकी है और फंड भी एलोकेट हो चुके हैं दो साल से पैसा पडा है उसका आज तक सदुपयोग नही हुआ। जब वहां कोई इंसैपक्शन पर जाता है तो वह भी कहता है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को अपने रिहायश पर रहना चाहिए। जैसे कि मैने पहले भी बताया कि उसके लिए जमीन एक्वायर हो चुकी है और पैसा भी डिपोजिट हो चुका है लेकिन अभी तक काम शुरु नही हुआ। इसी तरह से अगर यह पैसा भी डिपोजिट हो गया तो आपत्तिजनक बात हो जाएगी। मेरी यह गुजारिश है कि हांसी में भी और भिवानी में भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के लिए एकोमोडेशन जल्द से जल्द बननी चाहिए। स्पीकर साहब, बोलने के लिए डिमांडज़ तो बहुत है पर आपने प्रतिबंध लगा दिया है।

श्री अध्यक्षः प्रतिबंध कोई नही है आप जो बात कहना चाहते हैं टू दी प्वाइंट कह दीजिये। मेरी इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा सदस्य इस बहस में हिस्सा ले सकें।

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, जब आप बीच में बोल पडते हैं तो मेरा रेलवे लाईन की तरह से लिंक टूट जाता है। स्पीकर साहब,

आगे चल कर डिमांड नम्बर 44 आती है। यह सिंचाई, नौ–चालन तथा जल–निकास निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय संबंधी है। इसमें हरियाणा सरका की तरफ से कुछ खर्च नही हो रहा है बल्कि यह पैसा सैंटर से लिया है। इससे इंदिरा गांधी नहर, बी0 एन0 चक्रवर्ती नहर तथा पश्चिमी यमुना आवर्धन नहर (प्रथम चरण) का निर्माण तथा हांसी शाखा को पक्का किया जाएगा। यह स्कीम 7 करोड 48 लाख रुपयो की है पहले 5 करोड 50लाख रुपये हम इस स्कीम के लिए ले चुके हैं। यह पैसा देने के लिए सैंटर को ही एग्री कराया गया है हरियाणा गवर्नमैंट को कुछ नही देना पडेगा। इसके साथ साथ इस डिमांड के साथ में यह ऐड करवाना चाहता हूं कि जहो छोटे–छोटे माईनरो की एक्शटेंशन है और उनको इम्पलीमैंट होने में देर की संभावना हो उनको पहले करवाया जाए। जैसे मेरी कांस्टीच्यूएंसी के वधना माइनर की अगर दो मील की एक्सटेंशन हो जाए तो हम बन्दम ज्यादा दे सकेत है। वह स्कीम तैयार है। गवर्नमैंट के पास आई हुई है। अगर बडी स्कीमों के साथ साथ छोटी स्कीमो की तरफ भी सरकार का ध्यान हो तो उस से पैदावार भी बढेगी और सूखे में खुशहाली आएगी। इसलिए मैं निवेदन करुंगा कि हमारी जो छोटी स्कीमें है वह रुकनी नही चाहिए। स्पीकर साहब आपका ध्यान मेरी तरफ है मैने अभी कुछ डिमांड्ज पर और बोलना था लेकिन आप चूंकि बैठने को कह रहे है इसलिए मैं इतना कह कर अपना स्थान लेता हूं।

चोधरी चांद राम (बबैन अनुसूचित जाति): माननीय स्पीकर साहब मेरे साथी पूर्ववक्ता श्री अमर सिंह जी ने काफी बातें कह दी हैं

और इसलिए मैं समझता हूं कि मुझे वे बातें दोहराने की जरुरत नही पडेगी। यह जो बजट है इसमें शब्द तो बहुत सुन्दर हैं और उनका ध्येय भी अच्छा दर्शाया गया है। बेरोजगारी दूर करने का जिक्र है, इस के लिए यह करेंगे, वह करेंगे। लक्ष्य तो अच्छे हैं इस बात में कोई शक नही। आजादी के 26 सालों में हम बहुत सुन्दर–सून्दर लफ्ज़ छाप कर ऐसे नारे लगाने रहे हैं लेकिन उसका फायदा तो क्या आज हालत यह है कि बेरोजगारी टाप पर है और कीमतें बहुत ज्यादा बढ रही हैं।

श्री अध्यक्षः चौधरी चांद राम जी आप डिमांड का हवाला दे कर बोलें।

चौधरी चांदरामः अभी तो स्पीकर साहब मैंने दो लाईने ही कही हैं। यह डिमांड्ज जो हैं किस–किस का नाम लूं, सारी बडी खूबसूरत डिमांड्ज हैं। शूरु में यह है कि एजूकेटिड अनएम्पलायड लोगों को रोजगार देंगे। इससे भी पहले जो लोग अनक्लीन प्रोफैशन करते हैं जो चमडे का या पिगरी वगैरा का काम करते हैं उन को घर बना कर देने के लिए डिमांड लाई गई है। इस के लिए 12लाख रुपया रखा गया है। और एक मकान कहते हैं दो हजार रुपये में बनेगा और उसमें बताया है एक कमरा, रसोई और बरामदा होगा। इसका मतलब है कि सारी स्टेट में 12 लाख रु में 600 मकान बनेगें और दस जिलो में अगर वह बराबर बांटें जाए तो एक जिले में 60 मकान आएंगे। तो आप अंदाजा लगाएं कि सारी स्टेट में जो 600 मकान बनाने से जो लोग अनक्लीन काम करने वाले हैं उनका क्या भला हो जाएगा। क्या ये मकान उन सब के लिए काफी होंगे? यह तो लोगों का झुठलाने वाली

बात है। आज रोज रेडियों में और अखबरो में परापोगंडा किया जाता है कि हम ने हरिजनो के लिए यह कर दिया, हम ने हरिजनो के लिए वह कर दिया। लेकिन उसके साथ अमाउंट के बारे में कोई नही बताता और उस से कितने लोगों को फायदा पहुंचेगा उस के फायदे की सीमा कोई नही बताता। सारे साल में सिर्फ 24 हरिजनो को जमीन मिली है और कहने को हर रोज यह ढिंढोरा पीटा जाता है कि हमने हरिजनो को जमीन दी है। मैं समझता हूं कि यह जो 12लाख रुपये की रकम रखी है यह बहूत थोडी है, इससे क्या फायदा हो सकता है? आप इस रकम को बढाएं और फिर अमली तौर पर साबित करें कि हम उनका पूरा फायदा कर रहे हैं जो लोग अस्वच्छ हैं। जैसे चौधरी अमर सिंह जी ने भी पहले काफी जिक्र किया है कि यह मंसूरी में भवन बनाने जा रहे हैं। इस तरह की अनप्रोडक्टिव स्कीमों पर खर्च करना अच्छी बात नही है। मैं पूछता हूं कि उस का गरीब लोगों को क्या फायदा मिलेगा।कौन जाएगा वहां पर। वहां पर अमीर लोग ही सैर करने के लिए जाएंगे। कितनी अजीब बात है कि हम अनप्रोडक्टिव स्कीमो पर पैसा खर्च कर रहें है। असूल के तौर पर सब को यह बात माननी पडेगी कि अनप्रोडक्टिव और मनोंरंजन के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है उस का कोई फायदा नही है। इसलिए मैं कहूंगा कि ऐसी फिजूलखर्ची को बंद करके प्रोडक्टिव स्कीमो पर सरकार को पैसा खर्च करना चाहिए। अगली है डिमांड नं0 23 जो कि शिक्षित बेरोजगारी को दूर करने के लिए है यह भी बडी अजीब सी बात है। इस देश में शिक्षित लोग आज कल कौन हैं? यह सब अपर क्लास के ही लोग होते हैं जो आम तौर पर डाक्टर या इंजिनियर बनते हैं। इस का मतलब तो

यह हुआ कि इससे उन लोगों को ही मदद होगी जिनकी हालत पहले से ही अच्छी है। मैं इस बात को मानता हूं कि शिक्षित लोग बेरोजगार नही होने चाहिए, यह कोई अच्छा नही लगता कि शिक्षित बेरोजगार फिरते रहें। क्योंकि मुश्किल से दो या तीन प्रसैंट लोग ही ऐसी तामिल लेते हैं उन में भी अगर बेरोजगारी हो तो यह कोई शोभा नही देता। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि जो हायर इंकम वाले लोग हैं वहीं आमतौर पर इंजिनियर बनते हैं। राजस्थान सरकार ने यह स्कीम बनाई हुई है कि जो बी0 ए0 से उपर तालीम वाले शेड्यूलकास्ट को लोग अनएम्पलायड हैं उन को एम्पलायमैंट काउंसल दिया जाता है। क्या आप भी यहां पर करेगें जितने दसवीं से उपर तालीम वाले हैं, मैं केवल शेड्यूलकास्ट के लिए नही कहता, मैं तो कहता हूं कि जितने भी कम आमदन वाले लोग हैं जिन की हालत पसमांदा है उन सब को जो हायर तालिम हासिल करके बेकार बैठे हैं उनको राजस्थान सरकार की तरह हमारी सरकार को भी काउंसल देना चाहिए। जिन लोगों कि दस एकड से कम जमीन है उन के बच्चों को आप को रोजगार देना चाहिए। अगर आप इस पालिसी पर चलेंगे तभी समाजवाद आएगा। स्पीकर साहब, इरीगेशन और पी0 डबल्यु0 डी0 के महकमो मे एडहाक अप्वायमैंट होती है, उस में जो लडके शैड्यूल्उकास्ट के इंजीनियरिंग पास थे वह भी नही लिए गए और उनको यह कह कर टाल दिया कि एडहाक में रिजर्वेशन नही है। मैंने एक लडके के बारे में चीफ मिनीस्टर साहब को चिट्ठी भी लिखी थी वह लडका बेरोजगार है। पांच साल गवर्नमैंट से वजीफा लेकर इंजिनियरिंग पढा है लेकिन चीफ इंजीनियर साहब ने उसको अनफिट करार दे कर अप्वायंट नही किया।

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल): जिस लडके का यह जिक्र कर रहे हैं वह इंटरव्यू में एक सवाल का भी जवाब नही दे सका था। स्पीकर साहब, यह आप को भी मालूम है, यह बात आपके नोटिस में भी आई थीं। हम जो बिल्कूल नालायक हो उसको कैसे भर्ती कर ले।

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, वह तो डिग्री लेकर आया है। मैं चाहता हूं कि हाउस कमिशन मुकरर करे और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उसे फेस करें। मैं अपने वक्त की बात बताता हूं।

चौधरी बंसी लालः स्पीकर साहब इनका वक्त आया ही कब था?

चौधरी चांद रामः जब वक्त था तब ऐसी बातें नही होती थी।

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, आप मेरी तरफ मुखातिब हों।

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, जब यह बीच में बोल पडते हैं तो फिर तेजी आ ही जाती है। मैं इनको कुनीन दे रहा हूं, अगर उस खा लेंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे।

चौधरी बंसी लालः अफसोस की बात तो यह है कि यह खूद तो कुनीन सारी उमर नही खा पाए।

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब चीफ मिनिस्टर साहब में कुछ तो बर्दाशत करने का मादा होना चाहिए। आज वे समझते हैं कि उन के हाथ में ताकत है, उन के पास पुलिस है और उनका हर वर्ड कानून

बना हूआ है। लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि अगर शड्यूल्ड कास्ट्स के बारे में देखना चाहतें हैं तो

11.00 बजे

.....

चौधरी बंसी लालः दिल्ली के बारे में किसी प्रकार का रैफ्रेंस हरियाणा विधान सभा में नही आ सकता, इल लफ्जो़ को एक्सपंज करवा दिया जाए।

श्री अध्यक्षः जहां स्टेट सरकार की बात हो वही आप कह सकते हैं, दिल्ली वाली बात एक्सपंज की जाए।

.....

चौधरी चांद रामः .....

श्री अध्यक्षः आप किस डिमांड पर बोल रहे हैं?

चौधरी चांद रामः यह मांग नं0 38 है। (व्यवधान).....

.....(व्यवधान).....

चौधरी बंसी लालः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर।

चौधरी चांद रामः आप रुल देख लिजिए ताल्लुक है या नही, कोई चाहे कितना ही उंचा क्यों न हो .....(व्यवधान)। आप आगस्ट कुर्सी पर बैठे हैं और अगर कोई मैम्बर कोई मैमोरैंडम, जोकि

शडयूल्ड–कास्ट से ताल्लुक रखता हो या डिमांड के बारे में हो तो उसको सदन के पटल पर रखने की मेहरबानी करें.....

श्री अध्यक्षः जो बात रैलेबैंट नही होगी, प्रकरण में नही होगी वह मैं जरुर ऐक्सपंज करुंगा। आप डिमांड्ज पर बोलें, मैमोरैंडम की कोई बात नही है। अगर आप इररैलेवेंट बोलेंगे तो जरुर एक्सपंज करुंगा।

चौधरी चांद रामः राष्ट्रपति साहब कांस्टीच्यूशनल हैड हैं, सबसे बडे हैड हैं, यह रैलेवेंट कैसे नही हो सकता। उनकी बात करना कैसे रैलेवेंट नही हो सकता। कोई चीज स्टेट के हैड को ही दी जाती है तो उसके बारे में रैफ्रैंस करना इररैलेवैंट नही है। एक मैमोरेंडम स्टेट के आदमी दे रहे हैं वह कार्यवाही का हिस्सा कैसे नही बन सकता?

श्री अध्यक्षः आप डिमांड नम्बर बोलें। आप किस डिमांड पर बोल रहे हैं?

चौधरी चांद रामः डिमांड नम्बर 38 है, पेज नम्बर 11 और यह रुरल एम्पलायमैंट के बारे में है। मैंनें इस सिलसिले में एक मैमोरैंडम दिया है जिसमें सुझाव हैं। अगर आप इसको रैलेवैंट कर सकें तो ठीक है, अगर नही कर सकते तब भी ठीक है। आप मेहरबानी करके इन्हें कह दें कि इसको ले लें, मैं इसको यहां पर पढना नही चाहता इसलिए आप इसको ले लें। 21 साल से यहां पर ऐसी ही होता आया है और डिस्कशन का पार्ट बनता रहा।

वित्त मंत्री (श्री रामसरन चन्द मित्तल): चेयर की इजाजत के बगैर टेबल आफ दी हाउस पर कोई चीज नही रखी जाती..... (व्यवधान)।

श्री अध्यक्षः मैनें तो इसके बारे में अलाउ नही किया है..... (व्यवधान)

चौधरी चांद रामः चलो कोई बात नही, आप शक्तिमान हैं लेकिन याद रखिए, आज हम डेमोक्रैसी में एक ऐसे दौर से गुजर रहें हैं जिसमें एक तबका, एक वर्ग जिसके लिए हम कहते हैं कि हमने सैंट्रल गवर्नमैंट से 10 लाख रुपया मांगा है.....

श्री गिरीश चन्द्र जोशीः स्पीकर साहब, चौधरी चांद राम डिमांड्ज पर नही बोल रहे हैं। ऐसा करके वे एक तरफ हमारा वक्त और दूसरी तरफ हाउस का वक्त जाया कर रहे हैं.....(व्यवधान)।

चौधरी चांद रामः मैं डिमांड पर ही बोल रहा हूं। 56 हजार की मांग मांगी है कि बेरोजगारी को दूर किया जाए।

श्री अध्यक्षः ठीक है इस प्वायंट पर आप बोलें।

चौधरी चांद रामः इसी पर बोल रहा हूं। आप कहते हैं कि मैं कोई काग़ज सदन में नही दे सकता। मैं कोई कागज देता हूं तो कहते हैं कि ये कागज राष्ट्रपति जी के पास दें। मैं आपको इस बात पर रुलिंग चाहता हूं कि क्या इस डिमांड पर बोलते हुए मैं कोई कागज दे सकता हूं या नही?

श्री अध्यक्षः चेयर की इजाजत से यहां कागत रखे जा सकते हैं।

चौधरी चांद रामः एसे तो आपकी इजाजत से सारे ही काम करते हैं।

श्रीमति लेखवती जैनः स्पीकर साहब, चौधरी चांद राम जी चेयर को धमकी दे रह हैं, यह उचित नही है.....

चौधरी चांद रामः अगर मैं थोडी सी ऊंची आवाज में बोलता हूं तो यह धमकी नही है। ये शहर की रहने वाली हैं और मैं देहात का रहने वाला हूं। (व्यवधान) आप मुझे इजाजत दें क्योंकि आपकी इजाजत मुझे जरुरी है, आप मुझे कागज रखने की इजाजत दें।

श्री अध्यक्षः आप अपनी बात कहें, जो डिमांड चल रही है उसी पर बोलें।

चौधरी चांद रामः क्या आप इजाजत देंगे या नही देंगे।

श्री अध्यक्षः मैं इसको एग्जामिन कर लूं कि कैसे कागज टेबल पर रखे जाते हैं, आप अपनी बात कहें।

विकास मंत्री (श्री श्याम चंद): इनकी जबान ही मोटी नही है, अक्ल भी मोटी है। देर से समझ में आती है बात .....(व्यवधान)।

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, मैं गावों की बेरोजगारी का जिक्र कर रहा था। बेरोजगारी का नक्शा जो चौधरी अमर सिंह ने

खींचा है, उस पर मिनिस्टर साहब कहते हैं कि करनाल में शू–फैक्ट्री खोल दी है। इस एक फैक्ट्री से कुछ होने वाला नही, आप देखें करनाल शू–फैक्ट्री में कितने कारीगर लगायें हैं, कितनी कितनी तनखाह उनको मिलती है? वहां पर दस बारह आदमी एसे काम कर रहे हैं जो डेढ डेढ दो दो हजार रुपया तनखाह लेते हैं। वे लोग तनखाह देने के लिए लगाए गए हैं। उनके रोजगार मिल रहा है जो जूती का काम नही जानते, किसी काम को नही जानते, वे सुपरवाईजर लगे हुए हैं, उनको चमडे का कोई वाकफियत नही है, उन को पांच–पांच सौ, छः–छः सौ रुपया महीने का दिया जाता है। जो जूती का काम जानते हैं उनको पीस रेट पर काम दिया जाता है कि तुम अगर इतनी जूतीयां बनाओगे तो इतने पैसे दिए जाएंगे। यह काम भी उन लोगों को दिया जाता है जो महकमो की मारफत मिलेंगे जो महकमो की मारफत नही मिलेंगे उनको काम नही मिलेगा। आज हमारे हरिजन मिनिस्टर कहते फिरते हैं कि करनाल में जो फैक्ट्री है उसमें हरिजन रखते हैं। केवल इस बारह आदमी जो तीन सौ रुपये माहवार तनखाह पर रखे हुए है लेकिन जो एक्युअल चमडे का काम करने वाला है उनको रखा ही नही। इस देश में यही सबसे बडी कमी है। जो कुछ मेरे भाई श्री अमर सिंह जी ने कहा है वह काफी है, और ज्यादा कहने की जरुरत नही है। जहां तक मैं समझता हूं आज बेरोजगारी का कारण यह है कि जो गांव का दस्तकार है उसको काम नही मिलता क्योंकि उसका प्लास्टिक की चप्पलों ने बेकार कर दिया है। जमीन की जो भुख थी वह ट्रक्टरो के आने से, थ्रैशरो के आने से खत्म हो गई है। जो लोग खेतो में काम करके रोजगार हासिल करते थे उनको ट्रक्अरों और थ्रशरो ने

बेरोजगार कर दिया है। आज सरकार दस दस लाख रुपये से इस बेरोजगारी को खत्म करना चाहती है और लोग इसी की इंतजार में बैठे हैं मिट्टी खूदवाने वाला ठेकेदार आएगा और उन्हें काम मिलेगा। आज हम 25 सालों से चली आ रही ठेकेदारी को खत्म नही कर पाए हैं। सारा पब्लिक फंड सरकार का है तो इन बिचौलियों को रखने की क्या जरुरत है। आपने तो देख लिया, आठ कांग्रेसियों ने एक गज लम्बा इश्तिहार निकाल कर देख लिया.....(व्यवधान) दिल्ली में जाते हुए लोगों की बसें चैक होती हैं, उनको उतारते हैं, वे बेरोजगारी दूर करने के लिए और भुख मिटवाने के लिए जाते है। वे चाहते हैं कि जो वायदे किए गए थे वे पूरे किए जाएं। (विध्न) के वायदे पुरे करवाओ बजाय मेरे से लडने के। (शोर)

चौधरी बंसी लालः वे भूखे तो मरेंगे ही क्योंकि ये उनसे चन्दा इकट्ठा करते हैं।

चौधरी चांद रामः क्या बात करते हैं आप? आप तो एक जिम्मेदार आदमी हैं। आपको ऐसी बात नही करनी चाहिए।

श्री अध्यक्षः चौधरी चांद राम आप मुझसे मुखातिब होइए।

चौधरी चांद रामः मैं तो स्पीकर साहब चंडीगढ में गिरफतार होने के लिए आया था।

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, डिमांड्ज के अन्दर गिरफ्तारी का कोई जिक्र नही है।

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, ये चंदे की बात करते है।

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, मैं बिल्कुल समय नही दूंगा अगर आप रैलेवेंट नही रहेंगे।

चौधरी चांद रामः परन्तु स्पीकर साहब, मेरे लिए वे चंदे की बात क्यों कहें? चीफ मिनिस्टर साहब तो जिम्मेवार आदमी हैं। इनको इस तरह की बात नही करनी चाहिए। अपने आप तो ये डेढ डेढ लाख रुपये की माला लेते है, मगर मेरे लिए चंदे की बात करते हैं।

चौधरी बंसी लालः उसकी एक एक पाई का हिसाब, स्पीकर साहब, मैं देता हूं लेकिन इस भाई ने कभी एक आने का हिसाब नही दिया हरिजन भाईयों को चंदे का।

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, चंदे का जहां तक ताल्लुक है....

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, चंदे का डिमांड्ज मे काई जिक नही है, आप डिमांड्ज पर ही बोलिए।

चौधरी चांद रामः चंदे का जिक तो वे कर रहे हैं, मैं तो कर ही नही रहा हूं। आप उन्हे रोकिए। उनको तो सुनने की हिम्मत नही हैं। स्पीकर साहब, इसमें जिक किया गया डिमांड नं0 44 का। यह इंदिरा गांधी कैनाल, बी0 एन0 चकवर्ती कैनाल, वैस्टर्न जमुना औगमैंटेशन कैनाल की कंस्ट्रक्शन और लाइनिंग आफ हांसी ब्रांच के बारे में है।

Mr. Speaker: Please no interruption

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, कल मैनें एक सवाल किया था कि आवर्धन नहर में पानी कहां से आएगा? उसका ठीक–ठीक उत्तर मुझे नही मिला। स्पीकर साहब, किसी स्टेट की तरक्की दो बातों का प्रबंधन किया था। उनकी यह कोशिश थी कि बिजनी ज्यादा पैदा हो लेकिन यहां इस स्टेट का क्या हुआ। जो बिजली नंगल भांखडा की हमारे हिस्से में आई, उसे ही इन्होने तकसीम किया है। एक यूनिट भी बिजली का इन्होने पैदा नही किया। मैने एक नवम्बर का एडवरटाइज़मैंट देखा। उसमें लिखा था कि हरियाणा ने 6 साल के अन्दर यह कर दिया वह कर दिया लेकिन यदि फैक्चुअल पोजीशन देखें तो फरीदाबाद और पानीपत के थर्मल प्लांट्स जो हैं वे भी अब बने हैं। अब 6 साल के बाद इन्हे होश आई। अगर ये इन्हे पहले बना देते तो आज 6 साल के बाद कितनी तरक्की होती? कितने ट्यूबवैल को बिजली मिलती? आज क्यों नही हमारा टारैगट खाद्य पूर्ती का हुआ? इसलिए पुरा नही हुआ क्योंकि किसानो को बिजली नही दी गई। कोई प्लानिंग होनी चाहिए। करनाल और कुरुक्षेत्र जिलों में पानी की सख्त जरुरत थी वे पानी के लिए तडपते रहे। लोग कहते थे कि पैसा ले लो, रिश्वत भी ले लो लेकिन टयूबवैल का कनैक्शन दे दो, खाद के पैसे ले लो, इसमें भी रिश्वत भी ले लो लेकिन खाद दे दो। बीज भी वे बैल्क में खरीदने के लिए तैयार थे लेकिन उन्हे कोई भी चीज नही मिली। उन्होने कर्जा ले ले कर ट्रक्टर खरीदे थे और ट्यूबवैल लगाऐ थे लेकिन उनका कोई बिजली न होने की वजह से कोई फायदा नही हुआ। अब ये एक बिल और ला रहे हैं। उसमें लिखा है कि किसी नहर के दोनो तरफ 30–30

मीटर के बीच कोई कुआं नही लग सकेगा और अगर सरकार चाहे तो 30 मीटर से 100 मीटर तक की लिमिट भी वह रख सकती है।आज ये क्या करना चाहते हैं? मेरी समझ में नही आता। आज तक करनाल जिला बडी मात्रा में चावल और धान बेंचता था और कुरुक्षेत्र जिला गेहुं बेचता था मगर आज उसका क्या हाल है यह सभी को मालूम है। आज ये कहते हैं कि आर्वधन नहर बनाई है। इसके बारे में भी मैं स्पीकर साहब थोडा अर्ज कर देना चाहता हुं। इसके बारे में प्लानिंग कमीशन ने कहा था कि यह एक अनप्रोडक्टिव नहर है लेकिन उस अनप्रोडक्टिव नहर पर काम शुरु किया गया जो कि कोई गवर्नमैंट नही कर सकती। हमने 30–21 साल में ऐसा नही देखा कि एक योजना जिसके बारे में प्लानिंग कमीशन ने कहा हो कि नही होना चाहिए, फाईनेंस कमीशन ने पास न किया हो, गवर्नमैंट आफ इंडिया की अप्रूवल न हो, उसके बारे में स्टेट का चीफ मिनिस्टर कहे कि बननी चाहिए। ऐसी स्कीम पर, स्पीकर साहब, आप सुनकर हैरान होगें कि रात दिन काम चला और 60 हजार युनिट रोजाना खर्चा उस वक्त हुआ जब तमाम फसल को पकाई के वक्त इसकी जरुरत थी। यह कीमिनल बात नही तो क्या है? स्पीकर साहब आप जानते है कि सारे इलाके में पानी की कितनी जरुरत है? केवल गेहुं की फसल के लिए ही कम से कम पांच पानी की जरुरत होती है। क्या इनकी नहर में पांच पानी देने की क्षमता है। जब नही है तो इन्होने पानी क्यों छीना? आज जो करनाल और कुरुक्षेत्र का इलाका था वहां इसलिए टारगैट पूरा नही हुआ क्योंकि इन्होने उसे पूरा पानी नही दिया। हम पूछते है कि नहर पर इतना खर्चा क्यों हो रहा है? इसमें कितना पानी चलता है.....

श्री अध्यक्षः चौधरी चांद राम, आप रैपिटिशन न करें बल्कि अगला प्वायंट कहें।

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, इन्होने बडे फर्ख से कहा है कि सैंट्रल गवर्नमैंट हमें 7.48 करोड रुपया देने पर सहमत हो गई है लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वह कर्जा है ग्रांट नही है फयूचर जनरेशन पर। आज तीन सौ करोड रुपया स्टेट के उपर कर्जा है। वह हम देंगे, आने वाली पीढी देगी। वे कहते है ंकि वह हम माफ करवा लेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि स्पीकर साहब, कि कोई चीफ मिनिस्टर हमेशा के लिए नही बैठा रहता। किसी को यह बहम नही रहना चाहिए कि कोई चीफ मिनिस्टर हमेशा बैठा रहेगा। (विघ्न)

चौधरी मेहर चंदः स्पीकर साहब, आन ए प्वायंट आफ आर्डर मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरे मोहतरिम दोस्त ने यह जो कहा कि कोई चीफ मिनिस्टर हमेशा के लिए नही बैठा रहता यह कौन सी डिमांड पर बोल रहे हैं? हमें ऐसी इररैलेवैंसी नही चाहिए.....

श्री अध्यक्षः कृप्या आप बैठिए।

चौधरी चांद रामः आज मुख्य मंत्री चौधरी बंसी लाल का जिक नही है, आज हमारी सरकार के हैड का जिक है।

श्री अध्यक्षः चौधरी चांद राम आपको काफी समय देदिया गया है। अगर आप एक दो मिनट टू दी प्वयांट कुछ और कहना चाहते हैं तो कह लिजिए वरना किसी और को बोलने दिजिए।

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, हमारी सरकार ने औगमैंटेंशन ट्यूबवैल्ज, आवर्धन कुएं लगाकर लोगों को पानी दिया लेकिन हमारी स्टेट में काई डेम नही बनाया गया। इन्होने यह भी नही किया कि बीबीपुर झील की तरह पानी रोक करके कोई और झील बनाई हो। इन्होने जमीन के नीचे का पानी निकाला और कहा.....

श्री अध्यक्षः चौधरी चांद राम आप यह बात 10 बार दोहरा चुके हैं कि जमीन से पानी निकाला गया है।

चौधरी चांद रामः मैं इसलिए कह रहा हू जी कि.....

श्री अध्यक्षः आप कहिए खुशी से लेकिन एक बार कह लें।

चौधरी चांद रामः जनाब, आपको याद होगा कि कल मैंने राज्य मंत्री जी से सवाल किया था कि क्या जमींदारो के प्राईवेट ट्यूबवैल जो है उनको पूरा पानी मिलता रहेगाा?.....

श्री अध्यक्षः आपको उसका जवाब आ गया था।

चौधरी चांद रामः अब इनका एक और बिल आ रहा है।

श्री अध्यक्षः जब बिल आये तब बोल लेना।

चौधरी चांद रामः मैं एक सैकिंड में एक बात कह देता हूं।

श्री अध्यक्षः मैं दो मिनट और देता हूं। आप दो मिनट में जो बोलना चाहें बोल लें। (विघ्न)

एक सदस्यः इररैलवैंट भी? (विघ्न)

श्री अध्यक्षः मेरा तात्पर्य यह है कि डिमांड्ज के उपर जो आप बोलना चाहें विद्इन स्कोप वह आप दो मिनट में बोल लिजिए।

चौधरी चांद रामः तो स्पीकर साहब, मैं आपसे ही फेसला चाहता हूं एक तरफ तो सरकार कहती है कि हमने इंजीनियर्स की रायले ली है कि जमींदारों के टयूबवैल के पानी मे कमी नही आएगी दूसरी तरफ ये एक बिल ला रहे है। उसमें इन्होने खुद लिखा है कि यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है कि यदि जमींदारों के कुएं लग जाएगें तो सरकार के टयूबवैल जो हैं उनमें पानी कम हो जाएगा। सीपेज उसमें आ जाएगी। इन दोनो बातों में से कौन सी बात सही है।

एक और बात कहकर स्पीकर साहब मैं अपनी जगह ले लूंगा। पहले ये कहते रहे कि हमने हंडर्ड परसैंट लिंक रोडज़ बनाने हैं लेकिन अब कहते हैं कि 60 परसैंट विलेजिज को लिंक करना है। आज किसी गांव में जाकर देखिए वहां मैटीरियल की बहुत बुरी हालत है। कितना मैटिरियल वेस्ट हो रहा है इंटीरियर के अंदर जाकर अगर आप देखेंगे तो कहीं ईंटे बिखरी पडी हैं कहीं रोडा बिखरा पडा है। यही बस नही स्पीकर साहब, ज्यादातर इंजीनियर्ज कहते हैं कि सडक के उपर जब मिटटी डल जाए तो उस दबने के लिए बरसात चाहिए लेकिन यहां कुछ और ही हो रहा है। यहां मिटटी पड गई और कोई दबाई नही हुई उपर से रोडी डाल दी, थर्ड क्लास ईंट डाल दी। न कही पर सडको पर तारकोल पुरा है। क्या कोई इन्कवायरी करवाने के लिए

तैयार है? कोई तैयार नही है। मेरी इस बात में काफी वेट है लेकिन कोई सुनता ही नही। सडकें बनाने का सरकार का जो लक्ष्य है मैं उसे बुरा नही कहता। हर अखबार में एडवरटाईजमैंट दे देते हैं कि हम यह कर देंगे वह कर देंगे। किसी अखबार में अपोजीशन की बात नही निकलती है। इस तरह का इन्तजाम करना क्या ठीक है जो सरकार का वे मुलम्मा किया हुआ नक्शा है वही निकाल जाए। अखबारों में बही मुलम्मा निकाला जाता है और दूसरी कोई तस्वीर नही निकलेगी। यह डेमोर्कसी का तकाजा नही है, जो अपोजीशन की बात है, जो ओपोजीशन का रचनात्मक क्रिटिसिज्म हो वह भी आना चाहिए।

हरियाणा पहली नवम्बर सन् 1966 को बना। इस हरियाणा के बनाने में, अगर मैं गलती नही करता हूं तो हमारे मोजूदा चीफ मिनिस्टर का हाथ नही था। हमारे मौजूदा चीफ मिनिस्टर तो उसके खिलाफ थें। उस वक्त ये पार्लियामैंट के मैम्बर थें।

श्री अध्यक्षः यहां पर क्या जिक्र आप कर रहें है? यहां पर कोई विषय है इस बात का जो आप कह रहे हैं?

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारा हरियाणा जो सौतेली मां कहलाती है, उसके हाथ में है क्योंकि उस का बाप यह कहता है कि हरियाणा न बने। तो मैं समझता हूं कि हरियाणा तरक्की नही कर रहा है, डिवैल्पमैंट नही कर रहा है, हरियाणा बैकवर्ड है। हरियाणा पर आज कितना कर्जा है। कितनी ही

स्कीमें ऐसी हैं जिनके द्वारा आवर्धन नहरें बना कर सारे हरियाणा में फेला रहे है।

श्री अध्यक्षः आप तशरीफ रखिए। आपका समय हो गया है।

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब मै आपका शुक्रीया अदा करता हुं।

श्री गुलाब सिंह जैन (हिसार): स्पीकर साहब हाउस के सामने नो आइट्म्ज सप्लीमैंटरी डिमांड्ज की है जिनपर आज हाउस ने गौर करना है। मेरे से पहले अपेाजीशन के दो भाई बोले हैं। चौधरी अमर सिंह जी का जहां तक संबंध है उन्होने तो इन डिमांड्ज की तारीफ ही की है। उन्होने कुछ बातों की तरफ सरकार का ध्यान खिंचा है कि इन डिमान्ड्ज के लिए रुपये की कमी है इसलिए और ज्यादा रुपया होना चाहिए था। **(इस समय सभापजियों की सूची में से एक सदस्य चौधरी ईश्वर सिंह पदासीन हुए)** चेयरमैन साहब अगर इन डिमांड्ज को हम गौर से देखें तो एक बात अच्छी तरह समझ में आती है कि सरकार का मुद्दा है कि ज्यादा से ज्यादा रुपया हरियाणा की डिवैलैपमैंट पर खर्च हो। हरियाणा कृषि प्रधान देश है। यहां के लोगो का ज्यादातर कृषि का पेशा है। जिस पर हमारी तमाम की तमाम अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। इसलिए सबसे ज्यादा रुपया इन डिमांड्ज में इरीगेशन के लिए रखा गया है।इसके अलावा जैसा कि होता है कि डिवेल्पिंग स्टेटस की अनएम्पलायमैंट को खत्म किया जाए, हमें भी हरियाणा से अनएम्पलायमैंट दूर करनी है। ओपोजीशन भी यही चाहती है कि इस

पर ज्यादा रुपया खर्च हो और सरकार भी यही चाहती है। लेकिन खर्च तो उतना ही हो सकता है जितना हमारी परिस्थितियां हमें अलाउ करती है। यहां पर एक चीज पर बडा जो दिया गया है कि यह जो एजुकेटिड अनएम्पलायड के लिए स्कीम है इसमें लोअर दज्रे के लोगो को ज्यादा एम्पलायमैंट दी जाए। यहां पर कहा गया कि इस स्कीम में उनके लिए कोई प्रोविजन नही है। मैं माननीय सदस्यों को यह बतला दूं कि इंजीनियर्ज के लिए ही ऐसा नही है बाकि लोगों के लिए भी है। मुझे मालुम है कि यह जो 11000 अन–एम्पलायड लोगो को एम्पलायमैंट देनी है इसमें ज्यादा हिस्सा उन अन–एम्पलायड का है जो मैट्रिक तक की तालीम हासिल किए हुए है।

जहां तक हरिजनो के लिए रिजर्वेशन का संबंध है उसके बारे में भी मैं सदन के नोटिस में ला देना चाहता हूं। मैं भी उस कमेटी का मैंबर हूं जो हरिजनो के हकूक के बारे में देखती है। मैं कह सकता हूं कि वहां इस मामले पर बहुत अच्छी तरह से छानबीन कर रहे हैं कि जहां–जहां पर हरिजनो की पोस्ट्स खाली है उनको जल्दी से जल्दी भरा जाये। इस हाउस ने जो कमेटी बनाई है वह हरिजनो के हकूक के बारे में पूरी तरह से सतर्क है और उनपर गौर किया जा रहा है। मैं उनकी इस बात से एग्री नही करता कि हरिजनो को रिजर्वेशन पूरी नही मिलती। यहां पर यह जो कहा गया है कि सिर्फ एजुकटिड इंजीनियर्स के लिए ही यह रुपया मुकर्रर किया गया है वे सभी लोग हाई–अपस से आते हैं यानी अच्छे फेमिलीज के होते हैं ऐसी बात भी

नही हैं। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसबात को बार–बार दोहराया गया था।

जहां तक देहातो मे अन एम्पलायमैंट का ताल्लुक है उसको हमें दूर करना है। उसके लिए यहां हाउस में इंडस्ट्री के बारे में कुछ सुझाव आए है। मैं भी इस बारे में चंद शब्द कहना चाहुंगा कि हम इंडस्ट्रीज को सबसे पहले इंसेंटिव देते हैं और सरकार ने भी ऐसा ही किया हुआ है इसलिए इस प्रकार से स्कीमें बनाई जाए कि अपने देहातों को कैटेग्राइज़ करके जो इंडस्ट्रीज हैं वे फिक्स कर दें कि फलां कैटेगरी की इंडस्ट्री परटीकुलर विलज़ के साथ अटैच करनी है ताकि उस विलेज की अनएम्पलायड लेबर को काम मिल जाए। चेयरमैन साहब आपको मालुम है कि जब तक सरकार की तरफ से पुरा इंसैंटिव न हो तब तक हरियाणा में इंडस्ट्री पनप नही सकती इंडस्ट्री लगाने वाले या तो स्माल स्केल इंडस्ट्री में यकीन रखते हैं या मिडल स्केल इंडस्ट्री में। ये दोनो ही इंडस्ट्री ऐसी हैं जिसमें सरकार की इमदाद जरुरी है। इसलिए मेरा अर्ज है कि देहातो का सर्वे करके प्लानिंग करके कुछ करें तो मेरे ख्याल में दोनो बातें ही साथ साथ हो जाएंगी।

चेयरमैन साहब आपको मालुम होगा कि तमाम दुनिया में एक सवाल उठ रहा है इनवायरमैंटल पोल्युशन का। बडे बडे शहरों मे ज्यादा बडी बडी इंडस्ट्री लगाई जाती है लेकिन उधर उनको लेबर की प्रोब्लम आती है। इस वक्त फरिदाबाद में इंडस्ट्री ज्यादा लगाई जा रही हैं। हमारी एक और नई प्रोब्लम है कि बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री को इनसैंटिव दिया जाए। सदन के अन्दर बैकवर्ड एरिया में जहां रुरल का

जिक्र आया वहां यह भी आया कि रुरल प्रोजैक्ट अफसर नियुक्त किया जाए। इसकी तरफ अगर सरकार ध्यान दे तो मैं समझता हूं कि हमारे विलेजिज की अनएम्पलायमैंट को दूर करने में काफी ज्यादा कामयाबी मिल सकती है।

चेयरमैन साहब हरिजनो के लिए मकान का भी यहां चर्चा हुआ यह ठिक है कि यह रकम जो इस वक्त मुकर्रर है यह कम है लेकिन यह तो केवल एक हैंड के अंडर है। यह तो हमें सैन्टर से इम्दाद मिलनी है उससे ये मकान बनाने है लेकिन जो हमार हाउसिंग बोर्ड है, म्युनिसिपल बोर्ड है, इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट है यानी हमारी स्टेट में कितने ही ऐसे अदारे हैं वे ज्यादा से ज्यादा काम कर रहें हैं। उन सब की यही कोशिश है कि लो–इंकम ग्रुप के लोगों को हाउस प्रोवाइड किए जाएं। जब हम यहां हाउसिज प्रोवाइड करने की बात करते हैं तो नैचुरल है कि उसमें हरिजनो का फायदा जायेगा क्योंकि वे समाज के अंदर नीचे तबके के लोग हैं । मुझे हिसार का मालुम है इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट हिसार मकान बना रहा है। इसमें हमारा खास तौर से ऐम यह है कि ज्यादा से ज्यादा प्लाट्स थोडे पैसों में हरिजनो को दें। हम हर स्कीम में उनके लिए प्लाट्स अलाट कर रहे हैं, फिक्स कर रहें हैं बाकि के लोगों को जो भी हम प्लाट्स देंगे, जमीन देंगे वह आक्सन में देंगे।इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट हिसार ने खास तौर से फेसला किया है कि गरीबो से उनके प्लाठ्स को जो डिवैल्प करने की कॉस्ट आएगी वही ली जाएगी यानी कि नो प्रोफिट नो लोस पर जमीन दी जाएगी। म्युनिसिप्ल कमेटी हिसार ने भी सफाई कर्मचारियों के लिए मकान बनाने शुरु किए

हुए हैं। हमारी और भी म्युनिसिप्ल कमेटीज़ ऐसा कर रही है, इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट कर रहे हैं, हाउसिंग बोर्ड कर रहा है। सरकार की यह जनरल पालिसी है उसी पालिसी के तहत काम हो रहा है। इस बारे में तो मेरे ओपोजीशन के भाईयों ने कुछ नही कहा, उसकी तारीफ में कुछ तो बोलना चाहिए था।

चेयरमैन साहब यहां पर जूतो के कारखाने का जिक्र किया गया। खैर उसका तो मिनिस्टर साहब ही जवाब देंगे लेकिन फिर भी मैं यह अर्ज कर दूं कि यहां कहा गया था सुपरवाइजरी स्टाफ को 500–500 और 600–600 तन्खाह दी जाती है। मैं कहना चाहता हुं कि शायद मैम्बर साहिबान को मालुम नही है कि किसी इंडस्ट्री को चलाने के लिए सुपरवाइजरी स्टाफ की क्या अहमियत होती है। चेयरमैन साहब मुझे मालुम है कि कितने ही लोग स्टेट्स के अंदर लाइसैंस ले लेते हैं और कोटा भी ले लेते हैं लेकिन वे इंडस्ट्री को एस्टैबलिश नही कर सकते है। जब तक वे नो हाउ प्रोप्रली नही जाने तब तक कामयाब नही हो सकते। नौ हाउस इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अहम पार्ट है।

किसी इंडस्ट्री को ऐफेशिएन्अली चलाने के लिए हमें अच्छा सुपरवाईजर स्टाफ रखना पडेगा। अगर अच्छा सुपरवाईजरी स्टाफ नही होगा तो वह इंडस्ट्री पनपेगी नही। इसलिए मैं अर्ज करुगां आपके द्वारा उन मैम्बर साहेबान को कि उनको इस सुपरवाईजरी स्टाफ की अच्छी तन्खाह के बारे में कोई एतराज नही होना चाहिए। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि उसमें कितने आदमी रखें हैं और कितने नही रखें हैं, इस बात का तो पता उन्ही को होगा कि वाकई वहां थोडे

आदमी रखे है या नही। इसका जवाब तो उनको ही मालुम होगा। मुझे तो इंडस्ट्री चलाने के बारे में मालुम है, वहां पर स्टाफ कितना है, इसका पता मुझे नही। मैने तो यह बात एक प्रिन्सीपल के तौर पर कही है।

इरीगेशन पर बोलते हुए एक बात सदन के सामने रखी गई कि जो नहरे बनाई जा रही है उनमें पानी कहां से आएगा। कल सदन के सामने इस प्रकार का एक सवाल भी आया था। सरकार ने उसका उत्तर भी दिया कि उन नहरो में पानी फलड वाटर का दे रहे हैं। जब यह बताया गया कि हमारे यहां पानी काफी है तब यह भी बताया गया कि हम जितना पानी नहरो को दे रहे हैं हमारे पास उससे भी बहुत ज्यादा पानी है। पहले भी मैने बजट के टाईम पर एक बात कही थी और आज फिर कहना चाहता हूं पानी को देहातो में खेतो तक ले जाने के लिए पहले खालें बनाने की जरुरत है। नहरें बहुत जरुरी हैं अगर हम नहरें नही बनाएंगे तो हमे अपने हिस्से का पुरा पानी नही मिल पाएगा। पंजाब कहेगा कि आप पानी ले जा सकते है लेकिन जब हमारे पास पानी लाने के साधन नही होगें तो हम कैसे लेंगे? चेयरमैन साहब जिस वक्त सन् 1947 में देश आजाद हुआ था और उसके बाद पंजाब का और हमार बंटवारा हुआ तो हमें पानी मिला लेकिन उस पानी को हमें मजबूरन पंजाब को देना पडा क्योंकि उस पानी को इस्तेमाल करने के हमने साधन नही बनाए थे। हमने उसके लिए नहरें मुकम्मल नही की थी। हम उस पानी को ला नही सकते थे। इसलिए यह देखना की कौन सी चीज जरुरी हे वाजिब है। नहरें बनाना बहुत जरुरी है। आज हमारी

हरियाणा सरकार जो कुछ कर रही है जो हम नहरो का जाल बिछा रहे हैं वह न केवल इस बात को देखते हुए कि इससे लोगों को पानी मिले बल्कि इससे आगे भी पानी का इस्तेमाल करने में आसानी हो जाएगी। इसके साथ ही साथ यहां पर हाउस के सामने कुछ लोगों ने यह बात कही कि आगमैंटेंशन टयूबवैल्ज़ के जरिए जो ये पानी डाल रहे हैं इसमे जमीन का पानी कम हो जाएगा मुझे इस बात का अफसोस है कि जिस बात को सरकार कहती है करती है, इन भाईयों को सकी कन्ट्राडिक्शन करने की जरुरत नही होती। जैसे एक कहावत है कि नाच न जाने आंगन टेढा, वही हाल इनका है। असल बात यह है कि इन ओपोजिशन के भाईयों के पास इस डिमांडज के बारे में कहने के लिए, किटीसिज्म करने के लिए काई बात है नही। अभी पिछले दिनों कि ही बात है कि एक ओपोजिशन के भाई से मेरी बात हो रही थीं, कहने लगे क्या करें, आखिर हम ओपोजिशन वाले कुछ तो कहें। तो यह जो कुछ कह रहे हैं वह कुछ कहने के नाते से ही कह रहें हैं वरना साफ तौर पर सरकार की तरफ से यह बतलाया गया है कि हमने इंजीनियर्ज से और अफसरो से अच्छी तरह से कन्सल्ट किया है कि हमारे यहां सब सॉयल वाटर कितने मिलियन एकड है और उसकी वजह से जो हम डीप ट्यूबवैल लगा करके, आगमैंटेशन कैनाल में पानी डालने जा रहे हैं उसके कारण करनाल जिले में या कुरुक्षेत्र जिले में पानी की कमी होने वाली नही है। यह बात सरकार ने यहां साफ तौर पर बताई है लेकिन इस सब के बावजूद हमारे ओपोजिशन के भाईयों को तसल्ली नही होती। (चौधरी चांद राम की ओर से व्यवधान) बिल जब आएगा तो बिल पर बोल लेंगे बोलना तो आपका भी काम है और मेरा भी काम है। मेरे में और आप

में थोडा सा फर्क है कि आप ऐजीटेशन करते हैं मैं ऐजीटेशन नही करता।

श्री अमर सिंहः तो आप ऐजिटेशन करवाते हैं।

श्री गुलाब सिंह जैनः मैं वह भी नही करता। इसलिए यह कहना कि नहरों में पानी कहां से आएगा, वाजिब नही है। मैं यह चाहुंगा कि मेरे मोहतरिम दोस्त मेरे साथ भिवानी के इलाके में चलें। उन्होने कहा कि पांच पानी के बगैर फसल नही होती, लेकिन मैं कहता हुं कि हमारे वहां तो एक पानी चाहिए जिससे की बिजाई हो जाए। फिर कुछ कुदरत का पानी हो जाए तो उससे भुसा वगैरह भी हो जाए तो उन लोगों के लिए कुछ गुजारा करने लायक बात बन जाती है। (व्यवधान) आप एग्रीकल्चर के बारे में जानते नही हैं आप देहाती नही है। आप रहते तो चंडीगढ में है और बात देहात की करते हैं।

सहकारिता एवं सीानीय स्वशासन राज्य मंत्री (चौधरी गोवर्घन दास चौहान): वे तो खुद कहते थे कि मैं 21 साल से यहां हूं।

श्री गुलाब सिंह जैनः मेरा कहना है कि अगर आप हकीकत देखनपा चाहते है तो जिन इलाको में नहरें चली गई हैं, आप वहां जाकर देखें। (व्यवधान) दौलता साहबा, पहले जाट और बनिए ही बोला करते थे, बडी मुश्किल से गांधी जी ने इनको बोलने का मौका दिया है, बोलने दिजिए। (व्यवधान) चेयरमैन साहब, आज कोई भी मैम्बर अगर इरीगेशन के खिलाफ कुछ बोलता है तो मैं यह समझता हूं कि वह हरियाणा की तरक्की के खिलाफ बोलता है। हरियाणा की जो जनता है

उसके इंटरैस्ट के खिलाफ बोलता है। चेयरमैन साहब, जैसा कि मैंन कहा, अगर इरिगेशन की हरियाणा में तरक्की नही होती, हमारे पास इंडस्ट्री के लिए माल नही होता और अगर बिलजी हम ज्यादा पैदा करने की कोशिश नही करते, तो हरियाणा आगे नही बढ पाएगा। एक चीज यह कही गई कि हमें जो 40 प्रतिशत बिजली मिली थी, हम वही डिस्ट्रीब्युट कर रहे हैं। और उसके अलावा हमने कोई बिजली पैदा नही की। अगर मैं आपको बता दूं तो यह काई गलत बात नही होगी कि बिजली पैदा करने के लिए हम नई स्कीमें बना रहे हैं। ठीक है, उसमें टाईम तो लगता है लेकिन सबसे पहले जो हमारे साथी ज्वायंट पंजाब के वक्त से हैं और इस बारे में कह रहे थे, उन्होने कभी इस बारे में कोशिश नही की कि हमारा बिजली का पूरा हिस्सा हरियाणा प्रांत में इस्तेमाल हो जाए। (व्यवधान) चेयरमैन साहब, मैं मैंम्बर साहिब से मुआइबाना अर्ज करुंगा कि जब वह बोल रहे थे तो मैने बीच में एक शब्द भी नही कहा। जिनके बोलने में मैंने इन्ट्रपशन की हो, अगर वे बोलें तो मुझे कोई एतराज नही होगा। He is an old parlimentarian. I am a new legislator and he should know that when a member is on his legs, he is not to be interrupted. I have never interrupted anybody. I should not be interruped.

चेयरमैन साहब, मेरे में तो पर्सनल बात कहने की जुर्रत नही और फिर बनिया हूं। जरा डर कर ही बात करता हूं। अर्ज यह है कि आखिर, जुम्मे जुम्मे नो रोज, हरियाणा बने टाईम ही कितना हुआ है। इनको यह पता होना चाहिए कि हमारे पास बिजली पेदा करने के सिर्फ तीन ही साधन होते हैं। एक हाईडल, दूसरी थर्मल और तीसरी डीज़ल।

हाईडल बिजनी को बनाने में और स्कीम वगैरा बनाने में और बिजली पैदा करने में 15–20 साल लग जाते हैं। और फिर हरियाणा के पास तो अपने साधन भी नही हैं। उसको तो उनके लिए पडोसी स्ट्टस पर डिपैंड करना पडता है। उसके लिए जब तक सैंटर इन्टरवीन नही करेगा, तब तक कुछ काम होना मुमिकन नही है। थर्मल प्लांट बनने के लिए भी 5–6 साल से कम लगना संभव नही। जब हरियाणा बना तब उसके तुरंत बाद डेढ साल का अरसा किन हालात में गुजरा, मैं उसकी चर्चा नही करना चाहता। वह बडा दुखद समय है उसके बारे में मैं कुछ भी नही कहना चाहता। जो लोग उस वक्त की सरकार में थे, शायद दुख उनको भी हो कि कुछ नही कर पाए। उसके बाद मौजुदा गवर्नमैंट वजूद में आई, मेरा कहने का मतलब यह है कि उसके बाद चौधरी बंसी लाल की हकूमत वजूद में आयी। उस वक्त से लेकर आज तक के आंकडे देखें। मैं खुश होता अगर मैम्बर साहेबान बोलते हुए कुछ फैक्टस एण्ड फिगर्ज की भी ख्याल रखते। एक बात को कह देना बहुत आसान है अगर वही बात आंकडे देखकर कहते तो उनकी बात में वनज होता। मैंने आंकडे देखें हैं और उसके मुताबिक मैं पूरी रिसपौंसिबिल्टी से यह कह सकता हूं कि बिजली के मामले में हमारी सरकार बिल्कुल सतर्क हैं। हरियाणा के अंदर बिजली की डिमांड अधिक हुई और वह इसलिए हुई क्योंकि हरियाणा ने आज राउंड तरक्की की। हमारी एग्रीकल्चर के लिए बिजली की मांग बढी और हमारी डोमैस्टिक कंजम्पशन बढी। मैं पिछले दिनो एक लिट्रेचर पढ रहा था उसमें यह लिखा था कि किसी स्टेट या किसी कंट्री के बारे में आपने यह देखना हो कि उसमें कितनी डिवैलपमैंट हुई है तो पहले यह देखिये कि उसमें

बिजली की डिमांड कितनी बढी है। अगर हम इस थर्मामीटर के मुताबिक देखें तो मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि हम इस पर खरे उतरते है। ओपाजीशन के भाई यह कहते है कि जितनी डिमांड है उतनी पैदावार नही। लेकिन सरकार इस बारे में ऐफर्टस कर रही है। वे यह तो देखें कि हम स्कीमें बना रहे है या नही। हमारे ओपोजीशन के भाई मानेंगे, सब लोगा यह मानेंगे कि हमारी सरकार बिल्कुल सतर्क है। हमारा बिजली बोर्ड उसमें लगा हुआ है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि हरियाणा की तरक्की से या जो लोग चौधरी बंसी लाल से जलते हैं, वे लोग बजाया इस बात के की सरकार के हाथ मजबूत करें, बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को ही बहकाते रहते है। चेयरमैन साहब, इसलिए हम लोगों को सरकार का साथ देना चाहिए ताकि यह जो बिना वजह स्ट्राइक होती है और उसके कारण बिजली की पैदावार में कमी आती है वह कमी न आए। हम बिजली की पैदावार तेजी से बढाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि उसकी स्पीड में कमी न हो ताकि हमारी स्टेट की मुकम्मल तरक्की होती रहे।

सडको के बारे में एक बडी मजेदार बात कही गई कि सरकार ने कहा था कि वह सौ फिसदी सडकें बनाएगी। लेकिन अब वह साठ फिसदी सडके बना रही है। मैं अपने साथियों को बताना चाहता हूं कि इसी सदन में मुख्य मंत्री महोदय ने इसकर रीजन दिया था। उन्होने कहा था कि हमने यह महसूस किया कि सडको की बजाय नहरें ज्यादा जरुरी है। जब तक सुखे खेतों में पानी नही देंगे तब तक खेतो में पैदावार नही बढेगी, और जब तक पैदावार नही बढेगी तो हमारा व्यापार

नही बढेगा, इंडस्ट्री नही बढेगी और इस प्रकार हमारी स्टेट की डिवलैप्मैंट रुक जाएगी। अगर हमने जो पैसा पांच साल में खर्च करना था वो चार साल में खर्च कर दिया तो इसमें हर्ज क्या है। अब देखना यह है कि दूसरे प्रदेशो में सडकों की क्या तरक्की है? चेयरमैन साहब इस बारे में मेरी गुजारिश यह है कि अगर दूसरे प्रदेशो के आंकडे देखें तो सडको की प्रगति कहीं दस प्रतिशत है, जब हम हरियाणा से बाहर जाएं तो हरियाणा की कितनी तारीफ होती है कितनी सराहना होती है कि जो भाई मेरे दाई तरफ बैठे हैंउनके सर जी फर्ख से उठ जाते हैं। आज आप हरियाणा से बाहर चले जाए हर जगह पर यहां की सडको की डिवैलपमैंट की, यहां की बसों की तारीफ सूनने को मिलेगी।

कुछ भाईयों ने मसुरी के रैस्ट हाउस की बात कही। अगर देखा जाए तो अजीब सी बात नजर आती है। जो लोग हरियाणा के बाहर से यहां आते हैं आखिरकार वे हर गावं में नही जाते हैं। वे सबसे पहले सडको पर आते हैं, तो उनके ठहरने के लिए जगह चाहिए। कुछ दिन पहले इसी सदन में हरियाणा में जो रैस्ट हाउसीज बन रहे हैं कुछ भाईयों ने उसका क्रीटिसिज्म किया था। अगर मसूरी में रैस्ट हाउस बन जाता है तो हर्ज क्या है। यह तो है नही कि उसमें बडे आदमी ही ठहरेंगे, उसमे तो हरियाणा का कोई भी आदमी ठहर सकता है। जो लोग पहाड घुमने जाएं, हिमालय को देखने जाएं वे वहां ठहर सकते हैं। घूमना यानी ठूरिज्म भी एक एजुकेशन है (व्यवधान)। चेयरमैन साहब, इस सप्लीमैंटरी डिमांड में काई ऐसी मद नही है जिसमें क्रीटिसिज्म की गुंजाइश हो।अगर कुछ नुक्ताचीनी हो सकती है तो वह

सिर्फ इतनी कि जहां दस हजार रुपया मांगा गया है वहां पचास हजार दिया जाना चाहिए। जहां एक लाख मांगा गया है वहां दस लाख दिया जाना चाहिए। और हमें ज्यादा से ज्यादा डिवैलपमैंट स्कीमज् पर खर्च करना चाहिए। लेकिन एक कहावत है कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फेलाने चाहिए। हमारे मुख्य मंत्री जी एक देहाती भी हैं, एक जमींदार भी और एक बनिए भी। वे अच्छी तरह समझते है कि कहां खर्च किया जाना चाहिए। चेयरमैन साहब एक बात और कही गई कि साहब कर्जा लिया जा रहा है आने वाली पीढियों पर बोझ डाला जा रहा है। मै बताना चाहता हुं कि आज जो इंडस्ट्री लग रही है अगर आप उनका प्रोसैपैक्टस देखें तो पता लगेगा कि 80 प्रतिश्त कर्जा लेकर ही लग रह हैं। जो इंडस्ट्रीयलिस्टर्ज़ हैं और जो छोटा शेयर होल्डर है वह जानता है कि इंडस्ट्री प्रोडिक्टव है। और जिस कर्जे से यह बनाई जा रही है वह उतर जाएगा और मुनाफा भी मिलेगाा। आज हमारे सामने फैक्टज़ एंड फिगर्ज़ हैं । हमारी स्टेट तो छोटी सी स्टेट है लेकिन जो लोग प्लानिंग कमीशन में और सैनट्रैल गवर्नमैंट में बैठे हैं वे कम दिमागा वाले नही है। उन्होने काफी सोच विचार के बाद हमारी स्कीम को मंजूर किया है। हमारे इंजीनियरों ने जो स्कीम दी वह उनके दिमागा में ही नही आती थी। इस स्कीम के बारे में सोचते भी नही थे। वे कहते थे कि यह कैसे मुमकिन हो सकता है। लेकिन दिल्ली में जो इंजीनियर बैठे हैं, जो प्लानिंग कमिशन के मैम्बर बैठे हैं उन्होने हमारी बात को माना और यह अमाउंट सैक्शन किया। आने वाली पीढीयां तो इस सरकार को दुंआएं देंगी। यह तो आम का पेड है। (व्यवधान) चेयरमैन साहब जब हम स्कूल में पढा करते थे तो एक कहानी आती थी कि एक

बूढा आदमी आम का पेड लगा रहा था। उसकी उम्र 70–80साल थी। किसी ने पूछा कि यह आम कितने दिन बाद फल देने लगेगाा तो उस बुढे ने कहा बीस साल बाद। उसको कहा गया कि तुम्हे इसका क्या फायदा होगा तो उसने कहा कि हम नही खा पांएगें तो हमारे बच्चे तो खएंगे। तो इस प्रकार हम यह आम का पेड लगा रहे है और इन योजनाओ का फायदा हमारी आने वाली पीढी उठाएगीं।

श्री अमर सिंहः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, क्या हमारे मुख्य मंत्री अस्सी वर्ष के हैं?

श्री सभापतिः यह प्वायंट आफ आर्डर नही है।

श्री गुलाब सिंह जैनः मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे साथी इस तरह की फिजूल बातें न करें। इस तरह की बातें हमको भी करनी आती है। मैं तो एक वकील हूं आप दस दफा भी टोक लें मैं अपने रास्ते से नही हटूंगा।

चेयरमैन साहब, तो मैं अर्ज करुंगा कि ये लोग कहते हैं कि यूं ही पैसा वेस्ट किया जा रहा है। मैं इनको यह बता देना चाहता हूं कि यह सारे का सारा रुपया प्रोडक्शन के कामों पर, डिवैलपमैंट के कामों पर खर्च किया जा रहा है। कहीं पर रेल लाईन के लिए, कहीं पर अन–एम्पलायमैंट को दूर करने के लिए और कहीं इंडस्ट्रीज को बढावा देने के लिए, तो कहीं पर नहरे खोदने के लिए। ये सारी की सारी प्रपरफुल वर्क हैं और प्रपजफुल प्रपज के लिए है। हम सब सरकार को बधाई देते हैं कि वह किस तरह सोच समझ कर सरकारी खजाने से

खर्च कर रही है। जैसा कि आदमी एक–एक पानी के कतरे को देख कर इस्तेमाल करता है उसी प्रकार आज एक–एक पैसा को देखकर सरकार खर्च कर रही है। अगर यह कहा जाए कि इन कामों के लिए यह पैसा कम है, इसके लिए और पैसा चाहिए तो मैं इससे सहमत हूं, मैं भी सरका से इस बारे में कहूंगा कि मैं भी एसे लोगों का हाथ बंटाने के लिए तैयार हूं जो कहते हैं कि रिर्सोसिज मुहैया कराए जाएं ताकि हरियाणा और ज्यादा तरक्की करे। हम और सौ साल इंतजार नही कर सकते। मैंने एक दफा इस सदन में बताते हुए कहा था कि justice delayed is justice denied इसी तरीके से हमने जो तरक्की करनी है अगर उस में देरी हो जाए तो वह तरक्की तरक्की नही रह जाती।

चेयरमैन साहब, यहां एक बात और भी कही गई कि सडकों पर मैटीरियल वेस्ट पडा है। यह बातें तो हाउस में कहने वाली नही है। जब सडकें बन रही होती हैं उस समय सरकार के नोटिस में लाएं तो फिर हम भी उन भाईयों का साथ देंगे। क्योंकि हम नही चाहते, ट्रेजरी बैचिज वाले नही चाहते, ओपाजीशन वाले भी नही चाहेंगे कि हरियाणा के जो टैक्स पेयर हैं, जो उनके खुन पसीने का रुपया है उस में से एक पैसा भी गलत इस्तेमाल हो, इस बात के लिए मैं उनके साथ हुं। I will be one with them सैशन के बाहर भी कई बार आपस में मुलाकातें होती हैं। इससे पहले हमारे नोटिस में यह बात कभी नही लाई गई। अगर ऐसी और कोई बात नोटिस में हो तो उसे सरकार के सामने जरुर लाएं, मैं उनका साथ देने के लिए तैयार हूं। जहां पर मैटीरियल

खराब हो, ठेकेदार गलत काम करते हो, हम किसी गलत आदमी को स्पोर्ट करने को तैयार नही है। किसी बडे छोटे का इस मामले में ख्याल नही किया जाएगा और चौधरी बंसी लाल जी इस बात के लिए मशहुर हैं कि बिना लिहाज वे किसी को बर्दाश्त नही करते। किसी गलत बात को, अपने किसी नजदीक से नजदीक दोस्त को भी बर्दाश्त नही करते। इसलिए मैं समझता हूं कि कुछ बातें सदन मे कहने मात्र की कही गई हैं। और ये कहने की बातें नही हैं हकीकत हैं, देखने वाले ही कहते हैं कि They are speaking against their conscience लेकिन दिल में वे जानते हैं कि हरियाणा तरक्की कर रहा है। क्योंकि वे अपोजीशन के बैचिज पर बैठे है इसलिए वे अपना कर्तव्य समझते है कि सरकार की नितियों के खिलाफ, इन डिमांडज के ख्लिाफ कुछ तो कहना है। इन बातों के साथ मै इन मांगी गई डिमांडज् की हिमायत करता हूं और सदन से यह अपील करता हूं कि इन डिमांडज् को पास कर दिया जाए।

चौधरी प्रताप सिंह दौलता (बेरी): चेयरमैन साहब, मुझे इस बात से बिल्कुल इत्तफाक है कि हरियाणा में डिवलैपमैंट हुई है और जब मैं यह बात समझता हूं तो कुछ भाई यह महसुस करते हैं कि मैं जरुरत से ज्यादा किसी को राजी करने की बात कहता हूं। भई सीधी बात है, जहां तक डिवैलपमैंट का ताल्लुक है हरियाणा एज़ ए होल बहुत डिवैल्प हुआ। मुझे इस बात पर ऐतराज नही कि हरियाण की डिवैलपमैंट में कमी है, मुझे यह एतराज है कि डिवैलप्मैंट के साथ एक बडी गलत चीज डिवैल्प हुई है हरियाणा में जो डेमोक्रेसी को ले

बैठेगी। आप डिवैल्प करते है नक्शा देखकर, इंजीनियर की रिकमन्डेशन से डिवैलपमैंट किजिए लेकिन आप डिवैलपमैंट करते हैं एम0 एल0 एज0 का चेहरा देखकर, जब एम0 एल0 ए0 नापसंद आदमी हो तो उसके हल्के में काई पैसा भी खर्चना हो तो नही खर्चगें। यह डिवलपमैंट काहे कि यह तो करप्शन है। मै डंके की चोट से , और दावे से कहता हूं, चेयरमैन साहब, अगर काई महकमा, तालीम का महकमा, नहर का, पी0 डबल्यु0 डी0 का यह कह दे कि मेरे हलके में चार पैसे खर्च हुए हैं आठ साल में हरियाणा बनने के बाद या यह कह दे कि जो सडके पहले की बनी हुई थी वह सारी टूट चुकी है और अब मरम्मत नही हो रही उनकी, तो बिल्कुल गलत बात नही होगी। उस डिवेलैपमैंअ के साथ पोलिटिक्ल शर्त लगा दी जाए कि अगर यह कांस्टीचुएन्सी फलां चेहरे वाले आदमी को पसंद करेगी, चुनेगी तब तो डिवलैपमैंट होगी अगर वह अगर वह नही चुना तो देख लेना कि खेत सूखे रहेगें। यह डिवलैपमैंट नही है, डिवलैपमैंट के साथ कुरप्शन और डेमोक्टिक वैल्यु को कत्ल करने का बद्तरीन तरीका है, जो हमें एवायड करना चाहिए। मैं अर्ज किए देता हूं कि जहां तक इरीगेशन की डिवलैपमैंट का ताल्लुक है चेयरमैन साहब मुझे बडी खुशी है कि सरकी मुलाजमों पर खर्च होने के बाद, इस गवर्नमैंट को आप बंसी लाल जी की गवर्नमैंअ कह लिजिए, इंदिरा जी की गवर्नमैंट कह लिजिए, क्योंकि वोट तो इंदिरा जी के नाम पर ही मिली थी। इरीगेशन पर ज्यादा खर्च किया है। बंसी लाल जी बेहतरीन मैनेजर हैं और इस बात से काई यह इंकार करे और कहे कि इनकी गलती है और आप जरुरत से ज्यादा इस बातको उडां तो इनका दिमाग खराब करने की बात है। यह तो हकीकत है कि बंसी लाल जी

ने एक स्टैंडर्ड कायम किया है और काई दूसरी स्टेटस ऐसा कर सके तो मुझे बडी खुशी होगी। इस इरीगेशन में भी बिल्कुल यह बात है। सरकार खर्च के बाद जो बजट का हिस्सा हरियाणा में खर्च हुआ है उसमें इरीगेशन की सबसे अहम पोजीशन है। चौधरी चांद राम जी को यह शिकायत है कि करनाल के पेट का पानी क्यों निकाल रहें हैं। अगर यह चीज है कि करनाल जिले में पानी बहुत ज्यादा है और अगर यह भी ठीक है कि हरियाणा के ही तहसील झज्जर में, जो चौधरी चांद राम जी की तहसील है, उस में पानी की कमी है, भिवानी में पानी की कमी है तो एक आदमी के पेट से भी निकल जाए, एक जिले की धरती से भी निकल जाए और आगे पहुंच जाए तो उस में डिवलैपमैंट में कहां गलती हुई? यह बात कि करनाल सूख जाएगा, करनाल के मैम्बर इस बात को बडी अच्छी प्रकार से समझते है, उनको काई शिकायत नही है। यह सूख जाएगा चौधरी चांद राम जी आप तो अपने जिले में वापिस आ जाइए। करनाल वालो को करनाल वालो को सपुर्द कर दें...। .....शोर.. ..... चेयरमैन साहब, रोडज़ के बारे में मेरी अर्ज यह है, पी0 डबल्यु0 डी0 मिनिस्टर साहब बैठे हैं, मुझे बडी खुशी है, वह जरा चैक करले कि क्या बात है कि जमींदारो की जमीन पी0 डबल्यु0 डी0 लेता है, उनको एक नोटिस दे करके 5–5 और 6–6 साल तक बैठ जाते हैं और उनको इतनी देर तक कम्पनसेशन अदा करने का नाम तक नही लेते चाहे वह जमींदार कितना ही जोर क्यों न लगा लें। मै इनको इन्सटांट देता हूं इसको जनरलाइज कर लिजिए। बतरा साहब ने एक सडक बनवाई कलानौर के हल्के में, लाहली से जो मेरा गांव है, उस में मेरी जमीन भी है और मैं रोज जाकर पी0 डबल्यु0 डी0 वालो को सलाम कर आता

हूं, भई पैसे दे दो। मेरी सलाम के बावजूद, मेरे याद दिलाने के बावजूद मुझे पांच वर्ष तक उस जमीन के पैसे न मिलें तो बाकी जो सादे किसान होते हैं, उन बेचारों को कोन पैसे देता होगा, कितनी दे में देता होगा, मैं मिनिस्टर साहब के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं।

चेयरमैन साहब, दूसरी चीज यह है कि पी0 डबल्यु0 डी0 वाले जब रोडज़ बनाते हैं सडक बनती है तो जमींदारों की जमीन को जो सडक के साथ–साथ होती है बडी बेदर्दी के साथ खोदे चले जाते हैं। ठेकेदार इस खुदाई में मिट्टी डालने के अलग से पैसे लेता है लेकिन उसको पी0 डबल्यु0 डी0 वाले खुदवाई की कोई जिम्मेवारी नही लेते, चुनाचे सडक के किनारे–किनारे किसानो की आध–आध बीघा जमीन इतनी खराब हो जाती है कि उन बेचारों को उसे डेवलैप करने में बडी देर लगती है। तीसरी बात मैं सडको के बारे में यह कहना चाहता हूं कि जहां तक बेरी के हल्के की बात है, मैं फिर याद दिला देता हूं। कानौर से लेकर चिमनी तक एक सडक बनी हुई है, चेयरमैन साहब, आप के जरिए मै पी0 डबलयु0 डी0 मिनिस्टर साहब, को याद दिला दूं कि वह सडक 50 साल तो नही 43–44 साल पुरानी जरुर है। आज जब से हरियाणा बना है उससे पहले उसकी खुब मरम्मत भी हुआ करती थी सब कुछ हुआ करता था। अब वह टूट कर रेत बन चुकी है। जोर लगा चुके लेकिन वह नही बनती। एक और गावं हैं ढिराना, ढिराना से लेकर चिमनी तक ईंटे आपकी बिछि हुई हैं, कंकर आपकी पडी हुई हैं, लोग उठा रहें हैं, कम से कम उस सडक को ही कम्पलीट

कर दें। इस तरह तीन चार सडकें और हैं जो 8 साल पहले कभी बन रही थी और वह अधूरी पडी है। उनको कम्पलीट किया जाए तो डिवलैपमैंट उस हलके में भी हो सकती है। आखिर बेरी के हलके का कसूर यही है कि वहां शेरसिंह पैदा हुआ, जो पहले सैंटर का मिनिस्टर बना, भगवतदयाल पैदा हुआ जो, पहला हरियाणा का चीफ मिनिस्टर बना। दौलता पैदा हुआ जो सबसे पहले शमाली हिंदुस्तान की टिकट लेकर कांग्रेस को हरा कर सैंटर में गया। वहां ब्रिगेडियर रणसिंह भी हैं, सारे ही एसे चेहरे हैं जो सी0 एम0 साहब को पसंद नही तो वहां के लोगों को क्यों सजा दी जा रही है। यह काई डेमोक्रेटिक वे आफ लाईफ है? एक पैसा उस हलके में खर्च न हो क्योंकि वहां लीडर इस टाइप के हैं जो बंसी लाल जी को पसंद नही तो यह जमहूरियत का तरीका नही। बंसी लाल जी का डायनैमिक वे आफ वर्किंग तो हमें पसंद है। हम डंके की चोट पर कहते हैं, हाथ जोड शर्माते नही। (12:00 बजे) चार साल हो गए हाथ जोडे जोडे, बात तो सुन लें, बात कर लें, यह कोई डेमोकटिक वैल्यूज़ हैं कि पहले जी निकालूंगा फिर एक घूंट पानी या एक रोडी कंकर की दूंगा। यह सब बातें बडी मुश्किल हैं। गूलाब सिंह जैन जी, यह सब तपस्याएं मेरी न करवाओ और बहुत तरीके हैं.....विघ्न....मुझे मालुम है, सुनते हैं, मैंने उनसे पहले सुनना शुरु किया था। सिकन्दर के वक्त में जब वह स्कूल भी नही गए थे। तो मेरी अर्ज यह है कि डिवैलपमैंट के साथ डिसक्रिमीनेशन कि यह आपोजीशन का हलका है, और यह हलका कांग्रेस का है और जनरल इलैक्शन में यह स्पीचें कि देखिए साहब, अगर इधर वोट डाली तो अगले पांच साल पानी नही मिलेगाा, इससे बढिया

डिवैलपमैंट–कम–करप्शन और कोई नही है। हरिजन की बस्तीयों की बात चली। चेयरमैन साहब, मैं चौधरी चांद राम जी को बधाई देता हूं और मुझे खुशी होती है कि जब कोई आदमी किसी इंट्रेस्ट का नुमाइंदा हो जैसे दिवान चमन लाल जी, लेबर के नुमाइन्दे थे, सैंटर में रहे, जोशी साहब भी सैंटर में बहुत देर रहें। पंडित मोती लाल नेहरु के वक्त में, तो यह बात चौधरी चांद राम जी एक मसल्लमा लीडर हैं, हमारे लैबर्ज के लिए, ये हरिजन लफज तो पसंद है नही। तो चेयरमैन साहब मेरी अर्ज यह है कि यह लैन्डलैस लेबरर्ज का तबका है, हरिजनो का, इसमें जात पात की डिसक्रिमिनेशन (**इस समय उपाध्यक्षा पदासीन हुई**) भी दूर की जानी चाहिए कि कौन कौन कहां पैदा हुआ है, यह शैडूलकास्ट नान–शैडुलकास्ट , यह गरीब तबका है, जिस बेचारे के पास जमीन नही, खाती के पास जमीन नही या किसी ब्राहमण के पास नही। यह जमीन आबादी की है। यह डिसक्रिमीनेशन इररिस्पैक्टिव आफ कास्ट एंड क्रीड होनी चाहिए। हर एक को आबादी के लिए मिलना चाहिए। देहात के लोगों ने बडी कुर्बानी दी है, शामलात देह में से अलाटमैंट के वक्त। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टीस थे हिदायततुल्ला साहब, उन्होने बडा स्ट्रोंगली लिखा है। चांद राम जी मैने पहले भी जिक्र किया था, फिर दोबारा दोहरा देता हूं। उन्होने कहा कि प्रेजैंट प्रोप्राईटर्ज़ की कीमत पर जो लैंडलैस लेबर्ज़ को जमीने दी गई हैं हिंदुस्तान में लैंड रिफार्मज़ से और कोई बडी चीज नही है। क्या यह सैक्रीफाईज अर्बन हलके में नही हो सकती कि तमाम हरिजन भाईयों को म्युनिसिपल कमेटी फ्री में जमीन दें और फिर शहरों में वोटे भी हरिजनो की तकरीबन कांग्रेस को ही जाती है। यह बात की वोटों के

वक्त तो उन गावों को याद कर लें और उनका हम कर्जा वापिस न दें और उनमें से कोई लीडर अच्छे स्टेचर पर ग्रो करे तो उसके लिए डेलीब्रेट अटैम्पट यह की जा कि पांच चार आदमी उसके बोलने ही न दें। उस क्लास की लीडरशिप, लैंडलैस क्लास की टाप लीडरशिप को गिरा कर उसका एक रैविन्ज लेने की कोशिश की जाए हरिजनो के साथ यह कोई इंसाफ नही है। जहां टाप लीडरशीप पर हमला होता है चाहे वह बंसी लाल हो, चाहे वह चांद राम हो, चाहे वह कोई और हो, यह घाटे की चीज है। चेयरमैन साहब, उससे डिवलैपमैंट का काम रुकता है। हमने प्रोडक्टिव काम जो डिमांडज के मुताबिक है, यह गवर्नमैंट और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, बडे डायनैमिक हैं। गवर्नमैंट के मायने सी0 एम0 है, सी0 एम0 के मायने गवर्नमैंट है। हम कोई इस बात से शर्मिंदा नही होते चाहे जनसंघ वाले मुझे ताना दें (विघ्न) चेयरमैन साहब, इनको .....(विघ्न)

एक आवाजः डिपटी स्पीकर आ गई हैं।

चौधरी प्रताप सिंह दौलताः वह तो हमारी बुआ जी हैं, यह 1937 से मैम्बर हैं.....(हंसी).....मेरा तो इन्हे देखकर वैसे ही इज्जत से सिर झुक जाता है, सर शहाबुद्दीन, सिकंदर हियात, और दिवान चमन लाल और उन लोगों को देखते हैं तो उस कडी की अभी यह कडी बाकी है। हमारा सिर तो वैसे ही तहजीब से झुक जाता हैं। ..... विघ्न.....इन्होने वह जमाना देखा जब मैम्बर मैम्बर की इज्जत करता था, इन्होने वह जमाना देखा जब एक सी0 एम0 की हिम्मत नही होती थी कि वह एक एम0 एल0 ए0 को कह दे कि मैं इंटरव्यु नही देता।.....

विघ्न.....यह डिमांड है, मैं ठीक बोल रहा हूं अनपढ नही हूं ध्यान से सुनना चाहिए। इन्होने वह वक्त देखा है। डेमोक्रेटिक वैल्युज़ जहां जहां खत्म हो जाएं उस डिवैलपमैंट को फूंक दो।

उपाध्यक्षाः आनरेबल मैम्बर डिमांड पर बोले।

चौधरी प्रताप सिंह दौलताः डिप्टी स्पीकर साहिबा, अब मैं कह रहा था कि डायनामिज़म बहुत ले लिया, डिवैलपमैंट बहुत हो ली। अब थोडी सी डिवैलपमैंट डेमोक्रेटिक वैल्युज की तरफ हरियाणा में होनी चाहिए। क्योंकि यह मौका नही है, मौका आएगा तो मैं दफा 107/151 के नाम पर हरियाणा में क्या हो रहा है, पसर्नल फ्रीडम क्या है और लॉ एंड आर्डर किसे कहते हैं, फिर अर्ज करुंगा कि मुझे उस साइड पर अपनी हरियाणा गवर्नमैंट से बहुत शिकायतें है मैं नही चाहता कि इस दौर में शायद मेरी आखिरी मैम्बरी हो। मैं रिकार्ड पर यह कैस जाने दूं कि यह चीजें अननोटिसड, अनस्पोकन अनप्रोटैस्टीड गई है। वह मैं मुनासिब वक्त पर आकर फिर कहुंगा। अब मैं डिवलैपमैंट के बारे में इतना कहना चाहता हूं कि डिवलैपमैंट के साथ पुलिटिक्ल करप्शन मत जोडो, मैम्बरो की कांस्टीचुएंसी मत देखो, जिस कांस्टीचुएंसी पर पैसे कि कितनी जरुरत है उस पर उतना पैसा खर्च करो, वरना डेमोक्रेसी सरवाईव नही करेगी।

चौधरी फूल चंद (मुलाना अनुसूचित जाति): मानयोग डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपका बहुत मशकूर हूं कि आने मुझे बोलने का मौका दिय। आज अनुपूरक मांगो पर चर्चा चल रही है और विरोधी

तथा कांग्रेस दल के सदस्य इसमें भाग ले रहे है। इन एस्अीमेटस में बहुत अच्छी अच्छी मांगे सदन के सामने प्रस्तुत की गई हैं।इन सब में से मैं सबसे पहले मांग नं0 14 का जिक करुंगा जो कि हरिजनो के लिए मकानो के निर्माण के संबंध में है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, जिन लोगों के पास रहने के लिए मकान नही हमारी सरकार इस ग्रांट के जरिए उनको मकान देना चाहती है। (**इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए**)इतनी अच्छी विचार धारा के बावजूद भी कुछ साथी विरोध करते हैं क्योंकि उनका मुद्दा हि सिर्फ विरोध करने का है। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही अच्छी मांगे है। हमारी सरकार ने हरिजनो की भलाई के लिए कितने काम किए इसकी पुरी सूची देना तो मैं इस वक्त ठीक नही समझता लेकिन इतना बता देना चाहता हूं कि जो साथी हिंदूस्तान के अंदर दावा करते हैं कि हम हरिजनो के सब से बडे साथी हैं, उनसे बहुत ज्यादा इस सरकार ने उनके लिए काम किए हैं। जोर से चिल्लाने से यह साबित नही होता कि आप हरिजनो के साथी हैं। मेरा इशारा चौधरी चांद राम जी की तरफ है कि वे हरिजनो की कितनी भलाई चाहने वाले हैं। स्पीकर साहब, 1967 के अंदर हमने टिकट के लिए एप्लाई किय। उन दिनों जो कांग्रेस के प्रधान थे....

चौधरी दल सिंहः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। ये कोन सी डिमांड पर बोल रहे हैं। इन डिमांड में तो कहीं टिकट का जिक नही है।

श्री अध्यक्षः चौधरी फूल चंद जी आप डिमांड पर ही बोलें।

चौधरी फूल चंदः स्पीकर साहब, इसका ताल्लुक डिमांड नम्बर 14 से है जो हरिजनो को मकान देने के संबंध में है। तो मैं जिक्र कर रहा था कि हमारे प्रधान ने यह बात कही कि टिकट आपको देते हैं मगर ये चाहते हैं कि कोई पढा लिखा हरिजन आगे न आए।

श्री अध्यक्षः आप टिकट का जिक्र छोडिए। डिमांड पर बोलें।

चौधरी चांद रामः मैं कांग्रेस हाई कमांड में नही था।

चौधरी फूल चंदः आप सिलैक्शन कमेटी के मैम्बर थे। आपने एक अनपढ आदमी का नाम रिकैमंड किया था।

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, इनसे पूछ लो कि कितनी दफा कांग्रेस के खिलाफ लडे?

चौधरी फूल चंदः स्पीकर साहब, यह जो डिमांड नं0 23 है यह अच्छी है। जो स्माल स्केल यूनिट्स हैं जब वह रुरल और अर्बन एरियाज़ में देंगे तो उस से एक तो लोगों को राजगार मिलेगा और चीजों की प्रोडक्शन भी बढेगी और हरियाणा जो काफी तरक्की पर जा रहा है वह पहले से भी ज्यादा तरक्की करेगा। इसके बाद मैं डिमांड न. 0 26 पर जाता हूं। इसमें शिक्षित बेरोजगारो के लिए पैसा मांगा गया है। यह भी बहुत अच्छी स्कीम है। आज कल हम देख रहें हैं कि अनएजुकेटिड बेरोजगारों के साथ साथ एजुकेटिड अनएम्पलायमैंट भी बहुत है। एजुकेटिड लोगों को रोजगार देने के लिए यह जो मांग लाई गई है इसके लिए मैं सरकार को मुबारकबाद देता हूं। अभी एक मैम्बर साहब ने कहा था कि रुरल एरियाज़ में लोगों का उजाडा जा रहा है।

जिसका कि इसके साथ कोई ताल्लुक नही था। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस मैमोरैंडम के जरिए उन्होने एक संघर्ष समिति बना कर लोगों से लाखो रुपया चंदे का इकट्ठा किया और अपनी जेब में डाल लिया, इसके अलावा खरखौदा टेनरी की सोसाईटी का कोई हिसाब नही दिया, और इस तरह से सुनारवाला सोसाईटी का हिसाब नही दिया।

चौधरी राम लाल वधवाः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब, हमें कृप्या बताया जाए कि मैम्बर साहब किस डिमांड पर बोल रहे हैं।

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, यह जो कुछ भी अभी मेरे बारे में कहा गया है यह प्रोसीडिग्ज का पार्ट रहेगा या ऐकसपंज करवाया जाएगा।

श्री अध्यक्षः फिर तो आपकी भी बहुत सी बातें एकसपंज करवानी पडेगी।

चौधरी चांद रामः आप मेरी तो ऐकसपंज करते ही रहें हैं। स्पीकर साहब मैं आप का ध्यान रुलज़ की तरफ दिलाना चाहता हूं कि जो मैम्बर हाउस में हाजिर हो वह दूसरे मैम्बर का इस तरह से नाम नही ले सकता। लेकिन अगर वह कहते हैं तो मुझे फिर से पर्सनल एक्सप्लेनेशन का टाईम मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्षः आप तशरीफ रखिए। मुझे रुलज़ का पता है।

चौधरी फूल चंदः स्पीकर साहब, असलियत तो सब को कडवी लगती है।

श्री अध्यक्षः आप डिमांड पर बोलें।

चौधरी फूल चंदः यहां इरीगेशन की स्कीमों की चर्चा हुई जिसमें इंदिरा गांधी का जिक्र हुआ। मेरे कहने का मतलब है कि ऐसी ऐसी नहरे बना कर हमारी सरकार ने उन इलाकों को सरसब्ज करना है जहां पर सदियों से पानी की कमी रही है। अब वहां के खेत लहलहाएंगे। वैसे तो पहले ही इस बात को सारे देश मे माना गया है कि हरियाणा बहुत तरक्की कर रहा है। हमे विश्वास है कि जो इनकम्पलीट नहरे और सडकें रह गई हैं, खास तौर पर मेरे मुलाना के हलके में, उन को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाएगा। सिंचाई के जो साधन है वे और अच्छे होगें, सडके बनाने के लिए और अस्पताल खोलने के लिए जो लोगों की सेहत के लिए बहुत जरुरी है, सरकार इन पर ज्यादा खर्च करेगी। हलका मुलाना में अधूरी सडके तथा सिंचाई के साधन पुरे करेगी। जो लोग महज नुक्ताचीनी के लिए ही बात करते हैं उस चीज का कोई फायदा नही होता। अभी चौधरी चांद राम जी ने कहा था कि थोडे से पैसे से क्या फायदा होगा? वे क्या यह चाहते हैं कि लोगो कि भलाई के लिए बिल्कुल ही कुछ न हो? मैं तो कहता हूं कि कुछ न होने से कुछ होना अच्छा है। अगर थोडा थोडा भी होता गया तो उससे काफी सफलता होगी। मैं समझता हूं कि जो डिमांडज हाउस में रखी गई हैं वह बिल्कुल जायज हैं और उनसे हमारे प्रांत में

ज्यादा तरक्की होगी। इसलिए मैं निवेदन करुंगा कि यह पास होनी चाहिए।

चौधरी दल सिंह (जींद): आदरणीय स्पीकर साहब, चौधरी प्रताप सिंह दौलता और चौधरी चांद राम जी के बोलने के बाद मैं समझता हूं कि इन डिमांड्ज पर और ज्यादा बहस करनी कोई समझदारी नही।

चौधरी मेहर चंद: तो फिर आप बैठ जाएं। Why to waste time?

चौधरी दल सिंह: I must, स्पीकर साहब, मैं निवेदन कर रहा था कि अब इन डिमांड्ज पर कुछ ज्यादा कहने कि जरुरत नही लेकिन फिर भी चंद बातों की तरफ मैं हाउस का ध्यान दिलवाउंगा ताकि वह बात साबत हो सके कि यह डिमांडज रखते वक्त इन्होने बडी लापरवाही से काम लिया है। मैं सन् 1952 से मैम्बर चला रहा हूं। इतने अरसे से मैं ने शायद कहीं देखा हो कि बजट के अंदर जो राशि रखी गई हो उस से भी ज्यादा सप्लीमैंटरी डिमांड्ज मांगी जाए। मैं आपका ध्यान डिमांड नम्बर 26 की तरफ दिलाना चाहता हूं जो 1973–74 का बजट ऐस्टीमेट था उसमें 1 करोड 21 लाख 5 हजार 360 रुपये का प्रोविजन किया गया था। लेकिन अब यह 1 करोड 75 लाख 75 हजार 20 रुपये की रकम सप्लीमैंटरी डिमांड के जरिए मांग रहे हैं जो कि बजट प्रोविजन से भी ज्यादा है। कितनी हैरानी की बात है कि जब बजट बना उस वक्त यह महसूस नही कर सके कि बजट में ठीक तरह से प्रोविजल करें। हमारे वित्त मंत्री साहब ने कहा था कि हमारे सरकारी कर्मचारियों

ने बजट बनाते वक्त बडा अच्छा काम किया है और बजट बडा अच्छा बनाया है। लेकिन उस अच्छे बजट का नमुना आज हमारे सामने सप्लीमैंटरी डिमांडज में दिखाई दे रहा है। मैं समझता हूं यह बहुत भारी गलती है और इस से और इस से बैड विजिटिंग और काई हो नही सकती और यह गलती लाकाबलेबर्दाश्त है। इसी तरह डिमांउ नं0 44 है जो सिंचाई से संबंध रखती है। इस के लिए 1973–74 में बजट में 6,71,57,150 रुपये रखे थे लेकिन अब 7,48,00,000 रुपये की मांग की जा रही है। यह बडी अजीब कहानी दिखाई देती है। बजट में कम रकम और सपलैमंटरी में ज्यादा रकम मांगी जा रही है। अब मैं डिमांड नं0 14 की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। उस पर वैसे तो बहुत बहस हो चुकी है। इस में 12लाख रु अनकलीन काम करने वाले हरिजनो को एक कमरा बना कर देने के लिए रखा गया है। स्पीकर साहब, आजकल की महंगाई में 2 हजार रु में कैसे मकान बन सकता है। अगर वाकई सरकार हरिजनो की भलाई चाहती है और उनको मकान बना कर देना चाहती है तो फिर सरकार को इस काम के लिए बडी रकम रखनी चाहिए। वर्ना दो हजार में जो मकान बनेगा वह दो चार साल के बाद गिर जाएगा और यह पैसा भी जाया जाएगा। आज कल चाहे कोई भी पार्टी हो वह यही चाहती है कि समाजवाद होना चाहिए और हरिजनो को उपर उठाना चाहिए। इस के साथ साथ हमें यह भी नही भुलना चाहिए कि हमारे सूबे और भारतवर्ष में बहुत से ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो हरिजनो से भी गरीब हैं।इसलिए कोई वजह नही है कि एसे लोगों के लिए प्रोविजन न किया जाए। चाहे वह किसी बिरादरी के हों उनकी तरफ भी गवर्नमैंट को ध्यान देना चाहिए। चाहे हरिजन हैं, चाहे बैकवर्ड

क्लासिज़ के लोगे हैं या किसी भी बिरादरी के लोग हैं अगर वे गरीब हैं तो उनको सरका द्वारा मदद देनी चाहिए और रियायत देनी चाहिए।

इसके बाद मैं डिमांड नं0 26 की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं यह सोशल और डिवलैपमैंट आर्गनाईजेशन के बारे में है। इस में बेरोजगारो को रोजगार देने की बात कही गई है। आमतौर पर सरकार जो काम करती है वह किसी खास मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए करती है। किसी खास जिले को, किसी खास तहसील को तरजीह देने की कोशिश करती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जिले में बेरोजगारों को रोजगार देने का कोटा मुकर्रर किया जाना चाहिए ताकि हर जिले को फायदा हो सके। यह नही होना चाहिए जैसे सर्विसिज़ में तहसील भिवानी और महेंद्रगढ के लोग ही भर्ती हो। अगर किसी विशेष इलाके के लिए इस प्रकार की बात होगी तो यह हरियाणा के लिए बहुत घातक सिद्ध होगी। मैं कहना चाहता हूं कि जो बैकवर्ड इलाके हैं, वे चाहे भिवानी तहसील के हैं, चाहे भिवानी तहसील के हैं, चाहे जींद के इलाके हैं उन को प्रपोर्शनेटली उपर उठाया जाएं। यह नही होना चाहिए कि एक तरफ बहुत ज्यादा रुपया खर्च कर दिया और दूसर तरफ एक पैसा भी खर्च नही किया।

अब मैं डिमांड नं0 44 के बारे में कहना चाहता हूं जो इरीगेशन के सिलसिले में है। इरीगेशन के लिए बडी भारी रकम मांगी गई है। इस मांग के अन्तर्गत हिसार जिले को पानी दिया जाएगा। मुझे कोई दिक्कत नही है कि हिसार जिले में पानी जाए लेकिन हरियाणा में बहुत से इलाके मौजूद है जहां पानी की बहुत भरी कमी है। मैने पीछले

सैशन में दो बार जिक्र किया था कि मेरे इलाके जींद में झांज गांव, झांजकलां, झांजखुर्द, दरियावाला, जजांवाणखेडी, बडौदी जैसे इलाके हैं जहा पिछले सात साल से बारिश नही हुई और आज भी कहर पडा हुआ है। मैं यहा तक कह सकता हूं कि वहां लोग शदी नही कर सकते, इतनी खराब हालत है, अगर ऐसे इलाके को पानी देने से नजरअंदाज किया जाए तो बहु बुरी बात है। रकम को देखने से पता चलता है कि तमाम रकम जिला हिसार पर खर्च की जा रही है। मैं हिसार और भिवानी का विरोधी नही हूं लेकिन मैं यह कहना चाहताहूं कि जो इलाके पानी हासिल नही करते, जहां कईसालों से खुश्की है, उनको पहले पानी दिया जाना चाहिए, उनका भी हक है। जो हमारे सरकारी भाई हैं वेशायद ऐसे इलाकेमें जाने का दम नही रखते लेकिन मैं उनके बारे में कह सकता हूं। जूलाने के अंदर मालवी, कचामखेडा, जफरगढ और पौली वगैरा ऐसे गावं हैं जहां पानी नही मिलता, इनकी तरफ खास ध्यान दिया जाए। जहां पानी की बात करते हैं वहां पानी का बंटवारा करते हुए इन पिछडे हुए गावों को ध्यान में रखना चाहिए।

इसी प्रकार सडको की हालत है। सडको के बारे में दौलता साहब ने जिक्र किया है। ऐसी ऐसी सडके मौजूद हैं जो दो दो हजार रुपये की कमी के कारण नकारा पडी हैं। इन सडको को देखकर सरकार की बदनामी होती है। क्योंकि कई जगहो पर पुलिया नही है और अगर कहीं पर है तो वहां सडक से पांच गज के फसले पर है। पडा पडा मैटीरियल खराब होता रहता है।मैं जानना चाहता हूं कि सरकार के सामने कौन सी दिक्कत है जो सरकार चैकिंग नही करती?

एक तरफ ो ये कहते हैं कि विरोधी दल वाले जो बात कहेंगे उस हम मान लेंगे और दूसरी तरफ जो बात हम कहते हैं तो उनको शील्ड करते है। कोई भी कर्मचारी जो रिश्वतखोर है, अगर कोईउसके बारे में शिकायत करता है तो उसको बचाने का काम सरकार को नही करना चाहिए और जो शिकायत मिलती है उसकी इन्कवायरी करनी चाहिए। रामराय से राजपूरा तक एक लिंक रोड हैं यह सडक इतनी खराब है कि इस पर डंगर नही चल सकते, तांगा नही चल सकता। इसके अलावा अमरहेडी से कैरखेडी जाने वाली लिंक रोड बीच में पडी हूई है। खटकर से बरसोआ जाने वाली सडक की भी बहुत बुरी हालत है। मेरा कहने का मतलब है कि जो सडकें थोडी थोडी कमी के कारण बीच में पडी हुई हैं उनकी मुरम्मत की जाए।जो लोग उन सडको पर जाते हैं वे सरकार को गालियों निकालते है। मुझे दिक्कत नही है सरकार बनाये या न बनाये लेकिन सरकार को लोगों की भलाई का ध्यान रखना चाहिए। जो सडके मामुली खर्च पर बन सकती हैं उनको बनाया जाए।

Shri Ram Saran Chand Mittal: On a point of order, Sir, For the information of the hon. Member I may read out this Rule about the debate of supplementary estimates.

It reads-

"223. The debate on the supplementary grants shall be confined to the items consituting the same and no discussion may be raised on the original grants nor policy underlying them save in so far as it may be necessary to explain or illustrate the particular items under discussion."

चौधरी दल सिंहः वजीर साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया लेकिन अब मैम्बरों ने ऐसी बातें कही हैं, बडी इररैगुलैरिटी हुई है। स्पीकर साहब मैंआपका ज्यादा टाईम न लेता हुआ एक बात कहना चाहता हूं कि हाउस के अंदर रोज चर्चा होती रहती है चौधरी चांद राम जी के बारे में। जब चौधरी चांद राम जी बोलते हैं तो चार पांच मैंम्बर बोलते है। उनको एक बात याद रखनी चाहिए कि वे हरिजनो के वाहद लीडर हैं इसमें कोई शक नही है। दूसरी एक समस्या है जिस को हल करने के लिए चौधरी चांद राम जी को यह डिकलेयर करना चाहिए कि वे कांग्रेस में नही जाना चाहते। हम यह रोज का झगडा नही चाहते। अगर उन में दम है यह कहने का कि मैं नही जाना चाहता तो हम यह समझेंगें कि ये हरिजनो के हमदर्द है। यह गोलमोल बात न करें, इसको क्लीयर करें। (इस समय बहुत से सदस्य बोलने के लिए खडे हुए)

चौधरी चांद रामः मैं एक एक्सपलेनेशन देना चाहता हूं.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप तशरीफ रखिए।

चौधरी चांद रामः मेरे पोलिटिक्ल कैरिअर पर एक बात कही गई है उस पर एक्सप्लेनेशन देता चाहता हूं।.....

श्री अध्यक्षः इस किस्म के रैंकस आते ही रहते हैं। आप तशरीफ रखिए।

चौधरी शिवराम वर्मा (नीलाखेडी): स्पीकर साहब, हाउस में सप्लीमैंटरी डिमांड्ज पर चर्चा चल रही है। में समझता हूं कि सरकारी

बैंचिज की तरफ से डिमांडज् पर बोलने की आवश्यकता नही है क्योंकि उन्होने लिखकर दे रखा है जो कुछ भी मसला उनके पास था। हम विरोधी पक्ष के लोगों ने इनको यह बताना है कि क्या क्या कमियां इसमें रह गई हैं। और इसका जवाब मंत्री महोदय देंगे।..... का काई लाभ नही है।

श्री अध्यक्षः ये लफ्ज़ एकसपंज कर दिए जाऐं।

चौधरी मेहर चंदः स्पीकर साहब, ये हम पर इस किस्म का असपर्शन कास्ट क्यों करते हैं? हम भी इनकी तरह इलैक्ट होकर आए है।ये गलत बात क्यों कहते है। आखिर हमें भी बोलने का राईट है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मैनें ये शब्द पहले ही ऐक्सपंज करवा दिये हैं?

चौधरी शिवराम वर्मा (नीलाखेडी): मैंने यह नही कहा कि इलैक्अ होकर आए हैं ...(व्यवधान) स्पीकर साहब,मैं हाउस का टाईम बचाना चाहता हूं। इसलिए कह रहा था। डिमांड नं0 14 जो सबसे पहली डिमांड है, इस में हरिजनो के लिए, बैकवर्ड क्लासिज़ के लिए मकान बनाने की बात कही गई है लेकिन इस प्रर्पज़ के लिए 12 लाख रु रखे है। मैं समझता हूं कि 26 साल तक सरकार ने हरिजनो को, बैकवर्ड क्लासिज को जमीन देने का लारा दिया, लेकिन जमीन दी नही गई। दो साल से बैंक से लोन देने का लारा देते रहें और गरीब हरिजन इस चक्कर पर चढे रहें। अब इधर से मकान देने का लारा शुरु कर दिया। यह लारा ही लारा है। हरिजनो का कुछ होने वाला नही है।

चौधरी चांद राम जी के हिसाब से 12 लाख रुपये से प्रति जिला में केवल 60 मकान ही बनते है अगर दो हजार रु मकान पर खर्च किया जाए। अगर 3000 रु खर्च हो तो शायद 40 ही बने। इस हिसाब से कितने लोगो ंको मकान मिलेगें? यह लारा देने के सिवाय और कोई बात नही । बजाय वोटो की तरफ ध्यान देने के इस तरफ ध्यान देना चाहिए और आज तक ये लारा देकर ही वोट लेते रहे, यही रवैया रहा कि अगर हमने चीज देदी तो लारा किस चीज का देंगे। अगर आपके पास चीज नही है तो ये कह दें कि अपने पैरो पर खडे हो, कमाओ और खाओ लेकिन लारा देना ठीक बात नही है। जो काम आपने करना है वह दिल से करें, ज्यादा से ज्यादा रुपया लगाएं। इस में लाभ करने की बचत करने की बात नही है। मै डिमांड नं0 23 जो स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में है, कुछ कहना चाहता हूं। मैं सरकार को एक बात कहना चाहूंगा कि वैसे तो अपने अपने स्थान पर ये सभी डिमांडज अच्छी है लेकिन इस डिमांड की तरफ बहुत ज्यादा घ्यान जाना चाहिए। देश में बहुत बेरोजगारी है और हमने इसे खत्म कर लोगों की हालत सुधारनी है। चाहे हरिजन हैं या दूसरे तबके के लोग उनको छोटे छोटे उधोग दें। वे अपने आप ही अपने मकान बना लेगें। इस तरह से देश खुशहाल होगा और देश में किसी किस्म की कमी नही होगी। यदि छोटे छोटे युनिट्स का सारे देश में जाल बिछा दिया जाए तो जहां लोगो को रोजगार मिलेगा वही दूसरे फायदे भी होगे। बडे बडे उधोग जहां होते हैं वहां लेबर युनियनज़ उनकी हडताल कराती है। वहां झगडे खडे होते हैं। अगर गावं गावं में बिखरे युनिट्स होगें तो लेबर प्रोब्लम भी नही होगी, लोगों को काम भी मिलेगा और जो चीज जहां पैदा

होती है वह वहां के लोगों को सस्ते दाम पर मिलेगी। आज कितने ही लोग बीच में मुनाफा कमाते है। इसलिए सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। स्पीकर साहब, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं तरकीबन डेढ साल हो चुके हैं, उधोग मंत्री ने कहा था कि निलोखेडी में शैड्ज बनाए जाएगें। कुछ बने हुए है उनको हटा कर और बनाए जाएगें, और ज्यादा इंडस्ट्रीज चालु होगी लेकिन अभी तक कोई बात नही छेडी गई। जो जमीन बराबरी में पडी हुई थी उस पर भी दूसरे डिपार्टमैंट ने कब्जा कर लिया। स्पीकर साहब, जो बात यहां कही जाए और अगर पुरी नही की जाए तो यह अच्छी बात नही है। इससे तो लोग समझेंगें कि सरकार जो कहती है वह करती नही है। जो बात सोच ली जाए उसको कर दिया जाए। इससे सरकार के उपर लोगों का विश्वस जमेगा। लोग समझेंगें कि सरका जो कहती है वही करती है। यह नही कि लारा दे दिया और लारा देने के बाद उनको दिया कुछ नही।

इसके बाद स्पीकर साहब, मैं डिमांड न 26 की ओर आता हूं। शिक्षित बेरोजगारो के लिए जो बात कही गई है वह भी मैं समझता हूं क इतनी बडी योजना नही है जिससे सब लोगों को रोजगार मिल सके। शिक्षित बेरोजगारो को रोजगार देना सबसे ज्यादा जरुरी है। क्यांकि अशिक्षित बेरोजगार शारिरीक मेहनत करके अपना गुजारा कर लेते हैं वे थोडे खर्चे में अपना काम चला सकते हैं लेकिन पढे लिखे बेरोजगार जो हैं उनके रहने सहने का स्तर उंचा हो जाता है और वे शारिरीक मेहनत से किनाराकशी करते है। मैं चाहता हूं कि विशेष योजना बनाकर सभी को पूरा रोजगार देने के लिए सरकार को कोई

योजना बनानी चाहिए। इस तरह से तो बेरोजगारी खत्म होने वाली नही है। शिक्षित बेरोजगारी को खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा जरुरी है कि उन्हे उधोग धंधो में लगाया जाए। उधोग लगाने के लिए उन्हे कर्ज दिया जाए, ग्रांट दी जाए। ये सारे काम एक नियोजित ढंग से करने की जिम्मेवारी सरकार को अपने जिम्मे लेनी चाहिए। तभी शिक्षित बेरोजगारो की समस्य हल होगी नही तो इस तरह और भी बढती जा रही है।

इससे आगे स्पीकर साहब, मैं डिमांड न0 30 की बात करता हूं। इसमें मैं समझता हूं कि सरकार यह नही सोचती कि बहुत जरुरी जो खर्चे है केवल वही किए जाएं और दूसरे जो नाजायज खर्चे हैं उनको रोक दिया जाए। कल यहां बात हूई कि स्कुलो मे टीचर्ज नही हैं क्योकि पैसा नही है। मंत्री महोदय ने बता दिया कि पैसे की कमी के कारण टीचर्ज की भर्ती के उपर प्रतिबंध लगा रखा है। आज शिक्षा की बडी आवश्यकता है। शिक्षा फेलनी चाहिए न कि प्रतिबंध लगा कर उसके फेलाव को रोक दिया जाए। जब एक तरफ यह हालत है तो मंसूरी जैसी जगह में जो दूसरे प्रांत में है एकांत भवन खरीदने की आवश्यकता को मैं नही समझ सका। मुझ से पहले भी कुछ सदस्यो ने इस बात का जिक्र किया। एकांत भवन भी इसका नाम पता नही कैसे पडा। पता नही पहले से ही इसका नाम ऐसा था या बहुत दूर होने की वजह से रखा गया है। खैर मैं इस ओर न जाते हुए इतना कहूंगा कि इसकी कोई आवश्यकता नही थी। ऐसे खर्चो को कम करके दूसरे कामों में जो की बहुत जरुरी हैं पैसा लगाया जाना चाहिए।

रोहतक–भिवानी रेल लिंक का बनाया जाना बहुत अच्छा है। बाकी लिंकज के बारे में भी सैंट्रल गवर्नमैंट से बात की जाए। इस लिंक पर तो हमारी सरकार ने सर्वे आदि पर खर्च किया है, बाकी सैंट्रल सरकार कर रही है मगर एक और लिंक जिस पर हमारी सरकार कुछ खर्च नही करना पडेगा वह है गोहाना से पानीपत जिसे पिछले वर्ल्ड वार में उठा दिया गया था।

श्री अध्यक्षः वह भी मंजूर हो गया है।

चौधरी शिवराम वर्माः मंजूर तो हो गया है मगर उस जल्दी बनवाने के लिए सरकार को प्रयत्न करना चाहिए।

राजस्व मंत्री (पंडित चिरंजी लाल शर्मा): वह भी करेंगे।

चौधरी शिवराम वर्माः आपके हाथ में तो कुछ नही है। आपका संबंध तो सडको से रहा है जिन पर साईकिल भी नही चल सकती। मैं उनकी तरफ भी आ रहा हूं।

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, अब आप समाप्त करें क्योंकि अभी कुछ और सदस्य भी बोलना चाहते हैं।

चौधरी शिवराम वर्माः मैं तो जल्दी जल्दी में एक डिमांड पर एक ही मिनट ले रहा हूं। स्पीकर साहब, मैं भी निवेदन करुंगा कि रोहतक–भिवानी लिंक के साथ साथ अगर हो सके तो झज्जर को भी लिंक कर दिया जाए। (विघ्न)

इसके बाद स्पीकर साहब, मैं डिमांड न0 44 की बात करता हूं। यह सिंचाई वगैरा के बारे में है। इसके संबंध में मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस काम को बहुत समझदारी से करना चाहिए। ऐसी बात न हो कि जिन इलाको में सिंचाई सुविधा मिली हुई है उनमें कटौती करके दूसरी जगह नहर निकाल दी जाए या फलां जगह पानी पहूंचा दिया। पानी बढा कर अगर नई नहर निकाले तो अच्छी बात है। आज तो हालत यह है कि पीछे जहां 30 परसैंट पानी मिलता था वहां बडी मुश्किल से 10 से 15 परसैंट भी पानी नही मिल रहा क्योंकि सरकार उसे आगे ले जा रही है। इससे तो मैं समझता हूं कि समस्या का हल नही हो सकेगा। हमने तो सारे प्रांत की और सारे देश की समस्या को हल करना है। अगर सारे देश या प्रांत को हम सामने रखे तो हमें सोचना चाहिए कि जिस पानी से 100 एकड खेती पक सकती है उसे यदि हम उस इलाके में ले जाएं जहो केवल दस पंद्रह एकड में ही वह पानी खत्म हो जाएगा तो इससे देश या प्रांत का नुकसार होगा। यह ठीक है कि कुछ आदमियों को पानी मिलेगा उन्हे लाभ होगा लेकिन प्रांत को नुकसान होगा। इसलिए अगर फालतू पानी कहीं से लाकर हम ले जा सकते हो तो जरुर ले जाना चाहिए लेकिन पानी पीछे से काटकर आगे ले जाने का कोई फायदा नही।

स्पीकर साहब, ड्रनेज़ की बात भी इसी डिमंड में हैं। मैं निवेदन करुंगा कि सरकार सबसे पहले सर्वे कराए जहां लिंक ड्रनेंज की जरुरत है ? जहां पानी ब्लाक हो जाता है वहां काफी रकबा मारा जाता है। अगर वहां छोटी छोटी ड्रनेज़, कोई मिल, कोई दो मिल की बनवा

दी जाएं तो फुलड्ज से काफी रकबा बच सकता है और लोगों में जो एक शोर मचता है ज्यादा बारिश होने पर वह शोर भी खत्म हो जाएगा। इसलिए लिंक ड्रेनेज की ओर भी विशेष ध्यान दिया जाए।

अब मैं डिमांड नं0 45 पर आता हूं। इसमें बताया गया है कि नए जिले बनाने की वजह से काफी खर्च बढा है। मैं यह समझता हूं कि जिस समय प्रांत के अंदर रुपये की कमी है और आवश्यक खर्चे रोकने पडे हैं नए जिले थोडे दिन बाद भी बन सकते थे, अभी उनकी जरुरत नही थी.....

श्री के0 एन.0 गुलाटीः फरीदाबाद को तो बनने दो।

चौधरी शिवराम वर्माः फरीदाबाद को कौन रोकेगा गुलाटी साहब? वह तो आप मुख्य मंत्री जी से बात कर रहे हैं। तो यह जो नये जिलों का खर्चा था इसे रोक कर, जो सडकें बहुत जरुरी थी उन पर करते। बिजली को बढाने का प्रयत्न करते। शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा टैक्नीकल शिक्षा देने के लिए कोई प्रोग्राम बनाते। यदि ऐसा सरकार की ओर से किया जाता तो वह अधिक लाभदायक सिद्ध होता। इन जिलो को तो बाद में भी बनाया जा सकता था।

मैं सरकार का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जो आवश्यक खर्चे है वही किए जाएं। जो अनावश्यक है, अन–उत्पादक खर्चे है उनको रोक दिया जाना चाहिए जो बहुत ही आवश्यक खर्चे है उन पर ही खर्च किया जाना चाहिए।

सरकार ने जो सडके बनानी शुरु की थी वे बीच में ही पडी है। कई सडके तो ऐसी ळे जिनके बारे में पी0 डबल्यु0 डी. मिनिस्टर साहब भी अच्छी तरह से जानते होगे, वे सडके ऐसी बनी हई हैं जिनपर साइकल भी नही चल सकती। उन सडको के पत्थर उखडे हुए है कई सडको पर ईंटे पडी है, सोलिंग भी हूई है पत्थर रोडा भी पडा है और वह जाया हो रहा है। इसलिए सरकार को ऐसी सडके पहले पुरी करने की ओर ध्यान देना चाहिए। जहां पर एक या दो चीजें पडी हैं दूसरी के बिना वह सडक रह गयी है तो वह सडक सब से पहले बनायी जानी चाहिए। उन सडको पर खर्चा भी कम होगा। इस तरह से हम इंटीरियर में जा सकेगें। इसी तरह से जो सडके मेन रोड से दो तीन गावों तक तो चली गई लेकिन उनके बीच में जो गावं आते है उनके पास वही कच्ची पडी है, कहीं वह दो फर्लांग है, कहीं एक फर्लांग है। उनके रास्ते कच्चे पडे हैं, बरसात हो जाने पर उन रास्तो को पार करना बडा ही मुश्किल हो जाता है और इसी कारण बेकार हो रही है। इसलिए इस प्रकार की सडकें भी पूरी बनायी जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा कर देने से जो सडक तीन–चार मील लम्बी बनी है। उसके बीच के सभी उन गावों को भी सुविधा मिल सकेगी।

बिजली के बारे में मैंने सरकार का ध्यान पहले भी दिलाया था और अब फिर दिलाना चाहता हूं और लोगों ने रबी की फसल के बारे में अभी से शोर मचाना शुरु कर दिया है कि पिछले साल की तरह इस बार भी बिजली नही मिलेगी। अब भी 16 घंटे में मुश्किल से 12 घंटे बिजली मिलती है। यदि बिजाई के वक्त ही बिजली पुरी न मिले

तो आगे गेहूं की फसल का क्या हाल होगा। किसानो का मन गेहूं की तरफ से बदल चुका है। वे अब जौ चना आदि बोना चाहते है। क्योंकि उसमें थोडा पानी देना पडता है थोडा खर्चा करना पडता है। इसलिए अब उनका ध्यान इस ओर बदल रहा है। अगर यह ट्रैंड बदलता चला गया तो देश के हित में नही होगा। कुछ तो भाव कम होने की वजह से ट्रैंड बदल रहा है। अब अगर पानी की भी कमी हो जाएगी तो किसान का मन दूसरी तरफ हो जाएगा। हमारे देश में गेहूं का बडा संकट आया हुआ है। अगर हम पानी का कोई ईलाज नही कर पायेंगे तो किसानो का अवश्य ही मन बदल जाएगा। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि गेहूं के उचित भाव, सिंचाई की ओर, खाद की ओर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि देश के अन्न का अकाल आने का भय दूर हो।

श्री अध्यक्षः अब आप समाप्त करें। आपका समय हो गया।

चौधरी शिवराम वर्माः एक बात मैं और भी कहना चाहता हूं कि किसानो को गेहूं का भाव 125रुपये क्विंटल मिलना चाहिए। जब यह भाव मिलेगा तभी किसान का ध्यान गेहूं की पैदावार बढाने की ओर होगा। इसलिए मैं फिर कहूंगा कि देश के सामने जो संकट आया है उससे बचला है तो इन चीजो का सरकार को इलाज करना ही पडेगा।

(इस समय कई सदस्य बोलने के लिए खडे हुए)

बैठक के समय में वृद्धि

श्री अध्यक्षः देखिए समय बडा कम है और आप कई सदस्य बोलना चाहते हैं। यदि आप बोलना ही चाहते है तो हाउस का टाईम बढा देते हैं।

कई सदस्यः जी हां कुछ टाईम बढा दिया जाए।

श्री अध्यक्षः आधा घंटा सदन का समय बढाया जाता है।

वहिमर्गन

चौधरी रामलाल वधवाः स्पीकर साहब, क्या मुझे टाईम मिलेगा या नही?

श्री अध्यक्षः आप जनसंघ पार्टी से दो मैम्बर हैं। आपकी पार्टी का एक मैम्बर बोल चुका है। एक मैम्बर कल बोल लेगा।

चौधरी रामलाल वधवाः स्पीकर साहब, आपने मेरे मोशंज के विषय में लिखित उत्तर में भी कहा है कि सप्लीमैंटरी डिमांडज पर बोल सकते हैं लेकिन फिर भी आप मुझे समय नही दे रहे हैं।

श्री अध्यक्षः आप एप्रोप्रिएशन बिल पर कल बोल लेना।

चौधरी रामलाल वधवाः स्पीकर साहब, मै बतौर प्रोटैस्ट वाक–आउट करता हूं।

(इस समय चौधरी रामलाल वधवा सदन से उठकर चले गए)

अनुपूरक अनुदानो की मांगो पर चर्चा तथा मतदान
(पुनरारम्भ)

Revenue Minister (Pandit Chitranji Lal Sharma) : Mr. Speaker, Sir, I had absolutely no mind to speak today, but in view of what has been said by some members of the opposotion pertaining to my Department. I have to say a few words. I won't take too long. Particular reference has been made to he conditions of roads that were constructed during the crash programme and Hon'ble members have been able to draw my attention to particular roads. In this connection I have to say only one thing. I would welcome suggestions, I would welcome complaint and I can assure all the members of the opposition that an enquiry would be instituted into the allegations that are made by them. During the crash programme, Mr. Speaker, I would not dispute that quality of roads which may not be upto the expectations of the people. It is possible, may, probable that inferior quality of material may have been used during crash programme. But the credit goes to the engineers that within a very short span of time they were able to connect about 60% villages of Haryana by roads. As far as allegations are concerned, I will not mind it; we are open to conviction and I would again welcome my hon. friends to give me in writing their complaints and I can assure them that enquiry would be instituted.

Then, again one hon'ble member from the opposotion it does not look nice to mention his name has unnecessarily reopened a closed chapter ie.e creation of three new districts. he has criticised it. This point was amply discussed last time and I had made it clear that the formation of these three districts out of Hissar, Karnal and Rohtak, was in the interestof development. I

mean, Government had no ulterior motive. It is correct that some extra expenditure is going to be incurred. That is no ground for criticism. A lot has been said by me about it.

Then, again an Hon'ble member from the opposition just criticised the Government for some sort of discriminatory treatment that was meted out to a particular constituency. That is not so. If facts and figures are quoted, I can say with confidence, may, with sense of responsibility that there is absolutely no discriminatory attitude towards any particular member, whether he is from oppositionor from the Treasury benches. During the crash programme, Mr. Speaker, construction of roads was started everywhere in each and every corner of the State withoud any sort of discrimination, whether this particular constituency was represented by a member from the opposition or a member from the Treasury Bencesh. Anyhow, if there are grievances I would certainly assure the House that I will look into them and try to remove the same.

Further a reference has been made about the purchase of Rest House in moussorie. I fail to understand as to why the Hon. Member has not been able to appreciate the importance of the building. We are just very soon thinking of going in for a House in another Hill station. ie in Kasauli. We are developing Morni Hills. We purchased this house for Rs 3.60 lacs and if we want to sell that house more than s. 5 lacs and if we want to sell that. Members and others can go to hill stations and if we have our property there we can stay there. But instead of paying compliments to the Government the Hon'ble members are criticising for the sake of criticism.

Then another senior member of the opposition stated that he had been a member since 1952. Well it is gratifying to know it. But to say that it is for the first time in 20 years that supplementary estimates are going to be more than the budget estimates, is not correct. Perhaps the Hon. member has not cared to go through the copy of the supplementary estimates supplied to him in which the reasons have been categorically stated, Mr. Speaker, this scheme came from the Govt. of India afer the passing of the Budget. We are getting a lot from the Govt. of india and then we have to add our share also.

It is clearly stated at page 6 of the Supplementary Estimates that- "Half a millions jobs programme was launched in 1973-74 by the Government of India to provide employment to educated unemployed more specially to the technical personnel in various States....."

Again in para 3 under this item, it is stated that-

"Since as already stated above this programme has been introduced during the year 1973-74 no provision could be made therefor in the Budget Estimates of the year. Hence the supplementary demand."

Similar is the case. Mr. Speaker, Sir, with respect to the second demand referred to by my hon friends which is mentioned on page 13 of the supplementary estimates regarding the construction of Indira Gandhi Cancl B.N. Chakaravarty Canal, Western Jamuna Augmentation Cancal and Lining of Hansi Branch. So on page 13 of the supplementary estimates it has been stated-

"The central Government have agreed to advance Rs. 7.48 crores as Special Loan Assistance for the construction of

Indira Gandhi Canal, B.N. Chakravarty Canal and Western Jamuna Augmentation Canal (Phase 1) and Lining of hansi branch during the financial year, 1973-74. against this Rs. 5.50 crores have so far been received and the balance amount of loan assistance is likely t be released by them soon. it is a post budget decision due o which funds could not be provided in the original budget estimates, 1973-74. Hence an additional demand of Rs. 7.48 crores under this head is necessary."

I hope when I have invited Hon' Members attention to this particular portion. the misunderstanding of my friends from the opposition will be removed.

With these words, Sir, I thank you very much.

विकास मंत्री (श्री श्याम चंद): स्पीकर साहब, मै ंहिंदी में ही बोलूंगा क्योंकि आज काफी देहाती जनता बैठी है, जरा हिंदी में बात समझ जाएंगे। मेरे कुछ ओपोजीशन के भाईयो ने हरिजन वैल्फेयर डिपार्टमैंट की चर्चा की। मैं अपने भाईयों को यही बताना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार ने पिछले 20 महीनो में हरिजन वेल्फेयर के लिए कितना काम किया है। स्पीकर साहब, आपको याद होगा, पिछले सैशन में हम यहां पर एक प्रस्ताव लाए थे और उसमें सदन को यह बताया गया था कि जितनी पब्लिक अंउरटेकिन्गज़ हैं, चाहे वह बिजली बोर्ड है, चाहे वह इंडस्ट्री या फाइनैंशियल डिमार्टमैंट है या चाहे वह सैंट्रल को–आप्रेटिव बैंक है । जहां पर आज तक हरिजनो के लिए कोई रिजवेशन नही थी, सरकार ने पहली बार उन भाईयों के लिए रिजर्वेशन की है। वे सब लोग जिन्होने इस बारे में क्रिटिसिज्म किया है, 20 साल

पहले इन कारपोंरेशन्ज़ वगैरा में रिजर्वेशन करते तो शायद उनको पता लगता कि हरिजनो का कितना फायदा होता। लेकिन मैंने स्पीकर साहब, जैसे कि पहले अर्ज किया था, उनकी जुबान ही मोटी नही, उनका दिमाग भी मोटा है। ऐसी जो चीजें हैं हरिजनो के फायदे की वे उनके दिमाग में नही आई। इसके साथ साथ जितने भी टेक्नीकल कालेज हैं प्रोफैशनल कालेज है या मैडिकल कोलज है, आज तक उनमें हरिजन विधार्थियों के लिए दाखिले में कोई रिजर्वेशन नही थी। इस सरकार ने पहली बार यहां जो हरियाणा में तीन विश्वविधालय हैं, पंजाबी युनिवसिटी, हिसार एग्रीकल्चर युनिवसर्टी और कुरुक्षेत्र युनिवसर्टी, से टेक–अप करके हरेक प्रोफैशन में 20 परसैंट शैउयूल्ड कास्टस के लिए और दो परसैंट बैकवर्ड क्लासिज़ के लिए सीटें रिजर्व करवाई है। इसके साथ साथ जब हमारे भाई पावर में होते थे। आज हमने हरेक कालेज मे छः महीने का स्कालरशिप ऐडवांस भेज रखा है ताकि हमारे हरिजन विधार्थियों को आए महीने वजीफा मिले और उनको दूसरे आदमियों के आगे हाथ न पसारने पडे। स्पीकर साहब, आपने अनुमति दी और एक स्टैंडींग कमेटी बनाई गई जिसमें इस विधान सभा के 9 सदस्य हैं। वह कमेटी हरेक साल हरियाणा सरकार को अपनी रिकमैंडेशन देगी कि इस महकमें में यह यह खामी है। सरकार के इस महकमे को हरिजनो की भलाई के लिए इस तरह से काम करना चाहिए। हरियाणा सरकार उनकी जो भी सजैशन्ज होगी, उन पर गौर करके, उन पर पुरी तरह से अम्ल करेगी। स्पीकर साहब, यहां पर उन्होने हरिजन कल्याण निगम का भी कीटीसिज्म किया। सरकार ने हरिजनो की भलाई के लिए कितने अच्छे स्टैपस लिए हैं। यहां पर करनाल फैक्ट्री का जिक आया। स्पीकर

साहब मैं दावे के साथ कहता हूं कि उस फैक्ट्री में इतना बढिया प्रोडक्शन है कि वैसा किसी दूसरे कारखाने में नही है। इसके अलावा हमने यह भी फेसला किया है कि हरियाणा सरकार की जितनी भी खपत होगी, वह उस निगम को करनाल की फैक्ट्री से पुरी की जाएगी। इसके साथ ही साथ सरकार ने यह भी फेसला किया है कि टोहाना में एक आर0 सी0सी0 स्पन पाईप की फैक्ट्री लगाये, कुरुक्षेत्र में कार्ड बोर्ड की फैक्ट्री लगाएं, पानीपत में हैंडलूम की फैक्ट्री लगाए और भिवानी में एक कपडे की मिल लगाए। इस तरीके से हम यह चाहते हैं कि अगले सालो में हर एक डिस्ट्रीक्ट में एक–एक फैक्ट्री लगायें–हरिजनों के लिए हमारे जो बडे बडे शहर हैं, अगले साल उनमें हरिजनो के लिए एक एक फक्ट्री लगाएं ताकि जो गरीब हरिजन भाई अपना काम–धंधा नही कर सकते, वे उन फैक्ट्रीयों में जाकर काम करें। उनको वहां से अच्छी तन्खाह मिले, वे भी अपने बच्चों को पढाएं, साफ सुथरे रहें और वे भी हमारे हरियाणा के निर्माण में उतना ही सहयोग दें जितना कि दूसरे भाई लोग। आज जो समझते है कि मैं तो हरिजनो का लीडर हूं, आज यह तरक्की के काम जैसे हो रहे है अगर इसी स्पीड से काम होते रहे तो हरिजनो की जो आने वाली नस्लें है, वे इनको गालियां देगीं कि अगर ये लोग यह काम 20 साल पहले कर देते तो आज हरिजन की क्या हालत होती। स्पीकर साहब, आज से 20 साल पहले के अर्से में क्या हुआ जिसके बारे में ये छाती तानकर कहते हैं कि मेरे जमाने में यह होता था, मैं यह बताना चाहूगां कि इनके जमाने में क्या हुआ है। एक कस्टोडियन की जमीन हरिजनो को मिली और वह किस तरीके से मिली? वह इस तरीके से कि कुछ हरिजनो ने दिल्ली में आंदोलन

किया। पंजाब एसैम्बली में उसकी चर्चा हुई। जितने भी पंजाब असैम्बली में हरिजन एम0 एल0 ए0 थे, उन्होने एज ए प्रोटैस्ट वाक–आउट किया विधान सभा से।

चौधरी चांद रामः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहब हमारे सामने तीन–चार डिमांडज थी, एक डिमांड हाउसिंग की, एक डिमांड बेरोजगारी की। ये कौन सी डिमांड पर बोल रहे है?

चौधरी चांद रामः मैं चांद राम वाली डिमांड पर बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, ये मिनिस्टर है और जवाब दे रहे हैं। आपने या किसी और ने जो कीटीसिजम किया है, मिनिस्टर उसका जवाब दे रहे है.....(व्यवधान).....

श्री श्याम चंदः स्पीकर साहब, मैं चौधरी चांद राम जी की डिमांड पर बोल रहा हूं। जब वहां पर पंजाब विधान सभा का सैशन था तो सारे हरिजन एम0 एल0 ए0 ने वाक आउट किया कि कस्टोडियन की जमीन हरिजनो को मिलनी चाहिए लेकिन हमारे ये दोस्त वहीं पे बैठे रहे। He was the last man to walk out and that too after half an hour.

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, ये हाउस के रिकार्ड की बात को भी क्या चेलेंज करेंगे?

Shri Shyam Chand: He was the last man to leave the House.

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, ये क्या बात करते हैं? मैंने तो उस वक्त 34 एम0 एल0 ए0 को लीड किया था। ये तो उस वक्त बच्चे थे जब मैने..... (शोर व विघ्न)

13:00 बजे

श्री श्याम चंदः ये तो दूसरे के वजीफे पर पढे है। इन्होने तो दूसरो की जूतियां साफ की है और तब पढे हैं। इन्होने चौधरी छोटू राम की जूतियां साफ की हैं और उनके वजीफे पर पढे है। जबकि हम अपनी मेहनत से हाथ से काम करके पढे हैं। (व्यवधान) यह जमीन अठारह बीस रुपये एकड के हिसाब से सैन्ट्रल गवर्नमैंट ने दी थी और पंजाब सरकार ने यह फेसला किया कि यह जमीन पांच सौ रुपये एकड के हिसाब से हरिजनो के मिले। लेकिन जब यह रेवेन्यू मिनिस्टर बने तो इन्होने फेसला किया कि यह जमीन पांच सौ रुपये के हिसाब से हरिजनो को न दी जाए बल्कि उसका आक्शन किया जाए और जो सब से ज्यादा बोली दे उसको जमीन दी जाएं। स्पीकर साहब, इस तरह से वह जमीन छः और सात हजार रुपए एकड के हिसाब से बिकी और आज हालत यह है कि उस जमीन की इन्सटालैमैंट देना मुश्किल हो रहा है.....

चौधरी चांद रामः आन ए प्वयांट आफ आर्डर, स्पीकर साहब, मेरे उपर जो एलीगेशन लगाऐ जा रहे हैं उनके बारे में मुझे पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन का समय तो मिलेगा न?

श्री अध्यक्षः आप बैठ जाइए। इनको बोलने दिजिए।

गृह मंत्री (श्री के0 एल0 पोसवाल): स्पीकर साहब जब ये बोल रहे थे तो हम बडी शांती से सुन रहे थे और जब हम बोल रहे हैं तो इनको भी शांती से सुनना चाहिए और उसका बाद में जवाब देना चाहिए। कम से कम सुन तो लें।

श्री श्याम चंद: स्पीकर साहब, अगर हरिजन भाईयों को पांच सो रुपए एक एकड के हिसाब से जमीन मिलती तो उनका कितना भला होता। लेकिन यह तो चाहते थे कि अगर जमीन छः सात हजार रुपए एकड के हिसाब से बिकेगी तो हरिजन खरीद नही सकेगें और जब खरीद नही सकेंगे तो वे पिछडे हि रह जाएगें। उनकी आर्थीक उन्नती नही होगी। क्योंकि यह समझते हैं कि अगर उनको पास जमीन हो गई तो उनके पास पैसा हो जाएगा और फिर इनकी चौधराहट खत्म हो जाएगी और उनको दबाकर नही रखा जा सकेगाा। जमीन होने से हरिजन इनके खिलाफ हो जाएंगे। इसके साथ साथ स्पीकर साहब, ये चंदा लेने में भी बडे माहिर हैं और इसीलिए कुछ भाईयों ने इनका नाम चंदाराम रख दिया है।

श्री अध्यक्ष: आप डिमांड पर ही बोलिए।

श्री श्याम चंद: स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि ये चंदा लेने में भी बडे माहिर है (व्यवधान) मैं तेरे से ज्यादा पढा हूं। I can teach you for years together.

चौधरी चांद राम: कौन सा सर्टीफिकेट लिया हुआ है।

श्री श्याम चंदः तेरे की तरह सिफारिश से सर्टिफिकेट लेकर नही पढा हूं। (व्यवधान)

चौधरी प्रताप सिंह दौलताः आन ए प्वयांट आफ आर्डर, स्पीकर साहब, यह हरियाणा विधान सभा है या चमारो की चौपाड है। (व्यवधान–हंसी)

चौधरी चांद रामः यह भी उनकी तारीफ कर रहे हैं। मैं भी इनकी तारीफ कर रा हूं। स्पीकर साहब, मै कह रहा था कि यह चंदा लेने में माहिर हैं। इन्होने रोहतक में रविदास होस्टल बनाया उसके लिए गवर्नमैंट से ग्रांट दी लेकिन उसका आज तक कोई हिसाब नही। उसमें लाखों रुपए का गबन है। कोओपरेटिव सोसायटीज़ बनाने में भी ये माहिर हैं। खरखोदा में इन्होने टेनिंग कोओपरेटिव सोसायटी बनाई उसमें भी 35 हजार रुपए का गबन है और वह रुपया इनकी पॉकेट में गया है।

स्पीकर साहब, वीर–सुनारवाला का जिक्र आया। हो सकता है कि गवर्नमैंट से कुछ गलती हो गई हो लेकिन जब वह समझ गई कि गलती हो गई तो उसके बाद गवर्नमैंट ने उसको क्लेरिफाई कर दिया। इन्होने क्या किया कि उन लोगो को इकट्ठा किया, जाति पाति के नारे लगवाए, गौत्र की बात की, रिश्तेदारी की बात की और अगले दिन क्लाट पैलेस में जाकर उनको हवालात में भिजवा दिया। स्पीकर साहब सन् 1965 में या मिनिस्टर बने तो इन्होने फेसला करवाया कि यह जमीन एक साल के पट्टे पर दी जाए, लेकिन जहां तक अपने भाई

बंधुओं और रिश्तेदारों का सवाल है, इन्होने बीरछुछक में दो भाईयों, दो भतीजों के नाम पक्की अलाटमैंट करवाई। इनके जो फादर इन ला हैं, उनके भाई हैं, राजस्थान में रहते हैं और उनकी वाईफज़ तक के नाम पक्की अलाटमैंट करवाई। इनका हाल तो यह है कि जब फायदे वाली बात हो तो वहां पर रिश्तेदार और जहां कहीं पर नुक्सान वाली बात हो वहां नारा लगा देते हैं कि हरिजनो इकट्ठे हो जाओ। जब ये कांग्रेस में होते थे तो कांग्रेस की तारीफ और जब बाहर आ गए तो उसकी बुराई और कहते हैं कि कांग्रेस तो खराब है। स्पीकर साहब, वीर–सूनारवाला जहां की 150 फेमलीज़ अफैक्टिड हैं 1965 में इन्होने कहा था कि अगर मुझे 1000 रु पर फेमली दे दो तो परमानैंट और अगर नही दोगे तो पट्टे पर जमीन मिलेगी। उन बेचारे हरिजनो के पास एक हजार रुपया नही था तो उनको परमानैंट अलाटमैंट नही हुई। स्पीकर साहब, जो अलाटमैंट पट्टे पर होती है उसमें न तो पट्टे वाले का प्रोप्राईटरी राइट होता है और न टेनैन्सी राइट होता है। और.....

चौधरी चांद रामः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, स्पीकर साहब, पर्सनल ऐलीगेशन के लिए भी रुलज़ हैं। क्या उस वक्त यह हाजिर थे जब मैंने एक हजार रुपया मांगा था। यह बाहर यह इल्जाम लगा कर देखें तो मैं देखुगा। यह तो मिनिस्टर हैं इनको तो रुलज़ का ध्यान होना चाहिए और जब एक मैम्बर रुलज़ की तरफ ध्यान दिलाए तो .....
...

श्री अध्यक्षः आप बैठ जाइए। श्याम चंद जी आप डिमांडज़ पर ही बोलिए। डिमांडज के उपर जो कुछ इन्होने बोला है आप उसका जवाब दिजिए।

श्री श्याम चंदः इस विधान सभा के छः मैम्बरो ने एक इश्तहार निकाला था और मेरे पास जो आदमी आए थे उन्होने भी कहा था कि इन्होने एक हजार रुपया पर फेमली मांगा। उन्होने कहा था कि हम को परमानैंट अलाटमैट इसलिए नही हुई कि हमने एक हजार रुपया नही दिया। यह बात मैं यहां पर भी कहता हूं, बाहर भी कहता हूं और हर जल्से में भी कहता हूं। अगर यह कोर्ट में जाना चाहते हैं तो इनकी छुट्टी है हम कोर्ट में डिफैंड करेंगे। स्पीकर साहब, चाहे पंजाब असैम्बली थी चाहे हरियाणा असैम्बली है जितने दिन कांग्रेस पार्टी में रहे किसी भी पढे लिखे हरिजन को आगे नही आने दिया।

श्री अध्यक्षः समय हो गया है, अगर आप खत्म नही करेंगे तो टाईम और बढाना पडेगा।

श्री श्याम चंदः बस मैं अभी खत्म करता हूं। इस विधान सभा में हमारे एक साथी है, जब चौधरी चांद राम टिकट देने के लिए सात मैम्बरो की कमेटी में थे और जब उनका नाम आया और उनको टिकट देने लगें तो वह वाक आउट कर गए हालाकिं वे पढे लिखें लॉ ग्रजुएट हैं। स्पीकर साहब, जितने भी हरिजन विधायक जो चाहे मैट्रिक भी थे उनको टिकट मिलना था उनके नाम के आगें इन्होने लाल पेंसिल से निशान लगा दिया था। यह तो चाहते थे कि मैं ही हरिजनो का नेता

रहूं, वे अनपढ ही रहे और मैं अंधो में काना राजा बना रहूं। स्पीकर साहब, एक नवम्बर को एक मिटिंग हो रही थीं.....

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब, ये सारी रिकार्ड की चीज है। एक मिनिस्टर को यह शोभा नही देता। It will not go in his favour यह कहां तक ठीक है।? यह तो चौधरी चांद राम के पीछे ही पड गए....

श्री अध्यक्षः आप डिमांडज पर ही बोलिए।

श्री श्याम चंदः मैं कह रहा था कि एक नवम्बर को मिटिंग हो रही थी। पहले तो इन्होने कहा कि यह एजीटेशन नान–पोलीटीकल है। दस मिनट के बाद कहने लगे कि मेरी पार्टी जनसंघ की शुक्रगुजार है, मेरी पार्टी रिपब्लीकन पार्टी की शुक्रगुजार है, स्वतंत्र पार्टी की शुक्रगुजार है जिन्होने हमारी बहुत मदद की। चौधरी दल सिंह जो वहां पर मौजूद थे किसी ने कहा कि इनकी पार्टी का तो नाम ही नही लिया। वहां एक आदमी कहने लगा कि यह तो उनका नाम लेते हैं जो इनको पैसा दे, जो पैसा न दे उनका नाम नही लेते।

चौधरी दल सिंहः मैं तो अब भी कहता हूं कि हम हरिजनो को स्पोर्ट करते हैं। That is a hard fact, You cannot challenge it हरिजनो के सब से पहले हमदर्द हैं।

श्री श्याम चंदः आप हमदर्द है लेकिन जो हरिजनो के चौधरी बने बठै है वे हमदर्द नही है।

श्री अध्यक्षः श्री श्याम चंद जी, टाईम हो गया है।

श्री श्याम चंदः अच्छा जी ठीक है। बाकी दूसरी इनस्टालमैंट के वकत पर कह दूंगा। (हंसी)

बहिर्गमन

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, मेरे पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन है।

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, आप तशरीफ रख्यि। आप बैठिए, मेरी बात सुनिये। पहली बात तो यह है कि आप ने कुछ कागज सदन की मेज पर रखने के लिए कहा था। मैंने एगजामिन कर लिया, मैं उनकी आवश्यकता नही समझता इसलिए इजाजत नही देता कि सदन की मेज पर वह कागज रखे जाएं। दूसरी बात यह है कि आपने अपने भाषण के अंदर बहुत सारी बाते कही है। अब पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन अगर दोनो तरफ से आने लग जाएं तो इसके लिए बहुत समय चाहिए। इसलिए मैं कोई पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन देने की इजाजत नही देता। बात सारी खत्म हो गई।

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, आप तो बडे अच्छे .....

श्री अध्यक्षः नही अब समय बहुत हो चुका है।

चौधरी चांद रामः लेकिन बात यह है कि पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन भी रुलज़ का एक हिस्सा है।

श्री अध्यक्षः आप तो बीच बीच में ऐक्सपलेन करते ही रहे हैं और अब बाकी क्या रह गया है?

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, मैंने किसी के खिलाफ पर्सनल ऐलिगेशन नही लगाए। स्पीच में मैंने कोई पर्सनल ऐलिगेशन नही लगाया कि उसने यह खाया यह रिश्वत है।

श्री अध्यक्षः आप एक सैंकेंड के लिए बैठिए। आपने मुख्य मंत्री तक पर आरोप लगाए हैं। आप अगर रिकार्ड देखना चाहे तो देख सकते हैं।

चौधरी चांद रामः क्या आरोप लगाए है?

श्री अध्यक्षः वह आपको मैं पढ दूंगा लेकिन इन चीजो के अंदर अगर हम जाएं भी तो फिर इधर से पर्सनल ऐक्सपलेनेशन आए, ऐलिगेशन लगे और काउंटर ऐलिगेशन लगें तो फिर तो यह सिलसिला बंद नही होगा। इसलिए मैं वित्त मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वह अपना जवाब दें।

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, आप अगर पर्सनल ऐक्सपलेनेशन का टाईम नही देते है तो इस बारे में आप रुलज़ को तो देख लें।

श्री अध्यक्षः मैंने वित्त मंत्री जी को बोलने के लिए कहा है, आप उनको बोलने दिजिये आप तशरीफ रखिये। वित्त मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

चौधरी चांद रामः.....

श्री अध्यक्षः चौधरी चांद राम, मै अपनी व्यवस्थ दे चुका हूं। आप तशरीफ रखिए।

चौधरी चांद रामः.....

श्री अध्यक्षः आप तशरीफ रखिए। मै अपनी व्यवस्था दे चुका हूं। आप तशरीफ रखिए।

चौधरी चांद रामः.....

श्री अध्यक्षः मित्तल साहब, आप बोलिए।

चौधरी चांद रामः..... (शोर)

श्री अध्यक्षः जो कुछ यह कह रहे हैं यह सारा एक्सपंज कर दो। मेरी इजाजत के बिना जो भी बोलता है वह कोई रिकार्ड न किया जाए।

चौधरी चांद रामः आप न रिकार्ड करें, मेरा अधिकार तो है कि मैं वाक–आउट करता हूं एज़ ए प्रोटैस्ट।

(इस समय चौधरी चांद राम सदन से वाक आउट कर गये)

अनुपूरक अनुदानो की मांगो पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

वित्त मंत्री (श्री राम सरन चंद मित्तल): स्पीकर साहब, चौधरी चांद राम जी ने अपने भाषण में एक ऐसी बात कही जोकि मैंने पिछले

5 साल के अंदर नही सुनी कि हरियाणा बताये तरक्की के बैकवर्ड जा रहा है। अब बैकवर्ड क्या, आप कहीं हिंदोस्तां के अंदर चल जाइए, बैकवर्डनैस की तरफ तो उस समय जाते थे जबकि आया राम और गया राम होते थे इनके राज में। शायद ये भी उस वक्त थे या नही–(हंसी).. ....(विघ्न) गया राम में ये थे, आया राम में नही थें।.....(शोर)

श्री अध्यक्षः मित्तल साहब, आप बोलिए।

श्री राम सरन चंद मित्तलः मेरी अर्ज यही थी कि आप उस टाईम की बैकवर्डनैस और आज की बैकवर्डनैस को देख लिजिए। हिंदूस्तान के किसी कोने में आप आज चले जाइए, पहले पुछते थे कि आप कहां से आए हैं, कहते थे कि हरियाणा से तो वे कहते थे कि आया राम गया राम के मुल्क से। अब आप जाइये बडी इज्जत के साथ कहेगें कि ओहो, हरियाणा तरक्की कर रहा है, चाहे कहीं भी चले जाइए। दूसरी बात इन्होने कही कि साहब सडके ठीक नही है, सडकों की हालत खराब है। मैं उसके मुताल्लिक एक बात अर्ज करुंगा कि हरियाणा के चारो तरफ बहुत प्रदेश हैं, यू0 पी0, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली वगैरह। वहां पर मेरे साथ जब बाहर के लोग ट्रेवल करते हैं, हरियाणा के बाहर निकलें, तो कहते हैं साहब, अब तो दूसरा प्रदेश आ गया है, क्योकि वहां की सडके घटिया है। और हमारी हरियाणा की सडकें सबसे अच्छी हैं। इस वक्त जो सडकें हमारे यहां बन चुकी हैं, उनकी बराबरी कोई नही कर सकता। अब मेन प्वायंट पर आता हूं। चौधरी दल सिंह ने एक बात कही कि पहले बजट बना है, उसके अंदर यह स्कीम नही आई और फिर बजट बनने के बाद आई, यह उस वक्त

सोचना चाहिए था। कुछ प्वायंटस पंडित चिरंजीलाल जी ने बताये लेकिन करीब करीब हरेक डिमांड के अंदर यह लिखा हुआ है कि यह पोस्ट बजट निर्णय है जैसा कि डिमांड नम्बर 24 में पहला पैरा है:—

"As it is a post-budget decision, a sum of Rs. 12 lakhs has been provided through these estimates."

करीब करीब हरेक डिमांड के अंदर यह लिखा हुआ है कि यह रुपया सैंटर से मिला है या यह बाद में डिसीज़न लिया गया है।बजट के वक्त यह सवाल पैदा नही हो सकते थे? इसलिए यह बात उस वक्त बजट में नही आ सकती थी। एक प्वायंट इन्होने रेज़ किया कि औरिजनल बजट में कम रकम थी और अब के इस सप्लीमैंटरी में ज्यादा है। कोई रुल प्रोवाइडिड नही है कि सप्लीमेटी में कम होना चाहिए। जिस आयटम को ये रैफर कर रहे हैं वह आईटम भी बाद का है और उसके अंदर कोई झगडा नही है। अब जो डिमांड के मुताल्लिक चौधरी अमर सिंह जी ने रेस्ट हाएस के बारे में तो बेशक कहा लेकिन बाकी के बारें में कहा कि बहुत अच्छी बातें हैं। कम रुपया है यह अलगा बात है। दरअसल जब से बंगला देश की लडाई हुई है तब से भारत के अंदर हर जगह रुपए की कमी है। हर स्टेट के अंदर ऐसी ही हालत है। बजट का जो सिलसिला है कि जो जरुरी काम होता है या जितना रुपया होता है वह लगा देते हैं आगे के लिए रख लेते हैं। अब हाउसिंग की डिमांड नं0 14 है, हरिजन हाउसिज़ के लिए यह लिखा हुआ है कि हाउस साइट्स और प्रावाइडिड बाई दि डिवैलपमैंट डिपार्टमैंट है। तो इस प्रकार दो हजार रुपए पर हाउस सैंटर की तरफ

से बतौर ग्रांट दिया जा रहा है। बाकी जिसको दिया जा रहा है वह भी अपने पास से लगाएगा, इतने में मकान बन जाएगा। अब यह कहना है कि साहब 600 ही मकान बनते हैं, इस साल 600 मकान बने, आईदा भगवान करेगा ज्यादा अच्छा रुपया मिलेगा। यह तो शुरुआत है। इसी तरह चौधरी अमर सिंह जी ने हास्पीटल के बारे में कहा कि भिवानी में हस्पताल 500 बैड का बन रहा है और हमारे यहां बवानीखेडा में कुछ नही है। हमारा डिसीज़न यह है कि हम सब से पहले डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर एक अच्छा स्टैन्डर्ड देना चाहते हैं। जब रुपया आएगा फिर सब डिविजनल हैड–क्वार्टरज पर आएगे, फिर तहसील पर आएगें फिर मुफसल पर आएगें। यह तो इस तरह से सिलसिला चल रहा है। यह कहना कि अगर भिवानी में 500 बैड का हस्पताल बन रहा है तो हांसी में, बवानीखेडा में भी इसी समय अस्पताल बन जाए, यह मुमकिन नही हो सकता। (विघ्न) यह स्कीम अन–एम्पलायमैंट के कैश प्रोग्राम के बारे में है। इस से एजुकेटिड अन–एम्पलायड रुरल अन–एम्पलायड, हरेक के लिए इस में रुपया अच्छी तरह से प्रोवाईड है बल्कि गवर्नमैंट आफ इंडिया ने यह कहा है–

"Crash programme for Educated unemployed

Rs. 1,75,75,000

'Half a Million Jobs programmes was launched in 1973-74 by the Government of India to provide employment to the educated unemployed more specialy to the technical personnel in various States....'

आप बताईए पांच लाख आदमियों के लिए तमाम इंडिया के अंदर एम्पलायमैंट का एक सिलसिला शुरु हुआ। कितना अच्छा है और हमारे लिए सरकार ने यहां सैक्शन किया है 175,75 लाख रुपया। जिसका मतलब यह है कि एक करोड 75 लाख 73 हजार रुपया। तो यह कहना कि एकदम से सारा अन–एम्पलायमैंट खत्म हो जाए, यह मुम्किन नही है। यह तो शुरुआत है। हरियाणा तो छोटी सी स्टेट है इसमें मेजर प्रोशन सब आ जाएगा। रुरल एरियाज़ अन–एम्पलायड के लिए इस में प्रोवाइडिड है। डिमांड नं0 38 रुरल एरियाज़ अन–एम्पलायड दूर करने के कैश प्रोग्राम के बारे में है। इसके लिए 10 लाख 56 हजार रुपये मांगे गए हैं। मेरा कहने का मतलब यह था, अध्यक्ष महोदय, कि करीब करीब हमें डिवैलपमैंट की इतनी जरुरत होती है, जितनी प्रोवाइड कर सकते थे, वह प्रोवाइडिड है। कोई ऐसा आईटम नही है जिसमें यह कहा जाए कि यह रुपया वेस्ट जा रहा है। बल्कि हरएक चीज पर पैसे को अच्छी तरह सोच समझ कर लगाया जा रहा है। जूई कैनाल इत्यिादि के लिए 7करोड 48 लाख रुपया सैंट्रल असिसटैन्स हम को मिला है। उसमें कुछ रुपया उन्होने दे दिया, कुछ बाद में देगें, वह फिगर्ज़ इसमें आ गई हैं। जहां तक देखा जाए जितना सप्लीमेन्ट्री एस्अीमेटस का जस्टीफिकेशन है वह हर एक आईटम के अंदर हमने उसको पुरी जस्टीफिकेशन दी है। दरअसल उस पर कुछ कहने की जरुरत नही और किटिसाइज़ सिर्फ यहा किया जाए कि साहब, इससे भी ज्यादा रुपया दिया जाए। हरिजनो के मुताल्लिक यह कहा गया कि करनाल के अंदर जो जूते की फैक्ट्री है वह बेकार रहती है। मैंने फिगर्ज़ एसर्टेन की है। हमार पास एशिया का आर्डर आया और

हमने 16840 जूतो के जोडे सप्लाई किए हैं इसके अलावा और भी आर्डर आए। 7200 जोडे जूतो के सप्लाई किए और आगे करने जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूं कि इसमें ज्यादा कहने की बात नही है, हमारी तरफ से पूरा पूरा जवाब पहले ही दे दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपसे अर्ज करुंगा कि इन सप्लीमैंटरी एस्औमेट्स को पास कर दिया जाए।

श्री अध्यक्षः अगर आप सहमत हैं तो डिमांडज अलग अलग पुट करने की बजाए इकट्ठी पुट कर दी जाए?

आवाजें: जी हां कर दी जाएं।

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है कि एक अनुपूरक धन–राशि, जो 1200000 रुपये से अधिक नहो, 26 विविध विभाग के सम्बंध में 31 मार्च 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के कम में आने वाले खर्चो के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो 267260 रुपये से अधिक न हो 35. उधोग के संबंध में 31 मार्च 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष कें भुगतान के कम में आने वाले खर्चो के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो 17575020 रुपये से अधिक न हो 39.विविध सामाजिक तथा विकासात्मक संगठन के संबंध में 31 मार्च

1974 को समाप्त होने वाले वर्ष के भूगतान के कम में आने वाले खर्चो के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो 952750 रुपये से अधिक न हो 50—लोक—निर्माण—कार्य के संबंध में 31 मार्च 1974 को समाप्त हाने वाले वर्ष के भुगतान के कम मे आने वाले खर्चो के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो 123200 रुपये से अधिक न हो 70—वन के संबंध में 31 मार्च 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के कम में आने वाले खर्चो के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो 296870 रुपये से अधिक न हो 71—विविध के संबंध में 31 मार्च 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के कम में आने वाले खर्चो के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो 74800000 रुपये से अधिक न हो 99—सिंचाई नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय (वाणिज्यिक) के सम्बंध में 31 मार्च 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के कम में आने वाले खर्चो के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो 8000000 रुपये से अधिक न हो 103—लोक—निर्माण—कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय के संबंध में 31 मार्च

1974 को समाप्त होने वाले वर्ष के भूगतान के क्रम में आने वाले खर्चो के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो 20 रुपये से अधिक न हो स्थनीय निधियों तथा गैर–सरकारी पाटिर्यो को कर्जे के संबंध में 31 मार्च 1974को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चो के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः सदन कल दिनांक 14 नवम्बर 1973 प्रातः काल 09:30 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।

13:22 बजे

(इस समय सभा कल बुधवार दिनांक 14 नवम्बर, 1973 के प्रातःकाल 09:30 बजे तक के लिए स्थगित हुई)